हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 मार्च, 1979

खण्ड 1, अंक 18

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 28 मार्च, 1979

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एव उत्तर	(18)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(18)23
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(18)24
तारांकित प्र न सं. 1140 पर अपेक्षित सूचना	(18)26
दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 2) बिल, 1979	(18)26
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैन ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1979	(18)55
बैठक का समय बढ़ाना	(18)64
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) बिल, 1979	(18)64
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी	(18)70

स्पीकर्ज सेलरीज एण्ड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1979	
दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979	(18)72
बैठक का समय बढ़ाना	(18)80
दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979 (पुनरारम्भ)	(18)80
अनैक चर (ए)	(18)82

हरियाणा विधान सभा

वुधवार, 28 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,

सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष

(कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैंबर साहिबान, अब सवाल होंगे।

Shortage of Buses in Haryana Roadways

***927. Swami Adityavesh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that inconvenience is being caused to the passengers on account of shortage of buses in the Haryana Roadways; if so, the time by which it is likely to be removed;

(b) whether it is also a fact that the buses which have completed in prescribed period and are in damaged condition are being plied in Gurgaon District; and

(c) if so, the time by which the buses as referred to in part (b) are likely to be replaced?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह औजला):

(क) हां जी, पिछली गर्मियों मे बसों मे कमी के कारण यात्रियों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा लेकिन नई उपलब्ध कर देने पर बन बस सेवा आम तौर पर काफी है।

जैसे कि ऊपर बताया गया है कि बसों की कमी को दूर कर दिया गया है और यात्रियों की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए और बसें उपलब्ध की जा रही है। कुछ 394 नई बसें, इस वित्तीय वर्श के यात्रियों की सुविधा के लिये उपलब्ध कर दी गई है ओर इसके इलावा 115 नई गाड़ियों की मार्च, 1979 तक वृद्धि कर दी जायेगी।

(ख) नहीं जी।

(ग) प्र न ही नही उठता जी।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य संसदीय सचिव से जानना चाहता हूं कि जब हरियाणा मे बसों की कमी नही है तो बसों मे ओवर क्राउडिंग यानी बसें ज्यादा भर कर क्यों चलती है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजला: इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारी बसों मे ओवर क्राउडिंग होती है। वहां पर हम यह

कोि ा ा करते है कि बसों के ज्यादा टाईम लगा दे। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी 115 नई गाड़ियां और आने वाली है। ये अप्रैल के पहले हफते तक आ जायेंगी और इसके अलावा 120 और नई बसें भी अप्रैल के महीने मे आ जायेंगी। इसके बाद मेरा ख्याल है कहीं पर ओवर क्राउडिंग नही रहेगी।

चौधरी हरस्वरूप बूराः मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नै ानल हाईवेज है या औ बड़ी सड़कें है उन पर रिकवरी वैन का अरेंजमैंट है लेकिन जो बसें गांवो मे जाती है, कोई दिन ऐसा नही होगा जब वे खराब न होती हो। तो क्या हर डिपो मे रिकवरी वैन का प्रबंध किया जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः रिकवरी वैन्ज तो सभी डिपुओं मे होती है लेकिन यह बात ठीक है कि रिकवरी वैन्ज ज्यादातर हाईवेज पर ही रहती है और जो गांवो के अंदर बसें जाती है वे अगर खराब हो जाती है तो उनकी इतलाह वर्क ाप मे देर से पहुंचती है क्योंकि गांवो मे टैलीफोन वगैरह का इंतजाम नही है। इसलिये हम कोि ा ा करेंगे कि रिकवरी वैन्ज की संख्या बढ़ाई जाये।

श्री दीप चंद भाटियाः स्पीकर साहब ने जो पुरानी बसों का जिक्र किया इसवक्त हरियाणा मे कोई भी बस ऐसी नही है जो 8 साल से ज्यादा पुरानी हो। हमारी कोि ा ा यही है कि ज्यों ज्यों गांवों के अंदर सड़कें बनती जा रही है हम वहां पर बस सेवा

उपलब्ध करते जाएं। भाटिया साहब के हलके के बारे मे भी पूरा ध्यान रखा जायेगा।

श्री भाम ोर सिंहः जो हरियाणा की बसिज है इनकी छतों पर बे ुमार सवारियां बैठ कर जाती है। क्या इसको रोकने का कोई प्रबंध किया जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः मैं सुरजेवाल जी को बताना चाहूंगा और वे देखते भी होंगे दूसरी स्टेट्स मे जैसे पंजाब है, यू. पी. है और दिल्ली है, वहां पर भाायद हम से भी ज्यादा ओवर क्राडिंग रहती है। हमारी यह कोि ा ा है कि छत पर जो सवारियां बैठती है वे न बैठे और न समस्या को जल्द दूर किया जाये।

डा. बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, अम्बाला और जमना नगर की रोड्ज पर खास तौर पर ज्यादा ओवर क्राउडिंग रहती है और विधायकों के लिये जो सीटे रिजर्व होती है, उनको भी बैठने के लिये जगह नही मिलती। कई बेसिज मे पहली तीन सीटो पर यह भी नही लिखा होता कि ये विधायकों के लिये रिजर्व है। तो क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा इंतजाम करवायेंगे कि वे सीटे हमें खाली मिल जाया करें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः हमारी सभी बेसिज मे पहली तीन सीटों पर लिखा हुआ है कि ये सीटें एम.एल.एज. और एम. पीज. के लिये रिजर्व है। अगर किसी जगह पर यह ि ाकायत हो

कि कंडक्टर उन सीटों से सवारियों को नही उठाता है तो वह हमें लिख कर भेजे, हम कार्यवाही करेंगे।

मास्टर ि ाव प्र ाादः क्या चिफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बतायेंगे कि बसों की हालत इतनी खराब है कि आज भी अम्बाला भाहर से चण्डीगढ़ आते वक्त मैंने नै ानल हाईवे पर तीन बसें खराब पाई और सैंकड़ों लोग सड़क पर खड़े थे। क्या ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि ऐसी बसों की तुरंत रिप्लेसमैंट की जाये ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः आठ साल से पहले किसी बस की छुट्टी नही की जा सकती । हां, यह जरूर हो सकता है कि हम अपने वर्क ााप्स को अच्छा बनाने की कोि ा ा करे जिससे कि बसों के ब्रेक डाउन कम से कम हो। लेकिन अगर हमारी बसों को दूसरी स्टेटस ही बसों के कम्पेयर किया जाये तो खराब बसों की जो परसैंटेज है, यह हरियाणा मे सब से कम है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से यह जानना चाहता हूं कि बसों के खराब होने का सब से बड़ा कारण यह तो नही है कि हरियाणा मे एक बस पर 1.3 आदमियों के नार्म से नियुक्ति होती है जबकि और स्टेट्स मे जैसे महाराश्ट्र है वहां पर 2.6 आदमियों के नार्म से नियुक्ति एक बस पर होती है। तो क्या इस संख्या को बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः इस संख्या को बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नही है। अभी पिछले दिनों जब रोहतक मे

हमारे कर्मचारियों ने धरना दिया था कि उनकी डिमांड यह थी कि इस नार्म को बढ़ा कर 1.4 किया जाये। ऐसा करने से डिपार्टमैंट को लाखों रूपये का नुक्सान होता था। जहां तक महाराश्ट्र में 2.6 का नार्म है, मेरा ख्याल है कि वह नार्म हमारी स्टेट मे नही हो सकता क्योंकि वह बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर नार्म बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो उस पर गौर कर लिया जायेगा लेकिन यह नार्म 2.6 तक नही हो सकेगा।

चौधरी देस राजः कई बार बसें बस स्टाप्स से दूर ठहर जाती है और जो पैसेंजर बस स्टैंड पर खड़े होते है, उनको बड़ी दिक्कत होती है। क्या ड्राइवरों को यह हिदायत की जायेगी कि वे बस स्टैंड पर ही रोकें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः इस किस्म की इंस्ट्रक ान सभी ड्राइवर्ज को दी हुई है लेकिन फिर भी कई जगह वे ऐसी गड़बड़ कर देते है। जब हमें ऐसी ि ाकायत मिलती है तो हम उस ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक ान लेते है।

श्री मांगे राम गुप्ताः हरियाणा रोड़वेज की कई बसों मे स्टैपनी नही होती। जब कभी बस के पहिये मे पंक्चर हो जाता है तो बसें रास्ते मे खड़ी रहती है और सवारियां परे ाान होती है तो क्या सभी बसों मे स्टैपनी का इंतजाम किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः स्पेयर व्हील तो हर बस मे प्रावाइड किया होता है । लेकिन जो स्पेयर टायर होता है वह

रिंट्रेडिड होता है और वह अगले पहिये का काम नही दे सकता। अगर पिछले पहिये मे पंक्चर हो जाये तो उसे वहां रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिये हम अगले टायर तो नये रखते है और जो पिछले टायर होते है वे रि–ट्रेडिड होते है। यह देखा गया है कि टायर नया होने के कारण अगला टायर बहुत कम पंक्चर होता है।

श्री अध्यक्षः इस सवाल पर सप्लीमेंटरी पूछने वाले बहुत साहेबान है, इसलिये मैं गुजारि ा करूंगा कि क्वै चन छोटा और टू दि प्वायंट रखा जाये।

श्री लहरी सिंह मेहराः मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब को बताना चाहता हूं कि जितनी पुरानी बसें है वे सब कुरूक्षेत्र डिपो मे लगा रखी है और वहां से जितनी भी बसें गांवो मे जाती है वे हर रोज खराब खड़ी रहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः मेरे दोस्त को यह भ्रम है कि खराब बसें कुरूक्षेत्र मे चलाई जाती है ।

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़ियाः मैं मुख्य संसदीय सचिव जी को यह बताना चाहती हूं कि कई गांवो से स्कूल चार चार मील की दूरी पर पर है और स्कूल जाने वाले बच्चे तथा दूसरी सवारियां बसों पर चढ़ने के लिये सड़कों पर खड़े रहते है लेकिन कंडक्टर उनको बसों पर नही चढ़ने के लिये सड़कों पर खड़े रहते है लेकिन कंडक्ळर उनको बसों पर नही चढ़ाते । तो क्या ऐसी

इंस्ट्रक ांज जारी की जायेगी कि सभी बच्चों को बस पर चढ़ाया जाये ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): यह जो सवाल किया गया हे, यह बिल्कुल समझ मे आने वाला सवाल हैं इस बारे मे मैंबर साहेबान को भी ध्यान चाहिये। इसके बारे मे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो बड़े रूट्स होते है वहां बसें अमूमन इसलिये नही ठहरतीं कि लम्बे रूट पर जाने वाली सवारियां के टाईम की बचत होती है। जो लोग रास्ते मे तीन तीन और चार चार घंटे खड़े रहते है उनके लिये यह फैसला किया गया है कि लम्बे रूट के बीच लोकल बसें चलाई जायें। ऐसे रूटस पर जहां भी मैं जाता हूं तो लोकल बसें चलाने का आर्डर देता हूं। अगर इस तरह की कोई और इतलाह हमें किसी एम.एल.ए. से मिलेगी तो हम 30–40 मील के टुकड़े के बीच मे लोकर बस चला देंगे। ड्राइवर्ज को तो सवारियों को लेने के लिये इंस्ट्रक ान है लेकिन सब से बड़ी दिक्कत यही होती है कि लम्बे रूट की सवारियों को टाइम पर पहुंचना होता है, इसलिये ऐसे रूटस पर बीच मे लोकल बसें चलाने का फैसला किया है।

चौधरी संत कंवर: मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हरियाणा रोड़वेज की बसों की बाडीज है, वे प्राईवेट बाड़ी बिल्डर्ज द्वारा बनायी जाती है इनमे से बहुत सी बसों की बाडीज संजय की मारूति फैक्टरी ने बनायी है। क्या इस फैक्टरी ने कोई गारंटी एक साल, तीन साल या चार साल की दी

है कि यदि इस अवधि मे कोई नुकसान होता है तो ये फैक्टरी वाले या प्राईवेट फैक्टरी वाले खराब बसों को ठीक करेंगे ? क्या इस बात पर अमल किया गया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः गारंटी तो उसकी कुछ नही होती परंतु हम इन बसों की पेमैंट करेत वक्त कुछ हिस्सा रख लेते है। अगर किसी बस की बाड़ी खराब बनी है या टूट जाती है तो वह पैसा उनको रिफण्ड नही किया जाता।

कंवर रामपाल सिंहः स्पीकर साहब, जैसे कि मुख्य संसदीय सचिव साहब ने बताया कि 115 बसें मार्च मे और 120 बसें अप्रैल मे लेने जा रहे है, मैं इनसे पूछना चाहता कि इनमे से करनाल डिपो को कितनी बसें मिलेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः मेरे दोस्त को यह भ्रम है कि खराब बसें कुरूक्षेत्र मे चलाई जाती है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य संसदीय सचिव महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या उनके नोटिस मे है कि अम्बाला चण्डीगढ़ रूट पर पास होल्डर्ज के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है ? उनको कंडक्टर्ज रास्ते मे गालियां निकाल कर उतार देते है जबकि वे महीने से भाुरू मे 110 रूप्ये देते है । क्या इस समस्या को दूर करने के लिये इस रूट पर लोकल बसें चलाने की कोई तजवीज सरकार के विचाराधीन है?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः इसके बारे मे तो मुख्य मंत्री जी ने अभी हाउस मे आ वासन दिया है कि राज्य मे छोटे रूटों पर लोकल बसें चलायी जायेंगी।

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, यह ठीक है कि आप स्टूडैंटस को रियायती पास देते है। मैं अम्बाला, रोहतक और कुरूक्षेत्र जिलों की बात जानता हूं। वहां जिस बस मे स्टूडैंट्स बैठे होते है वे और सवारियों को चढ़ने नही नही देते है और इसकी वजह यह है कि स्टूडैंट्स के लिये प्र्याप्त संख मे बसें नही है। क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदय आ वासन देंगे कि जहां स्टूडैंट्स की ज्यादा तादाद हो वहां.....

श्री अध्यक्षः आप आ वासन मत पूछिए आप सवाल पूछिये।

श्री देवेन्द्र भार्माः सी.पी.एस. साहब भी कुरूक्षेत्र जिले के रहने वाले है, क्या वे वहां और ज्यादा बसें चलवायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः जहां तक पब्लिक की दिक्कत का सवाल है हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बसें चलाने की कोि ा ा कर रहे है। कुरूक्षेत्र मे मैं मानता हूं कि स्टूडैंट्स को प्रौब्लम है, इस को लोकल बसों से पूरा किया जायेगा और हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोि ा ा कर रहे है।

श्री गुलजार सिंहः यह जो मुख्य मंत्री जी ने लोकल बसें छोटे रूटों पर चलाने के लिये विचार रखा है, क्या इन पर

मुसाफिरों की तंगी दूर करने के लिये तजुर्बे के तौर पर मिली बसें एक्स सर्विसमैन और बेकार लड़कों को चलाने की इजाजत दी जायेगी ? इससे प्राईवेट बसों को भी फर्क पड़ेगा, वे कम होंगे और इनकी आपस मे होड़ होगी जिससे राज्य को लाभ होगा।

चौधरी देवी लालः जहां तक गांव के लोगो की तकलीफ का सवाल है, सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, इसकी बाबत सोच रही है। जो लिंग रोड्जे राज्य में बनी हुई है और जहां पर बस डिपो नही है वहां हम बसे चलाने के बारे मे सोच रहे है। वे बसें लिंक रोड वाले रूट से बड़ी सड़क पर सवारियों को छोड़ देंगी। आगे बड़ी सड़क पर दूसरी बसों का इंतजाम होता ही है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः इसमे दो राय नही है कि बसों का मसला गम्भीर है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो छोटे रूट है, उन पर ट्रैक्टरों से सवारियां ले आने जाने की इजाजत दी जायेगी ?

चौधरी देवी लालः पोहलू साहब, यह तो पहले ही इजाजत दे रखी है। यह पूछ कर वैस ही आपने समय खराब किया है और बेकार मे मुझे एक क्विंटल का बोढ उठाना पड़ा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः फिर ट्रैक्टर से सवारियां ले जाने पर चालान क्यों किया जाता है। (व्यवधान)

चौधरी राजेन्द्र सिंहः मैं सी.पी.एस. साहब से पूछना चाहता हूं कि जो गवर्नमैंट ने अपने डिपों के अंदर बसों की

बाडीज बनाने का काम भुरू किया है उसमे लाभ हुआ है या हानि, अगर लाभ हुआ है तो कितना, यदि नही तो हानि कितनी हुई है?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बसिज की बाडीज खुद बनाये। लार्ज स्केल पर यह काम अभी भुरू नही किया, दो चार बसों की बाडीज तजुर्बे के तौर पर बनायी है। इसमे अभी लाभ हानि का सवाल ही नही पैदा होता।

श्री हरफूल सिंहः प्राईवेट बाडी बिल्डर्ज से जो बसें बनवाई जाती है, जैसा कि सी.पी.एस. साहब ने बताया कि पेमैंट के वक्त उनका कुछ पैसा रख लिया जाता है ताकि जो बसें खराब हो उनको ठीक करवा लिया जाये। क्या आप बतायेंगे कि अभी तक आपने कितना पैसा बचाया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः इसके लिये अलग से नोटिस दीजिये।

स्वामी आदित्यवे ाः क्या मुख्य संसदीय बतायेंगे कि हरियाणा रोडवेज की बसों मे महिलाओं के लिये कुछ सीटें आरक्षित रखी जायेंगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः इसके बारे मे आगे ध्यान दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज अखबार मे छपा है कि हरियाणा रोडवेज की दो बसें राजस्थान सरकार ने पकड़ ली है। क्या सी.पी.एस. साहब बतायेंगे कि इनके पकड़े जाने की क्या वजह है और इनको छुड़ाने की क्या कोि ा ा की जा रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः यह इस सवाल से कनैक्टिड नही है, लेकिन बसें तो छुड़ा ली ही जायेंगी।

श्री हरफूल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब ठीक नही दिया गया।

श्री अध्यक्षः हरफूल सिंह जी, आप इसके लिये अलग नोटिस दीजिये। आपको यह तो दिया है। आप बैठिये।

Appointements in cooperative Sector

***1140. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state—

(a) whether the fresh appointments in the Cooperative Sector have beenmade through the Employment Exchanges;

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the number of fresh appointments made in Haryana Apex handloom Society, Panipat, grade wise from 1st April 1978 to 31st January, 1979;

(c) if reply to part (a) above be in the negative, the number of pesons appointed direct during the period referred to in part (b) above; and

(d) if direct appointments have made, whether any prior approval of tha State Government had been sought?

सहकारियता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) सहकारी क्षेत्र मे कुछ नियुक्तियां रोजगार कार्यालय से तथा कुछ खुली भर्ती से की गई है।

(बी) तथा (सी) हां जी। 1–4–78 से 31–1–79 तक की अवधि मे जो नई नियुक्तियां हरियाणां हैंडलूम वीकर्ज अपैक्स सरकारी समिति पानीपत मे की गई है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

पद	ग्रेड	कुल नियुक्तियां	रोजगार कार्यालय के माध्यम से	रोजगार कार्यालय अप्राप्य पत्र प्राप्त करने के	
1	2	3	4	5	6

लिपिक / सेल्जमैन	110–4–130 / 5–160 / 5–225	13	4		
स्टोर कीपर / सहायत स्टोर कीपर	–उक्त–	2	–		
सेज्ल मैनेजर	150–10–220	2	–	–	2
हेल्पर	70–2–80–3–95	7	–	–	7
	जोड़	24	4	1	19

(डी) जी नही।

डा. बृज मोहन गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सवाल के पार्ट (डी) के जवाब मे मैंने पूछा था कि जो भर्ती की गई है क्या इनकी एप्रूवल सरकार से ली गई है? इन्होंने जवाब नही मे दिया। क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि यह सरकार से एप्रूवल लेनी जरूरी थी या नही ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि एप्रूवल नही ली गई, इसके बारे मे मैंने कल भी सदन मे बताया

था कि अगर कहीं गल्त तरीके से लगे है तो उन पर सरकार कार्यवाही कर रही है और जो कायदे कानून के अनुसार नही लगे है तो सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्रीमती भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री महोदय ने बताया है कि 19 मे से केवल 4 की नियुक्ति थ्रू एम्पलायमैंट एक्सचैंज हुई है। यह नियुक्तियां कम से कम 50 परसैंट तो एम्पलायमैंट एक्सेचज के थ्रू होनी चाहिए थी यह क्यों नही हुई ?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब तो मंत्री जी दे चुके है कि अगर कोई गल्त तरीके से नियुक्ति हुई है तो सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

चौधरी गया रामः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 50 परसैंट एम्पलायमैंट एक्सचेंज से लिये जाते है तो क्या मंत्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि कि यह जो 50 परसैंट सीधी भर्ती द्वारा लिये जाते है, कया उनमे भी रिजर्वे ान के हिसाब से लिये जाते है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, रिजर्वे ान का पूरा ध्यान रखा जाता है लेकिन जैसे मैंने अभी बताया है कि जहां पर भर्ती प्रौपर नही हुई उसको फिर से ठीक करके बाकायदा नियमानुसार भर्ती की जायेगी?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि रोजगार कार्यालय की स्थापना इसलिये

की गई थी कि राज्य सरकार को हर साल के आंकड़े मिल जायें कि कितने बेरोजगार है और कितनों को रोजगार दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि रोजगार कार्यालय की उपेक्षा करके सीधी भर्ती द्वारा भर्ती करने से वह आंकड़े गड़बड़ा तो नही जायेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने बताया कि रोजगार कार्यालय द्वारा पिछले साल 37 हजार नौजवानो को सर्विस दी गई है। उनमे कुछ ऐसी बात हो सकती है कि कोई क्वालीफाई नही करता हो तो वह रह गया हो। इसके बारे मे हमने हिदायते जारी कर दी है कि अगर कोई गल्त ढंग से रखा गया है तो उसे फौरन हटाया जाये।

चौधरी रिजक रामः अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल कोआप्रेटिव बैंक सोनीपत मे कोई तीन साल से इंट्रब्यूज होते आ रहे है। पहले साल जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी इंटरव्यू लिये और लड़के रखे। दूसरा चेयरमैन आया उसने उनको हटा दिया और दूसरे लड़के रख लिये गये। इसी प्रकार से तीसरे ने किया। क्या उनको इस वजह से तो नही हटाया गया कि उसके बाद वाला चेयरमैन अपने आदमियों को रखना चाहता हो ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नही है। कि उनकी वजह से हटाया गया हो, लेकिन जहां तक पोस्ट भरने का ताल्लुक है उसके बारे मे हमने महकमों को हिदायतें

जारी कर दी है कि वह जल्दी भर्ती करें ताकि सरकार और जनता के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाये और यदि कोई भी लड़का गलत हटाया गया है तो चौधरी साहब हमारे नोटिस मे लाये, सरकार उन्हें जरूर इंसाफ देगी।

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब हरियाणा के सैंट्रल कोआप्रेटिव बैंकों में अधिकतर एम.एल.एज. चेयरमैन थे और उनमे जो क्लर्कों और दूसरी आसामियों की भर्ती की गई थी क्या गल्त बात नही करते जो कायदे कानून के खिलाफ हो।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह तो सवाल सोनीपत कोआप्रेटिव सोसायटी के बारे मे है लेकिन जहां भी हम भर्ती करते है वहां सारे कायदे कानून के मुताबिक सारी बातो को देखा जाता है और इस प्रकार की कोई गल्त बात नही करते जो कायदे कानून के खिलाफ हो।

चौधरी भागमलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 24 आदमी भर्ती किये गये है इनमे से कितने भाड्यूल्ड कास्टस भर्ती किये गये और कितने वैकवर्ड क्लास के भर्ती किये गये है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं जी कोई भर्ती करते है, हरिजनों के पूरे कोटे को ध्यान मे रखते हुए और हरिजनों को जितनी सीटें मिलनी चाहिए, वह दी जाती है और मैं

दावे के साथ कह सकता हूं कि हरिजनों को पूरी नुमांदगी मिली है, जहां हरजनो को एक सीअ मिलनी चाहिए थी, वहां हमने उनको पूरा हक दिया है।

चौधरी उदय सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भर्ती करते वक्त गांवों के लड़कों का ध्यान रखा जायेगा या भाहरों के ही लड़के लगाये जायेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह छांट करके लगाना तो पोसीबल नही है। यह बात नही कि देहात की बैकवर्ड क्लास और हरिजन का पूरा ध्यान न रखा जाता हो। गांवो के हरिजनों के बारे मे ही नही हमारी गवर्नमैंट ने यह फैसला किया है कि गांवों मे रहने वाला कोई भी लड़का हो चाहे थर्ड क्लास मैट्रिक ही क्यों न हो उसे भी सर्विस दी जायेगी।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो भर्ती की गई है उनमे हर जिलेवार कितने कितने बच्चे है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह खद ाा हो गया है कि मुख्य मंत्री जी ने और मैंने अपने इलाके के लोग लगा लिये है, ऐसी बात नही है। इसमे हिसार और सिरसा का एक भी आदमी नही लगाया गया । करनाल और

पानीपत के लगाए गये है। इनमें से एक बहादुरगढ़ का है और एक दिल्ली का भी है।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि 24 आदमियों मे से कितने हरिजन है तो उन्होंने मेरे एक सवाल का जवाब गोल मोल दिया और जहां तक मैं समझता हूं, एक भी हरिजन लड़का नही लगाया गया।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैंने अप्वायंटमैंट के नियम भी बतायें जिनके तहत 24 लड़के लगे, इन मे सिरसा और हिसार का कोई लड़का नही है। इनमे जितने हरिजनों की अप्वायंटमैंट होनी चाहिए, उनकी हुई है और अगर कहीं गलत से हरिजन लड़का कोटे के मुताबिक न लगाया गया होगा तो उस कोटे को सबसे पहले पूरा किया जायेगा और इसके इलावा हमने चिट्ठी लिख दी है अगर कहीं पर गलत अप्वायंटमैंट हुई है तो उस पर उचित कार्यवाही भीघ्र की जाये।

चौधरी पीर चंदः मैंने पूछा है 24 मे से कितने हरिजन लिये है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इसके लिये आप नोटिस दे दे, जरूर जवाब दिया जायेगा।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, असल बात यह है कि हरिजन लड़के लिये ही नही गये.....(व्यवधान)

चौधरी भजन लालः आनरेबल मैंबर ने हरिजनों के बारे मे पूछा है कि कितने हरिजन लगे, हमने इस संबंध मे पूरी हिदायत दे रखी है, सब महकमों को इंस्ट्रक ांज दी हुई है कि जब नियुक्तियां करे तो हरिजन कोटा हर हालत मे पूरा करने की कोि ा ा करे। अगर हरिजन अवेलेबल नही होता (व्यवधान) आप सुनने की कोि ा ा करे। (व्यवधान) अगर कंडी ान पूरी न करने की वजह से या क्वालिफिके ांज पूरी न होने की वजह से हरिजन अवेलेबल नही है तो हम उस पोस्ट को खाली रखते है और फिर से एडवर्टाइज करते है। अगर फिर भी उस क्वालिफिके ांज का हरिजन लड़का न मिले तो फिर जनरल से भरते है ताकि जनता और सरकार के काम मे रूकावट न आये।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया।

श्री अध्यक्षः चौधरी पीर चंद जी, आप त ारफ रखिये, आपका सवाल आ चुका है, इसका जवाब लेने के लिये आप नोटिस दीजिये । (व्यवधान)

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, इसमे सारी की सारी गड़बड़ है, असल बात यह है कि एक भी हरिजन नही लिया गया। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, जिस ढंग से हरिजन मैंबर खड़े होकर सवाल कर रहे है यह मुनासिब नही

है। वे केवल 20 परसैंट हरिजनों को ही रिप्रेजैंट नही करते, 80 परसैंट दूसरे लोग भी है, जिनको वे रिप्रेजैंट करते है, उनका भी कुछ ख्याल रखें, उनका भी नाम ले लिया करे। अगर आप डिफ्रैंट सवाल करते है तो उसका नोटिस दिया जाये, यह जरूरी नही कि उस लिस्ट मे लिखा हो कि कौन हरिजन है, कौन नही है। यह रिवायात आपके इंट्रैस्ट मे नही, मैं आपके इंट्रैस्ट की बात करता हूं। 80 परसैंट लोग और भी है जिनको आप रिप्रेजैंट करते है, उनका भी आपको कुछ ख्याल होना चाहिए।

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया: क्या मंत्री महोदय आंकड़े बताने की कोि ा ा करेंगे कि कितने हरिजन लिये है? (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: मोस्टली लड़के डिस्ट्रिक्ट करनाल, तहसील पानीपत के लगे है, एक बहादुरगढ़ का लगा है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं (व्यवधान)

चौधरी पीर चंद: अगर आपका आर्डर है कि हम न बोले तो हम आगे से नही बोलेंगे। (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: आप खूब बोले, हम आपको रोकते नही है। (व्यवधान)

श्री लहरी सिंह मेहरा: स्पीकर साहब, सवाल तो यह है कि कितने हरिजन लगाए गये है (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान, जहां तक बोलने की बात है, मेरे ख्याल मे आप सब सहमत होंगे कि जो भी मैंबर बोलने के लिये खड़ा होता है और जो कम बोलता है, सब को बोलने को पूरी पूरी अपौर्चूनिटी दी जाती है। जहां तक हरिजनों का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दिल मे हरिजनो के लिये जितनी जगह है, भाायद ही किसी और के दिल मे इतनी हो। जहां तक बीच मे इंट्रप्ट करने की बात है, यह आपको भाभा नही देती। जो मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया, या मंत्री महोदय ने जवाब दिया, इनके बीच मे इंट्र ान करने से कोई ज्यादा प्वायंट नही बनता। आप डिसिप्लन कायम रखे, सप्लीमैंटरी सवाल क्लीयर हों और बेसिक क्व चन से संबंधित हाने चाहिये। अगर सप्लीमैंटरी क्व चन बेसिक क्व चन से संबंधित न भी हो और इसके बावजूद भी मंत्री महोदय जवाब दे सकते है तो मैं पूरी अपौर्चूनिटी देता हूं जवाब देने की, लेकिन अगर सप्लीमैंटरी का जवाब मिनिस्टर साहब के पास नही है और मैंबर जवाब लेने के लिये एक्सरसाइज्उ है तो मैंबर सैप्रेट नोटिस दें, उसका जवाब गवर्नमैंट से मुहैया करके आपको दे दिया जायेगा।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, अपकी मारफत सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो लोग हरिजनों से भी ज्यादा गरीब है, कतई बेकार हे, कया उनका भी कोई वारिस है ?

श्री अध्यक्षः इसका बेसिक क्व चन से कोई संबंध नही है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव सैक्टर मे, बैंकों मे भर्ती की जाती है, हो सकता है इस भर्ती के बारे मे समाज के किसी सैक ान मे रिजैंटमैंट आई हो या न आई हो, यह दूसरी बात है, लेकिन क्या मंत्री महोदय इस बात से छुटकारा पाना चाहते है कि किसी सैक ान मे रिजैंटमैंट न हो ? अगर पाना चाहते है तो क्या अनएम्पलायड यूथ की अप्वांयटमैंट, रिटन टैस्ट लेकर, मैरिट बैसिज पर की जायेगी?

चौधरी भजन लालः अब आप देख ले, एक तरफ दे हांतों की बात करते है और दूसरी तरफ मैरिट की बात करते है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है, मैं भी कहना चाहूंगा कि कोआप्रेटिव सैक्टर मे जितनी भर्ती की है, *एक भी बैंक ऐसा नही है *एक भी जगह ऐसी नही मिलेगी जहां हरिजनों को पूरा कोटा न मिला हो, सब जगह पूरा कोटा दिया है। जहां तक हरियाणा अपैक्स हैंडलूम पानीपत का ताल्लुक है, मेरे पास इसके *आकंड़े नही है। जो जो हरिजन मैंबर आंकड़े लेना चाहे, मैं उनको आंकड़े भिजवा दूंगा। जहां पर कोई कमी है, उसको हर हालत मे तीन महीने के अंदर अंदर पूरा कर दिया जायेगा।

Recruitment of Constables

***1199. Chaudhri Ishwar Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the district wise number of Constanbles requited in the Police in the State during the month of January, 1979 together with the number of males and females out of them sperately;

(b) the district wise number of Harijan constables required in the State and whether the reservation quota for persons belonging to Scheduled Castes has been completed, if not the reasons therefor; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to make direct recruitment of ASIs?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)

(ए) जनवरी, 1979 मे भर्ती किये गये सिपाहियों की जिले वाईज संख्या निम्नलिखित है। किसी भी महिला उम्मीदवार की भर्ती नही किया गयाः–

हिसार	–	भून्य
अम्बाला	–	13
नारनौल	–	1
जींद	–	भून्य
कुरूक्षेत्र	–	भून्य
सोनीपत	–	भून्य

सिरसा — 3

करनाल — 4

भिवानी — भून्य

रोहतक — 12

गुड़गांव — भून्य

(बी) जिले वाईज हरिजन सिपाहियों की भर्ती की संख्या निम्ललिखित हैः—

हिसार — भून्य

अम्बाला — 1

नारनौल — भून्य

जींद — भून्य

कुरूक्षेत्र — भून्य

सोनीपत — भून्य

सिरसा — भून्य

करनाल — 1

भिवानी — भून्य

रोहतक — 2

गुड़गांव — भून्य

अनुसूचित जातियों को उपरोक्त ''ए'' पर भर्ती के अनुसार आरक्षित कोटा पूरा किया गया है।

(सी) हां जी।

चौधरी ई वर सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे बताया कि अम्बाला मे 13 सिपाही भर्ती किये गये है। जिनमे 1 हरिजन है जब कि हिसाब से 2 बनते है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसका क्या कारण है ? संवैधानिक रूप से 13 मे से 2 हरिजन होने चाहिए। इसके अलावा पार्ट (सी) का उत्तर 'हां' मे दिया है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या ए.एस.आईज. की कमी है, अगर कमी है तो कब तक पूरा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः पुलिस के सिपाही को भर्ती डिस्ट्रिक्टवाईज होती है, जितनी वकैंसीज होती है, जब उनको फिल अप करते है तो भाड्यूल्ड कास्ट के कोटे का ख्याल रखा जाता है। एक की कमी थी, उसको भी पूरा कर लिया गया है।

श्री मूल चंद मंगलाः स्पीकरसाहब, गुड़गांव जिले के बारे मे मंत्री महोदय ने दोनो ही कैटेगरीज की इंफर्मे ान भून्य मे दी है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसा क्यो है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः वहां कोई वैकेन्सी नही थी।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, पार्ट (सी) के जवाब मे मंत्री महोदय ने कहा है कि ए.एस.आईज. की डायरेक्टा रिक्रूटमैंट का मामला गवर्नमैंट के विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस डायरैक्ट रिक्रूटमैंट का क्राईटेरिया क्या बनाया जा रहा है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः वैसे तो यह सवाल इससे संबंधित नही है, लेकिन फिर भी मैं आनरेबल मैंबर को यह बताना चाहता हूं कि सुबार्डिनेट सर्विसिज सिलैक ान बोर्ड की तरफ से कुछ क्राईटेरिया सरकार के पास आया है जिसको सरकार ने मंजूर कर लिया है। पहले फिजिकल टैस्ट लिया जायेगा, उसके बाद मे इंटरव्यू होंगे और फिर सिलैक ान होगी।

चौधरी भाकरूल्लाः मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी तीन फरवरी को पुलिस की जो भर्ती हुई है उसमे मुसलमानो के कितने लड़के लिये गये है? (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, 3 फरवरी को हमने 256 नए कांस्टेबल्ज की भर्ती करनी थी। मुहम्मडन्ज के लिये कोई रिजर्वे ान नही है लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री जी ने नूह के इलाके मे एलान किया था कि हम कुछ परसैंटेज मुहम्मडन्ज को भी देंगे। जितना कोटा मुख्य मंत्री जी ने निर्धारित किया था, वह अभी पूरा नही हो पाया है। हम फिर कोि ा ा कर रहे है कि उसको पूरा करे।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, इसमे कोई दो राय नही नही कि कांस्टेबल्ज की जो भर्ती हुई है वह मैरिट पर हुई लेकिन जींद का जहां तक ताल्लुक है, दोनो जगह यह भून्य मे आई है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर इन जातियो से संबंध रखने वाले कैंडिडेटस उपलब्ध थे या नही थे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जींद मे स्पीकर साहब, वैकेंसी ही नही है भर्ती कैसे कर ले?

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, मेरे ख्याल मे इसके बारे मे कुछ सदस्यगण को कंफयूजन है। हमारे यहां पहले डिस्ट्रिक्टवाईज वकैंसीज होती थी और जितीन पोस्टस जहां खाली होती थी उतनी वहां भर्ती कर लिया करते थे। 256 वकैंसीज जब हमने भरने का निर्णय किया तो इस क्राइटेरिया को हमने चेंज किया और पापुले ान के आधार पर भर्ती करने का फैसला किया। अगर हम ऐसा नही करते तो जींद वैसे ही रह जाता और एक भी सिपाही वहां से भर्ती न होता। जनवरी की भरती के बारे मे चौधरी ई वर सिंह ने सवाल किया है, यह भरती उस वक्त की है वेकैंसीज के हिसाब से भर्ती की जाती थी।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, हरिजनों को वैसे भी रिजर्वे ान है, क्वालिफिके ान मे भी रिलैक्से ान है और एज मे भी रिलैक्से ान है। इतनी सहूलियतें होने के बावजूद भी वे

सैटिसफाईड नही है। क्या मंत्री जी इंकम के बेसिज पर रिक्रूटमैंट करने का क्राइटेरिया रखेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः फिलहाल ऐसी कोई तजवीज जेरे गोर नही है।

श्री रघूनाथ गोयलः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग नियमो के अनुसार पूरे न उतरते हो, क्या उनको फिर भी भरती किया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः नियम सब के लिये एक जैसे होते है लेकिन हरिजनो को कुछ रिलैक्से ान दी हुई है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, पुलिस स्टे ानों पर सिपाहियों की तादाद पुराने समय मे मुकर्रर की गई थी। क्या मंत्री जी बतायेगें कि बढ़ी हुई आबादी और क्राइम्ज की संख्या को देखते हुए उनकी तादाद बढ़ाने का कोई विचार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः तादाद बढ़ाने की कोि ा ा कर रहे है। कुछ बढ़ानी हमने भाुरू भी कर दी है। 256 नए सिपाही भरती कर रहे है। 33 ए.एस.आईज. लिये जा रहे है।

चौधरी सरदार खांः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत होम मिनिस्अर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का भाुक्रिया अदा करता हूं इस बात के लिये कि मुस्लिम को रिप्रैजेन्टे ान देने की कोि ा ा की जा रही है लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि

ए.एस.आईज. के जो इंटरव्यू हो चुके है, वे कायम रहेंगे या सबदुबारा होंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह मामला बोर्ड से ताल्लुक रखता है। सुना है कि उन्होंने पुराने इंटरव्यू कैंसल कर दिये है और दूबारा इंटरव्यू ले रहे है।

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि अम्बाला जिला मे 13 कांस्टेबल्ज मे से एक हरिजन कांस्टेबल लिया गया। अगर रिजर्वे ान के हिसाब से यह भरती न हुई हो तो क्या वे संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः वैसे तो यह रिजर्वे ान पूरी है, लेकिन अगर पूरी नही हुई तो जरूर कार्यवाही करेंगे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि 33 ए.एस.आईज. और लिये जा रहे है लेकिन समाचार पत्रों मे यह आया है कि यह जो इंटरव्यू कैंसल किये जा रहे है, इससे, कैंडिडेट्स को बड़ा नुक्सान रहेगा क्योंकि पांच हजार कैंडिडेट्स मे से एक तिहाई कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिये भी जा चुके है, उन्होंने फीस भी तीस रूपये के हिसाब से दी है और किराया भी वे पचास पचास साठ साठ रूपये लगा कर गये है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दूसरी बार जब ऐडवरटाइजमैंट हो तो इन लोगों की फीस यों ही इनटैक्ट रखी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः वैसे तो ये बोर्ड का काम है लेकिन जहां तक हमे इल्म है, उन्हीं कैंडिडेट्स को दुबारा इंटरव्यू पर बुलाया जा रहा है जिनकी आलरेडी ऐप्लीके ांज आई हुई है। अब कुछ फिजिकल टैक्स लेकर वे इंटरव्यू ले रहे है।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं अपने पापुलर मिनिस्अर से यह जानना चाहूंगा कि क्या कहीं गुजरों का भी भरती मे नाम आवेगा ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): हर गुजरो के लिये पूरी कोि ा ा कर रहे है लेकिन वे पे ा न आयें तो दूसरी चीज है। (हंसी)

Surplus Land

***1204. Master Jogi Ram:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the area of surplus land secured during the period from 4th July, 1977 to 4th July, 1978 and from 5th July, 1978 to date,

(b) the area of the said land as referred to in part (a) above which has been distributed and amongst whom;

(c) whether the persons to whom the said land has been distributed have taken possession thereof; and

(d) the area of land which still, remains to be distributed and amontst whom it is proposed to be distributed?

श्री अध्यक्षः इस सवाल के बारे मे *ऐक्सटैं ान मांगी गई है जो कि मैंने दे दी है। इस बारे मे संबंधित मंत्री मे आया पत्र इस प्रकार है–

अ0 स0 पत्रांक 1972 ए–आर (1)–79/15355

प्रीत सिंह मंत्री,

राजस्व विभाग, हरियाणा,

चण्डीगढ़।

दिनांक 27 मार्च, 1979

विशयः– सरपल्स भूमि बारे मास्टर जोगी राम, सदस्य हरियाणा विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित विधान सभा प्र न नम्बर 12041

प्रिय कर्नल राम सिंह जी,

मास्टर जोगी राम, सदस्य हरियाणा विधान सभा द्वारा सरप्लस भूमि बारे मे पूछे गये तारांकित विधान सभा प्र न नम्बर 1204 के उत्तर अभी तैयार नही है, क्योंकि वांच्छित सूचना सभी स्थानीय अधिकारियों से प्रतीक्षित है। यह प्र ान 28 मार्च, 1979 को उत्तर के लिये देय है। अतः मैं अनुगृहीत हूंगा, यदि इस प्र न का उत्तर देने के लिये 15 दिन का समय और देने की कृपा की जाये।

सादर

आपका

ह/–

(प्रीत सिंह)

कर्नल राम सिंह,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।

Jayana Devi Dispensary

***1202. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister of Health be pleased to state—

(a) whether the Jayana Devi Dispensary at Ellenabad (Sirsa) is without a lady doctor for the last one year; if so, the reasons therefor; and

(b) the time by which a lady doctor will to posted at Ellenabad?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा. कमला वर्मा):

(क) जी नही।

(ख) इस औशधालय मे एक महीला डाक्टर के नियुक्ति आदे ा पहले ही जारी हो चुके है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल सच है कि एक साल से वहां कोई लेडी डाक्टर नही है। डाक्टर के आर्डर तो होते है। लेकिन वहां कोई लेडी डाक्टर ज्वायन नही करती। इन्होंने अब यह कहा है कि वहां के लिये डाक्टर की नियुक्ति हो चुकी है लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि लेडी डाक्टर वहां कब तक ज्वायन कर जायेगी ?

श्रीमती डा. कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, 23–3–79 को आर्डर कर दिये गये थे और अब टैलिग्राफिकली वहां के सी.एस. ओ. को कह दिया है कि उसे जल्दी रिलीव करके वहां भेजा जाये।

श्रीमती भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, हमारे कलियाणा मे एक साल से लेडी डाक्टर नही है। क्या मंत्री जी वहां भी लेडी डाक्टर तुरंत भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्षः यह प्र न मेन क्वै चन संबंधित नही है लेकिन अगर मंत्री महोदया जवाब देना चाहें तो दे सकती है।

श्रीमती डा. कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, हर पी.एच.सी. मे तीन डाक्टर्ज की पोस्टस सैंक ांड है। यह जरूरी नही है कि लेडी डाक्टर भी वहां हो। फिर भी हम लोगों की सहूलियत की दृश्टि से एक लेडी डाक्टर वहां लगाते है। मैं मानती हूं कि लेडी डाक्टर्ज कुछ कम है और वे हर जगह ही भेजी जा सकती लेकिन अभी अभी कुछ इंटरव्यू हुए है, उनमे कुछ लेडी डाक्टर्ज आई है। जो जगह खाली है वहां पर उनको नियुक्त कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः डा. साहब आप कुछ पूछना चाहते थे।

डा. बृज मोहन गुप्ताः मैंने तो लेडी डाक्टर्ज के बारे मे पूछना था कि क्या अब भी लेडी डाक्टर्ज की कमी है, उसका जवाब आ गया है।

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र हैड क्वार्टर है लेकिन वहां पर कोई सी.एम.ओ. नही है। इसी तरह से लाडवा के अंदर कोई भी डाक्टर नही है जब कि एक पो.एच.सी. मे तीन डाक्टर होते है। तो मैं मिनिस्टर महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर डाक्टर भेजने का कश्ट करेंगी ?

श्रीमती डा. कमला वर्माः जहां पर सी.एम.ओ. नही है वहां अप्रैल मे अव य चले जायेंगे।

कंवर रामपाल सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदय ने सवाल के (ए) पार्ट का उत्तर जो नही मे दिया है और दूसरे भाग मे बताया है कि 23–3–79 को लेडी डाक्टर के आर्डर हुए है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले सालों मे यानी 23–3–79 से पहले वहां काई लेडी डाक्टर नही थी?

श्रीमती डा. कमला वर्माः डाक्टर श्रीमती इन्दू लता एच. सी.एस. वर्ग दो, जैनादेवी सिविल डिस्पैंसरी ऐलनाबाद मे दिनांक 3–7–78 तक कार्यरत रही है। वर्श 1978 के सामान्य स्थानांतरण मे उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मदीना जिला रोहतक मे बदल दिया गया था। उसके बाद डाक्टर श्रीमती मिलन यादव को 18–8–78 को इस डिस्पेंसरी मे नियुक्त किया गया था। उसने वहां पर 18–8–78 तथा 19–8–78 को कार्य किया फिर वह छुट्टी लेकर चली गई। उसके बाद डाक्टर अ ाोक कुमार 5–1–79 से 19–1–79 तक इस डिस्पेंसरी मे नियुक्त रहे। यह डिस्पेंसरी ऐलनाबाद मे नियुक्त किया गया है लेकिन वह वहां गई नही सो अब 23–3–79 को सख्ती से लिखा गया कि अव य कार्यभार सम्भाले।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, छारा मे प्राइमरी हैल्थ सैंटर है लेकिन वहां पर जो डाक्टर लगा हुआ है वह डीगंल से डेली पैंसेंजर है। इसी तरह से प्राइमरी हैल्थ सैंटर बदली मे कभी भी लेडी रेगुलर नही रही। मेरे पास पचासों चिटिठयां कांस्टीच्यूंसी के लोगों की आई हुई है वह फल्ड इफैक्टिड एरिया है इसलिये क्या मंत्री महोदय वहां दो जगहों पर नये तबादलों मे डाक्टर लगाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती डा. कमला वर्माः मैं माननीय सदस्यो को अ वासन दे चुकी हूं कि जिन पी.एच.सीज. मे लेडी डाक्टर नही है जरूरी नियुक्त करेंगे।

श्रीमती भाकुंतला भगवाड़ियाः क्या मंत्री महोदय बास दुधा, बावल और टाकड़ी जहां एक साल से डाक्टर नही है, वहां भेजने का कश्ट करेंगी ?

श्रीमती डा. कमला वर्माः जहां पर नही है, लगाई जायेंगी।

श्री भले रामः जिन डिस्पेंसरियों मे स्टाफ के लिये मकानात नही है, क्या सरकार वहां पर स्टाफ क्वार्टर बनाने का कश्ट करेंगी ?

श्रीमती डा. कमला वर्माः इसवर्श फर्स्ट प्रायरिटी रेजिडैं ि ायल क्वार्टरज बनाने को दी जायेगी।

Procurement of Wheat, Barley and Grams by Government

***917. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state the district wise quantity of Wheat, Barley, and Grams procured, separately, by the Government during the year 1978-79?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर): सूचना सदन की मेज पर रखी जाती है।

सूची

(क) **गेहूं:**

वर्श 1978–79 मे जिलावार खरीद निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रोक्योरमैंट			
		खाद्य विभाग	हैफड	खाद्य निगम	जोड़
		(आंकड़े टनों में)			
1.	अम्बाला	2977	16509	11348	57634
2.	भिवानी	870	302	82	1254
3.	गुड़गांव	52909	35181	20650	108740
4.	हिसार	39853	21233	18518	79604
5.	जींद	35854	15645	11128	62627
6.	करनाल	114128	37622	41483	193233
7.	कुरूक्षेत्र (कैथल सहित)	150727	79979	33894	164600
8.	नारनौल	4208	4014	1542	9764
9.	रोहतक	12907	7159	6192	26258
10.	सिरसा	41386	20260	18699	80345

11.	सोनीपत	23629	11910	12866	48405
	जोड़	506248	249714	176402	932464

(ख) **जौं तथा चना:**

इन खाद्यान्न की खरीद खाद्यय निगम द्वारा पराईस स्पोर्ट के तहत की जाती है। इस वर्श इन खाद्यान्न की कोई खरीद अभी तक नही ही गई क्योंकि इनकी कीमतें समर्थन मूल्यों से ऊपर रही है।

(कई सदस्यों की ओर से यह कहते हुए भाोर कि उन्हें रिप्लाई की कापियां नही मिली हैं)

Mr. Speaker: I would request to Government to ensure that suficient number of copies of the replies are sent to be put on the Table of the House/Members' benches. (विघ्न) जिन सदस्यों को कापियां न मिलने के कारण दिक्कत हुई है उसके लिये हम रिगरेट करते है, आइंदा से पूरी मिलेंगी।

स्वामी आदित्यवे ा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सूचना दी हे कि जब ज्यादा कीमतें होती है तो कोई चीज नही खरीदते है मैं यही पूछना चाहता हूं कि चले की खरीद सरकार ने कभी नही की, इनका क्या कारण है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः भाायद मेरे साथी इसको समझ नही पायें अगर स्पोर्ट प्राइस से भाव नीचे चला जाये तो गवर्नमैंट खरीदती है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी आप सोचने का प्रयत्न करें कि जब कम प्राईस मिलेगी तभी तो गवर्नमैंट खरीदेगी ज्यादा प्राइस होगी तो क्यों खरीदेंगी ?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि सरकार जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती है, अगर उससे नीचे भाव जायें तो क्या गवर्नमैंट किसानों को सपोर्ट प्राइस देगी ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः जी हां। जब भी सपोर्ट प्राइस से अनाज के भाव नीचे चले जाते है, गवर्नमैंट मार्किट मे चली जाती है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर सपोर्ट प्राइस से भाव नीचे चले जाते है तो गवर्नमैंट खरीद भाुरू कर देती है। पिछले दिनों बाजरें का भाव 85 रूपये मुकर्रर किया था लेकिन 65–70 रूपये के भाव से बिकता रहा। मैं मिनिस्टर साहब जानना चाहता हूं कि बाजरा क्यों नही खरीदा गया ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः जो भी भाव हमने मुकर्रर किये है वह मैं बता देता हूं ।

Mr. Speaker: What is the support price of bajra?

Voices: Rs. 85/- per quantal.

Mr. Speaker: If the hon. Minister does not have the information, he cah ask for a separate notice.

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, इस सवाल का बाजरें के भाव से कोई ताल्लुक नही है। इसके लिये सैपरेट नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जायेगा।

चौधरी हरस्वरूप बूराः इस वक्त गेहूं और जौं की सपोर्ट प्राइस क्या मांग की गई है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः वैसे तो इस सवाल के लिये सैपरेट नोटिस की जरूरत है लेकिन मैं बता देता हूं कि हमने सैंटर से पहले से ज्यादा मांग की है।

चौधरी हुकम सिंहः क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि जब किसान गेहूं लेकर मार्किट मे आता है तो इन्सपैक्टर, जिस क्वालिटी का गेहूं होता है, उसको घटिया क्वालिटी का बता कर कम दामों मे खरीद लेते है ? क्या इंस्पैक्टर की जगह किसी और आदमी पर इस बात को छोड़ने का प्रबंध करेंगे ताकि किसान का गेहूं सही भाव पर खरीदा जा सके ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः हमारे पास जहां से ऐसी कोई ि ाकायत आती है, हम वहां पर या तो अपने सीनियर

अफसर भेजते है या फिर मैं खुद जाता हूं। जब कोई ि ाकायत सही निकलती है तो फौरन कार्यवाही की जाती है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Appex Handloom

81141. Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Minister for Cooperation and Dairy Develompment be pleased to state—

(a) whether any new purchases by the Haryana Apex Handloom Society, Panipat, were made during the period from 1st October, 1978 to 28th February, 1979;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether those purchases have been made though any Purchase Committiee; and

(c) if answer to part (b) above be in the affiremative when and how this Purchases Committee has been formed ?

सहकारिता तथा दु ग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) तथा (ग) इस सोसायटी द्वारा 1—10—78 से 20—1—79 तक यह खरीद इस समिति के प्र ाासक बोर्ड द्वारा 14—2—78 गठित परचेज कमेटी के द्वारा की गई थी। 20—1—79 से 25—2—79 तक कोई परचेज कमेटी नही थी। 26—2—79 से 28—2—79 तक की खरीद इस बोर्ड द्वारा 26—2—79 को अधिकृत प्र ाासकों द्वारा की गई थी।

Rania Drain

***1203. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Rania Drain in district Sirsa; and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां।

(ख) 1979—80 मे यह निम्राण कार्य पूण्र हो जाने की सम्भावना है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Inclusion of Gujjar Community in Backward Classes

276. Chaudhri Lal Singh: Will the Minister of Revenue be pleased to state—

(a) whethe the Gujjar Community is not included in the category of Backward Class in Haryana; and

(b) if so, the Government propose to include the said community in the category of Backward Classes in the State?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(क) हां।

(ख) नहीं।

Cooperative Consumer Stores in Villages

277. Shri Bhagi Ram: Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to open Cooperative Consumer Stores in big villages in the State: and

(b) if so, the time by which they are likely to be opened?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) तथा (ख) सरकार ने यह फैसला किया है कि राज्य मे 5000 से ऊपर की आबादी के गांवों मे , सहकारिता क्षेत्र मे उपभोक्ता वस्तुओं का विवरण 30 अप्रैल, 1979 तक चालू कर दिया जाये।

Ottu Bridge

278. Shri Bhagi Ram: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposalunder consideration of the Government to re-construct of Ottu Bridge on Ghaghar river in sirsa for giving it the shape of a straight bridge; and

(b) if so, the time by shich the bridge as eferred to in part (a) above is likely tobe re-constructed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां जी।

(ख) यह पुल जून, 1980 तक पूरा होने की सम्भावना है।

तारांकित प्र न सं0 1140 पर अपेक्षित सूचना

सहकारिता तथा दुग्ध मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को एक सूचना देना चाहता हूं। यहां पर हाउस

मे कई हरिजन सदस्यों ने अपैक्स बौडीज मे भर्ती के बारे मे यह कहा था कि इनमें हरिजनों को नही लिया गया। मैं उन्हे यह बता देना चाहता हूं कि 24 मे से 4 हरिजन लड़के हमने लिये है। आपको यह भी पता है कि इन अपैक्स बौडीज मे सरकार नियुक्ति नही करती जैसे कि कायदा है कि पांच के बाद एक पोस्ट हरिजनों को आती है, उसके मुताबिक सही भर्ती की गयी है। अगर 24 की बजाये 25 होते तो उनका एक बादमी और आ जाता।

श्री देवेन्द्र भार्मा: कुरूक्षेत्र बैंक मे तो सारे के सारे हरिजन लगा लिये।

चौधरी संत कंवर: कंज्यूमर स्टोर्ज मे, कोआप्रेटिव स्टोर्ज मे सारे के सारे हरिजन लगा लिये गये है (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: माननीय सदस्यों को मैं यह बताना चाहूंगा कि यहां पर नियुक्तियां सरकार नही करती, बल्कि इनकी समितियां बनी हुई है, वे करती है। जहां कुरूक्षेत्र बैंक का ताल्लुक है, जिसका जिक्र यहां पर अभी किया गया, वहां पर एक दो हरिजन ज्यादा लगाये गये है। और वह भी इसलिये ज्यादा लगाये गये है क्योंकि पिछली कमी को पूरा करना था जिसको पूरा किया गया है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जो सिलैक ान कमेटी है, उसमे हमने ऐडी ानल रजिस्ट्रार चौधरी ि ाव लाल को

भी रखा हुआ था, ताकि किसी हरिजन के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती न हो जाये क्योंकि चौधरी भिाव लाल हरिजन है।

Mr. Speaker: I must congratulate the Hon. Minister and the Department for providing answer answer at such a short notice. It is a very good show. मैं मैंबर साहेबान से भी दरख्वास्त करूंगा कि वे भी इतने सैंटीमेंटल न हो जाया करे। जो भी उनका सवाल होगा, उसका मैं जवाब अपनी तरफ से भी देने की पूरी कोि ा ा करूंगा और गवर्नमैंट भी कोि ा ा करेगी कि आपको सही जवाब मिले।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मेरे काल अटैं ान मो ान का क्या बना?

Mr. Speaker: It is unde examination. It was reveived ony this morning. Please wait. (Interruptions) It come to me this moring. Let me examine it.

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1979

Mr. Speaker: Now the Hon. Finance Minister will introudce the Haryana Appropraition (No. 2) Bill, 1979.

वित्त मंत्री (श्री मूल चंद जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 2) बिल, 1979 पे ा रिता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 2) बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 2) बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़): आदरणीय स्पीकर साहब, फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने जो एप्रोप्रिए ान बिल सदन के सामने रखा है, मैं इसके बारे मे कुछ कहना चाहूंगा। स्पीकर साहब, नयी सरकार बनने के फौरन बाद हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यह एलान किया था कि भ्रश्टाचार बंद हो ओर आदरणीय मुख्य मंत्री जी भ्रश्टाचार को रोकना चाहते है। लेकिन स्पीकर साहब, आज हरियाणा के अंदर जितने भी तरक्कीयात के काम चल रहे है, इसमे भाक नही है कि काफी तेजी से चल रहे है लेकिन भ्रश्टाचार उनमे पहले से दो कदम आगे चल रहा है। तरक्की के जो काम है, वे तो अर्थमैटिक रे ाो से चलते है यानी एक, दो, तीन, चार, पांच के हिसाब से और भश्टाचार 8–16–32–64 की रफतार से चल रहा है। हमको याद है मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति भ्रश्टाचार की ि ाकायत करेगा, हम उसको कुछ पैसे भी देंगे। मैं इनकी इस बात की सराहना करता हूं कि लेकिन उन्हे यह बताना चाहता हूं कि आज भी भ्रश्टाचार बंद नही हुआ है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। स्पीकर साहब, यहां कल ही बताया

कि बैरियर्ज पर बड़ा भारी भ्रश्टाचार के बारे मे ि ाकायत की थी। भ्रश्टाचार के बारे मे हमारे इसी हाउस के एक आनरेबल मैंबर भी फतेह चंद विज ने अभी कल ही बताया कि बैरियर्ज पर बड़ा भारी भ्रश्टाचारहै। बैरियर्ज पर से जो भी ट्रक गुजरता है, उनको कुछ न कुछ देकर गुजरता है। अगर कोई ट्रक वाला नही देता, तो वे उसे मजदूर करते है कि ट्रक खाली करे, चाहे वे आपके एक्साईज एण्ड टैक्से ान डिपार्टमैंट वाले है, चाहे पुलिस डिपार्टमैंट वाले आदमी है, सारे ही इस काम मे लगे हुए है। स्पीकर साहब, आज हरेक मंत्री या मुख्य मंत्री महोदय अपने सीने पर हाथ रखकर यह नही कह सकता कि पी.डब्ल्यू.डी., कैनाल्ज बिल्डिंग एण्ड रोड़ज डिपार्टमैंट्स मे जहां पर काम ठेकेदारो द्वारा करवाया जाता है, वहां पर कमी ान नही बंधी हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसे सब ठेके के कामों मे 10 प्रति ात कमी ान बंधी हुई है। आपने जो यह भ्रश्टाचार को बंद करने का एलान कर रखा है कि आप भ्रश्टाचार को बंद करेंगे, आप इसे बंद नही कर सकते। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): आप बतायें, इसको रोकने का इलाज क्या है ?

राव दलीप सिंहः आप यह काम बजाये ठेकेदारो से कराने के, डिपार्टमैंट से करवाओ। इसी तरह से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक्साईज एण्ड टैक्से ान के जितने भी इंस्पैकटर्ज हे, उनकी सबकी दुकानदारों के साथ मंथली बांधी हुई

होगी। जिन गांव मे भाराब के ठेके नही है, वहां पर वे भाराब बेचते है। वह तभी बेच सकते है यदि वे मंथली देते है नही तो नही। मैं यह कहना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ मंडी के व्यापारियों का एक इ ि तहार मेरे पास है।.....

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं अपने मोआजिज दोस्त मे अर्ज कंरूगा कि वे मुझे यह ताये कि पी.डब्ल्यू.डी. मे जो कमी ान चलता है, इस बात की जानकारी उन्हे कैसे है ताकि उचित कार्यवाही की जाये। उन्होंने यह कहा कि 10 प्रति ात कमी ान है। कया उन्होंने खूद कोई काम किया था और उस समय उन्होनं 10 प्रति ात कमी ान दिया था या उनके किसी दोस्त ने कोई काम किया ळे जिन के थ्रू उनको यह बात पता लगी है ? यह हमें बताया जाये। हमने तो स्टाफ नया भर्ती किया नही। यह तो पिछले 30 साल से भर्ती किया हुआ है। 30 साल पहले किसने भर्ती किया है, यह भी आप सब को अच्छी तरह से पता है।.....(व्यवधान व भाोर)

राव दलीप सिंह: मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि वे 10 प्रति ात कमी ान तो एज ए रूल आफ ला ले रहे है.....

Mr. Speaker: I won't agree, it is a rule of law.

Rao Dalip Singh: It is a matter of fact and they claim it as a matter of right.

श्री देवेन्द्र भार्माः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरी रिक्वैस्ट यही हे कि हम चाहे कोई भी प्रोफै ान ले ले, ठेकेदार ले ले, कर्ल्कस ले ले, मास्टर ले लें, या कोई भी दूसरी प्रोफै ान ले ले, ईमानदारी बिल्कुल खत्म नही हुई हैं अग भी कुछ ईमानदार आदमी मौजूद है जो ठैके दारी करते है। इसलिये मन्थली देने वाली बात कोई भाोभा नही देती, इसको वापिस लिया जाये।

Mr. Speaker: Well, it is his opinion. He is entitled to say what he feels.

राव दलीप सिंहः आदरणीय स्पीकर साहब, व्यापारी व्यापर मण्डल, मण्डी महेन्द्रगढ़ ने अपने इस पैम्फलेट मे यह लिखा है कि सरकार कर्मचारी उन्हें मजबूर करते है कि हम उन्हें मजबूर करते है कि हम उन्हे मासिक दे। यह बात हर दुकानदार जानता है कि अगर वह मंथली नही देगा तो उसे नाजायज तरीके से तंग किया जायेगा। यह जो भ्रश्टाचार बंद करने की बात हमारे आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां पर कही हुई है और जिसका यहां पर दावा भी किया जाता है, मैं यह कहता हूं कि खाली कह देने से या नारा लगा देने से काम नही चल सकता। इनमे ने ान की करैक्टर बिल्डिंग करने के लिये भी कुछ किया जाना चाहिए। हमारे बजट मे एजुके ान के लिये 55 करोड़ रूपया रखा गया है कि इतना पैसा एजुके ान पर खर्च किया जायेगा।

लेकिन इस सारी एजुके ान मे कहीं ऐसा दिखाई नही देता कि कैसे स्टूडैंटस को करैक्टर बिल्डिंग की ि ाक्षा देंगे ?

इस किस्म की बात ने ान के करैक्टर को ऊंचा नही कर सकती। जब आप इंडिविजुअल का करैक्टर ऊंचा नही करेंगे तब तक ने ान का करैक्टर ऊंचा नही होगा। आदरणीय स्पीकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कौंसिल आफ मिनिस्टर के खर्चे के लिये पचास लाख की डिमांड की है। उनकी तनखाहों के के लिये 3 लाख 56 हजार और कारों की मैंटीनेंस के लिये 19 लाख रूप्या मांगा गया है और मैंटीनेंस आफ रेजोडेंसिज के लिये 8 लाख रूपया मांगा गया है। इसका मतलब यह है कि कोठियों और कारों को मैंटीनेंस के लिये 27 लाख रूप्या मांगा है और तनख्वाह के लिये 3 लाख 65 हजार। एक तरफ तो पिछले दिनों यह एलान किया गया है कि मिनिस्टर अब इम्पोरटिड कार का इस्तेमाल नही करेंगे और बड़ी कोठियों को छोड़कर मिनिस्टर छोटे घरों मे चले जायेंगे लेकिन दूसरी तरफ इतने पैसे की डिमांड से और कार बदलने से कुछ फर्क पड़ता है या नही या पहले जितना ही खर्चा किया जायेगा। अगर पहले जितना ही खर्च करना है तो फिर इनको छोड़ने की क्या जरूरत है ?

स्पीकर साहब, 1977–78 मे पब्लिक सर्विस कमी ान पर 12 लाख रूप्या खर्च किया गया लेकिन इस साल 18 लाख 29 हजार रूप्या पब्लिक सर्विस कमी ान के लिये रखा है। एस.एस. एस. बोर्ड पर 1977–78 मे 6 लाख रूप्या खर्च किया और इस

साल 10 लाख रूप्या खर्च करने जा रहे है। स्पीकर साहब, इस बोर्ड के काम का हाल यह है कि ए.एस.आईज. का हरियाणा भवन मे सिलैक ान होना था। हजारो लड़के सिफारि ों लेकर घूमते रहे। उन्होंने कोई एम.एल.ए. नही छोड़ा और न कोई मिनिस्टर छोड़ा। वे बेचारे घर छोड़ कर सिफारि ाों के चक्कर मे धूमते रहे। कितना उनका खर्चा हुआ होगा। लेनिक आखिर मे वह सिलेक ान केसिंल कर दिया। कितनी ज्यादती उन लड़कों के साथ की गई है। पहले ही ठाक प्रोग्राम क्यों नही बनाया गया ? गवर्नमैंट को कंसल्ट क्यों नही किया गया ? उन लड़कों मे बहुत से लड़के तो गरीब घरारो के होंगे। वे चार पांच दिन तक घर से बाहर सिफारि ाों के चक्कर मे घूमते रहे और आखिर मे इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। इससे बड़ी इन एफीसिएंसी बोर्ड की और क्या हो सकती है। पांच छः महीने हुए एस.एस.एस. बोर्ड ने इरीगे ान डिपार्टमैंट मे कुछ पोस्टों की सिलैक ान की थी। उसको भी पांच छः महीने हो गए है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस सलैक ान का क्या हुआ ? अब किस बात की इंतजार है? इन बातों से जनता मे बड़ा अंसतोश है और पता लगता है कि भ्रश्टाचार बढ़ रहा है।

श्री अध्यक्षः राव साहब, अब आप खत्म करें।

राव दलीप सिंहः बस जी, मैं थोड़ी देर और बोलूंगा। इंफरमे ान और पब्लिसिटी पर 1977–78 मे 61 लाख रूप्या खर्च किया और अब 1 करोड़ 69 हजार रूप्या खर्च करने जा रहे है । यानी 40 लाख रूप्या खर्च कर रहे है ताकि यह डिपार्टमैंट वजीरों

के ढोल बजाता रहे। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से रूप्या बर्बाद करना जनता के साथ बड़ा भारी अन्याय है। सौंग्य एंड ड्रामा सर्विसिज पर 10 लाख रूप्या खर्च करने जा रहे है। फिल्मज पर 11 लाख रूप्या और एडवरटाईजिंग एंड विजुयुलाइज पब्लिसिटी पर 9 लाख रूप्या 1979–80 मे खर्च करने जा रहे है। जनता की जो तकलीफें है या लोगो को रोजगार देना है, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नही हैं लेकिन इन्होंने 1979–80 मे 40 लाख रूप्या पब्लिसिटी पर बढ़ा दिया है। स्पीकर साहब, यह नाजायज बढ़ाया गया है।

स्पीकर साहब, अब मैं होम के बारे मे कहना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रे ान आफ जस्टिस मे जो लोगल एडवाइजर्ज एंड कौंसिल्ज है उन पर 1977–78 मे 23 लाख की रा ि ा खर्च की गई थी और 1979–80 मे 36 लाख रूप्ये की रा ि ा बढ़ा दी। स्पीकर साहब, 23 से 36 लाख रा ि ा कर दी है यानी कि 13 लाख की रा ि ा बढ़ा दी। स्पीकर साहब, एक बात देखकर मुझे हैरानी और दुख हुआ कि लीगल एड टू दि पुअर अंडर दि लीगल एड टू दि पुअर (रूल्ज) जंजाब, 1959 के तहत केवल 5 हजार 5 सौ रूप्या रखा गया है। यह सरकार गरीब आदमियों के मुकदमेबाजी मे जो मदद देना चाहती है उसके लिये सिर्फ 5 हजार 5 सौ रूप्या रखा गया है। वैसे यह सरकार गरीबो की सरकार होने का दावा करती है और उनकी मुकदमेंबाजी मे मदद के लिये केवल 5 हजार 500 रूप्या रख रही है (व्यवधान) । स्पीकर साहब,

इस सरकार ने इम्पूवमैंट आफ साइंस ऐजूके ान के लिये सिर्फ 1 लाख 69 हजार रूप्या रखा है ंसपीकर साहब, आज सांइस का जमाना है। ऐजूके ान का 55 करोड, का बजट हे और सांईस की प्रोमो ान के लियै 1 लाख 69 हजार रूप्या रखा है ंआज लोग चांद पर जा रहे हैं हमे साइंस की तरक्की के लिये अधिक से अधिक कदम उठाने चाहिए। स्पीकर साहब, सैंटिंग आफ टैक्सटस बुक का सैल कायम करने के लिये इतना थोडख रूप्या रखा है जब कि किताबों पर विद्यार्थियों का जीवन निर्भर करता हैं मोती लाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल के लिये 31 लाख रूप्या रखा है और कमला नेहरू स्कूल के लिये 9 लाख रूप्या रखा है। दोनो को मिलाकर 40 लाख बनता है। स्पीकर साहब, इतना रूप्या सिलेक्टिड विद्यार्थियों पर र्ख किया जा रहा हे और देहात मे जहां कि गरीब बच्चे रहते है, जिनके पास पहनने के लिये अच्छे कपड़े नही होते, पैर मे जूता नही होता, उन देहात के स्कूलो के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन उन स्कूलों पर 40 लाख रूप्या खर्च किया जा रहा है। बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन इन स्कूलों पर 40 लाख रूप्या खर्च किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः राव साहब, आपको पंद्रह मिनिट हो गये है। अब आप खत्म करें।

राव दलीप सिंहः स्पीकर साहब, द्वारका दास लाईब्रेरी के लिये कुछ रा ि ा खर्च की जा रही है। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि बताएं कि यह लाईब्रेरी कहां पर है ? स्पीकर

साहब, एम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज के लिये 40 लाख रूप्या खर्च किया जा रहा है। एम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज की हालत तो यहे है कि लोग चार चार, पांच पांच साल से वहां पर रजिस्टर्ड है लेकिन उनको कोई इंटरव्यू तक नही आता है। जिसको भी लेना हेाता है, सिफारि ा के आधार पर ले लिया जाता है। ऐसा करने से लोगो के अंदर भारी परे ाानी है। या तो आप इन ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज को खत्म कर दें या यहां से ही लोगों को नौकरी के लिये लिया जाये। बाहर का कोई भी आदमी न लिया जाये। स्पीकर साहब, सरकार ने केन ग्रोअर्ज को दो करोड़ की सबसिडी दी लेकिन हमारे इलाके मे जहां पर कि बाजरा पैदा होता है उसमे चेपा लग जाता है और फसल को नुक्सान होता है। उनको भी सरकार की तरफ से सबसिडी देनी चाहिए। स्पीकर साहब, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर वाकई सरकार किसानों की मदद करना चाहती है तो सब किसानों को सबसिडी देनी चाहिए। यह नही होना चाहिए कि केवल केन ग्रोअर्ज को सबसिडी दी जाये। हमाराइलाका तो पिछड़ा हुआ भी है वहां पर तो अव य ही सबसिडी देनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। फारैस्ट के ऊपर भी सरकार ने कुछ खर्च करने का विचार बनाया है। हरियाणा मे महेन्द्रगढ़ जिले के अंदर नील गायें पाली जा रही है और 100—100, 500—500 के झूण्ड मिल कर गरीब किसानो के खेतों मे घुस जाती है, उनके खेतों की बरबादी करती है, जिसके कारण किसानों को काफी मायूसी होती है। जब वे नील गाएं खेतों मे घूस जाती है तो वे वहां से निकलने का

नाम नही लेती। हम तो कहते है कि सरकार इन नील गायों को पालने के लिये कोई ऐसा इलाका ढूंढ लें जहां ये गायें नुकसान न करे। हमारे महेन्द्रगढ़ को इसके लिये सैंटर क्यों बना रखा है ? किसी ऐसे इलाके मे इन को रखा जाये जहां पर किसी किस्म का किसी भी गरीबी किसान को नुकसान न हो।

स्पीकर साहब, अब मैं एक्सपेन्डीचर आन सबसे डाईजड फूड इन बैक्वर्ड एरियाज के संबंध मे कहना चाहता हूं। बैकवर्ड एरियाज मे यह फूड इन बैकवर्ड एरियाज के संबध मे कहना चाहता हूं । बैकवर्ड एरियाज मे यह फूड ग्रोअर्ज को सब सिडी देंगे और इसके लिये दो हजारा रूप्ये की रा ि ा हर जिले के लिये रखी गई है, यह रा ि ा हर जिले के लिये रखी गई है, यह रा ि ा बहुत ही थोड़ी है। एक स्माल स्केल सेविंग की मुहिम भी सरकार की तरफ से चला रखी है लेकिन होता क्या है कि अगर बी.डी.ओ. के पास जाये तो वह कहता हे कि निकालो एक हजार, आपका काम तब होगा। जब तहसीलदार ओर दूसरे अफसरों के पास जाते है तो वे भी कहते है कि जमीन का इंतकाल तब होगा जब आप एक हजारा रूप्या दोंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से ये संविंग करना चाहते है लोगो से हजारो रूप्ये इस तरह ऐंठे जाते है।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, ऐप्रोप्रिए ान बिल पर इस वक्त डिस्क ान हो रही है और यह डिस्क ान बड़ी लिमिटिड है पर मेरे माननीय सदस्य इस तरीक से बोल रहे है

जैसा कि जनरल बजट पर डिस्क ान हो रही हो। मैं रूल 203 को यहां पर पढ़ कर सुना देता हूं उसकी सब क्लाज 4 मे लिखा हुआ है कि–

"The debates on an Appropraition Bill shall be restricted to mattes of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demand for grants were unde conderration." यह रैपीटी ान है और ऐसी बहस की आज्ञा नही देनी चाहिए।

Mr. Speaker: I uphold the point of order of the Finacne Minister. I think the Hon. Member is going in tood much detail of the Bill. He should be very berief and limit himself to the Apprpriation Bill. He may also please try to wind up in two mutes.

राव दलीप सिंहः बस जी, मै एक दो बातें कह कर ही समाप्त करता हूं। मैं स्माल सेविंग स्कीम के बारे मे कहा था कि मुझे बीच मे ही टोक दिया गया । स्पीकर साहब, सरकार इस तरह से लोगों से जो हजारों रूप्या बटोर रही है, इससे भ्रश्टाचार को बढ़ावा मिलता हैं इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने फारेस्ट डिपार्टमैंट की पब्लिसीटी के लिये 40 हजार का खर्चा किया है जबकि पब्लिक रिले ांज विभाग आलरेडी इस काम के लिये काम करता है। इस तरह से सरकार 20 हजार रूप्या हर जिला को पब्लिसिटी के लिये देगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के खर्चो पर रोक लगाई जाये ताकि सरकार की इकनोमी हो

सके। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, न तो मैं बजट पर बोला हूं और न ही डिमांडज पर बोला हूं। आपने मुझे अब बोलने का समय दिया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं (ाोर)

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, मैं तो बिल्कुल ही नही बोला हूं (ाोर)

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान, मैं तो अपनी तरफ से टाईम की फेयर डिस्ट्रीब्यू ान करता हूं, इसिलये मैं माननीय सदसयों से कहूंगा कि टाईम का ध्यान रखते हुए पांच पांच मिनट सभी बोल ले, जेसा कि अभी जैन साहब ने रूल्ज पढ़कर सुनाया है कि पांच पांच मिनट एप्रोप्रिए ान बिल पर बोला जा सकता है, क्योंकि इस संबंध मे बजट पर और डिमांडज पर डिस्क ान हो चुकी है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मेरे बहुत से साभी ऐसे है जो या तो बजट पर बोल चुके हे या डिमांडज पर बोल चुके हैं केवल पांच चार ही सदस्य ऐसेरहते है तो न बजट पर बोले है और न डिमांडज पर बोले है। आप कृपा करके कम से कम उनको तो अव य पांच पांच मिनट का समय बोलने के लिये अव य दे।

श्री अध्यक्ष: वे डिमांडज पर नही तो गवर्नर ऐड्रैस पर अव य बोल चुके होंगे।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, हम ने तो बोलना ही बंद कर लिया है (ाोर) हम तो अब तक बड़े ही लिलिटिड बोले है। (ाोर)

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। पहले बजट पर जनरल डिस्क ान और डिमांडज पर काफी चर्चा हो चुकी है, उन पर में नही बोला इसलिये अब एप्रोप्रिए ान बिल पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसी पर बोलते हुए मैं थोड़ा बहुत आपके द्वारा यहां सदन मे कहना चाहता हूं, वैसे ज्यादा बातें कहने की जरूरत भी नही है, जैसा कि आपने अभी फरमाया कि एप्रोप्रिए ान बिल ओर बजट पर काफी चर्चा हो चुकीहै और मुख्य मंत्री व अन्य मंत्रियों की ओर से जवाब भी दिये जा चुके हैं एक दो बाते जो हमारे सामने यहां पर आई है, उनके बारे मे थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहता हूं । जैसा कि अभी हमारे माननीस वित्त मंत्री बाबू मूलचंद जैन जी ने बताया कि मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी कोठी छोड़ दी है और बाकी मंत्री भी छोड़ने जा रहे है बल्कि यहां तक कि मुख्य मंत्री महोदय तो फ्लैट मे ि ाफट भी कर गये है और साथ ही यह भी कहा कि जिन मंत्रियों के पास बड़ी बड़ी कारें थी, वे उनके स्थान पर अब छोटी कारें ले रहे हैं। इस लिये अब यहां इन बातों पर और ज्यादा चर्चा करने की आव यकता नही है। (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य, चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान, पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, मुझे जाति तौर पर

बहुत खु ी है कि इस तरह के पग उठाये जा रहे है जिससे कि इकनामी हो सके। हमारे चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर अपने स्टेटस के मुताबिक चाहे वे बड़ी बड़ी कारों मे चले या बड़ी बड़ी कोठियों मे रहे, हमे इसमे कोई एतराज नही है ब ार्ते कि वे काम ठीक तरह से करते रहें यहां पर तो केवल काम की ही चर्चा है। मेरे ख्याल मे अगर मुख्य मंत्री महोदय छोटी कार मे चलेंगे या गर्मियों के मौसम मे फलैटस मे रहेंगे तो उनकी सेहत मे फर्क पड़ेगा क्योंकि ये दिन रात काम करते है। इनको तो बड़ी कोठी मे ही रहना चाहिए था, अतः मेरा विचार है कि वे अपने इस फैसले को बदले।

चेयरमैन साहब, इसी सिलसिले मे मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी कारें मिनिस्टरों ने छोड़ी है, उनके बारे मे आपने अखबारों मे भी पढ़ा होगी कि जो बड़ी कारें छोड़ी गई है, उनको अब किस प्रकार इस्तेमाल किया जाये। अखबारों मे लिखा है कि इनको या तो गैरिजज मे खड़ा कर दिया जाये या बेच दिया जाये या फिर ट्ररिजम कार्पोरे ान वालो को दे दी जाये ताकि सरकार की आमदनी बढ़ सके।

चेयरमैन साहब, अगर ये कारें गैरिजज मे खड़ी रहेंगे तो इनकी बैटरी फेल हो जायेगी, इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार को सुझाव दूंगा कि जनता पार्टी के 75–76 मैंबर है इस हाउस मे। कुछ मिनिस्टर्ज बन गये, कुछ का कारर्पोरे ांज का चेयरमैन बना दिया और कुछेक बेचारे मैंबर ऐसे है जो किसी वजह से

किसी भी जगह पर अडजस्ट नही हो सके। अगर मुख्य मंत्री महोदय मेरी इस बात को माने तो मेरा सुझाव है कि यह जो कारे है ये सब उन मैंबरों के हवाले कर दी जायें तो हर प्रकार का पक्षपात दूर हो सकता है। चेयरमैन साहब, मुझे बे ाक छोड़ दें पर मेरे भाई गंगाराम जी, जो दिन रात चीफ मिनिस्टर साहब के लिये खून पसीना बहाते है। और दूसरे भाई पोहलू भी है, इनको जो तकलीफ चलने फिरने मे होती है, को दे दे। इस बारे मे हमें किसी को कोई आपत्ति नही होगी। वैसे हमारे मुख्य मंत्री महोदये ऐसे है कि जो हमारे सदस्यों की राय हो, जनता की राय हो, उसको स्वीकार करने मे देर नही लगाते। बहुत जल्दी फैसला लेते है इसलिये उन्होंने कोठियां और कारें छोड़ने का फैसला कर लिया। हो सकता है उनके एडवाईजर इनको यह सलाह दें कि छोटी कारों की बजाये अगर वे रिक ाा पर चलेंगे तो ये उसको भी मान लेंगे। इस तरह से जो सारी कारें बच जाये वे भी एम.एल. एज. को मिल जाये।

चेयरमैन साहब, कोठी के बारे मे जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब महोदय को वह बड़ी कोठी नही छोड़नी चाहिये थी। वे वहां पर आराम से रहते और जो वे दिन राम काम करते है, उनके लिये यह जरूरी भी था कि वहीं आराम करते । इस बारे मे हमें कुछेक बाते भी सुनने मे आई है। एक चर्चा तो यह है कि किसी ज्योतिशि ने कह दिया कि इस कोठी मे नही रहना चाहिए।.....

11.00 बजे

चौधरी देवी लालः मैं ज्योतिश पर भरोसा नही करता।

चौधरी रिजक रामः अगर भरोसा नही करते तो अच्छी बात है। मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि आपके मंत्रिमण्डल मे बहुत राज ज्योतिशि है और वे सारे ग्रह जानते है। उनको पता है कि किस मौके पर मिनिस्टरी टूटनी है और किस मौके पर मंत्री पद मिलना है। तो आप बजाये ज्योतिशियों की बातों मे आने के आप इनसे पूछते रहा करे। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी और चौधरी भजन लाल जी इस मामले मे पूरे माहिर है। इसलिये किसी बाहर के ज्योतिशि तो बाबू मूल चंद भी है लेकिन इनके ज्योतिश का ज्ञान उल्टा है.....

श्री मूल चंद जैनः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैंने पहले भी बताया कि एप्रोप्रिए ान बिल पर ऐसे विचार व्यक्त नही किये जा सकते। अगर ये इंज्वाय करने की बात करना चाहते है तो कोई और मौका ढूंढ ले। एप्रोप्रिए ान बिल के लिये डेढ़ घंटा मकर्रर किया गया था इसलिये मैंबर साहेबान समय का ध्यान रख कर बोलें।

श्री सभापतिः आप अब समाप्त करें।

चौधरी रिजक रामः तो चेयरमैन साहब, मैं आगे कहना चाहता हूं कि अगर ये ज्योतिश के ज्ञान को बुरा मानते है तो मै

कुछ नही कर सकता। बाबू जी मिनिस्टर बने और इन्होंने फाइनैंस का महकमा ले लिया । इनका ज्योतिश उल्टा होने की वजह से इनसे आज किसान भी नाराज है, व्यापारी भी नाराज है और हलवाई भी नाराज है। चौधरी भजन लाल जी को देखे उन्होंने लेबर और कोआप्रे ान का महकमा ले लिया। गन्ने पर सबसिडी दे रहे है और हस्पताल खोल रहे है। अच्छी बात है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बाबू जी का ज्योतिश उल्टा होने की वजह से उनसे आज इस हाउस के मैंबर्ज भी नाराज है और दूसरे लोग भी नाराज है। इसके बाद चेयरमैन साहब, दूसरी बात यह है कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी की जो सी.आई.डी. काम करती है वह मुख्य मंत्री के भी तहते है। मुख्य मंत्री जी को उन पर पूरी तसल्ली नही है। एम.एल.एज. होस्टल मे जो सी.आई.डी. आप्रेट करती है वह पूरी तरह से काम नही करती। सुना है इसी वजह से इपने एडवाईजरों की सलाह पर मुख्य मंत्री जी एम.एल.एज. होस्टल के सामने जा कर बैठ गये है ताकि यह देखा जा सके कि कौन एम.एल.ए. क्या कर रहा है और कौन किधर जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सलाह गलत दी गई है। अगर वे मेरे से सलाह लेते तो मैं तो यह कहता कि दो सैक्टर का ध्यान रखो और जो राजेन्द्र पार्क के सामने क्लब है, वहां जाओं उसका ध्यान रखो।

श्री सभापतिः आपका टाइम हो गया है, अब आप वाइंड अप करें।

चौधरी रिजक रामः चेयरमैन साहब, मैं एक दो बाते कह कर वाइंड अप करूंगा। मुख्य मंत्री जी को सलाह देने के बारे मे मैं कह रहा था। उनकी रिहाय ा के लिये सैक्रेटेरिएट की दसवीं मंजिल ठीक थी ताकि वे आस पास के सारे सैक्टरों की निगरानी रख सके। इसलिये इन्होंने जो अपने एडवाइजर्ज की सलाह ली वह बिल्कुल गलत सलाह दी गई है । इसके इलावा आपने पीछे देखा होगा कि इन्होंने ओम प्रका ा जैसे भारीफ बेटे को तलाक दे दिया। इन्होंने जांच पड़ताल भी नही की कि वह कसूरवार है या नही.....

श्री सभापतिः चौधरी साहब, आप एप्रोप्रिए ान बिल पर ही बोले।

चौधरी रिजक रामः आगर आप चाहते है तो अब मैं एप्रोप्रिए ान बिल पर बोल देता हूं। चेयरमैन साहब, एप्रोप्रिए ान बिल के बारे मे जितना कहा जाये उतना अच्छा है। अभी वित्त मंत्री ने ब्यान दिया कि इस बजट मे 85 प्रति ात पैसा कृशि पर खर्च हो रहा है। मेरे पास मैमोरैंडंस पड़ा है इसमे एग्रीकल्चर पर 29 करोड़ रूप्या दिखाया गया है जिससे एनीमल हसबैंडरी भी है, फारैस्ट भी है और पोलटरी भी है तथा और मल्टी परपज प्राजैक्ट भी भाामिल है। तो इस हिसाब से कृशि पर केवल 12.3 प्रति ात खर्च किया जा रहा है। इसमे भी मल्टी परपज प्रोजैक्टस, इरीगे ान और फल्ड कंट्रोल का 20 करोड़ रूप्या भी भाामिल है। इसके अलावा 44 करोड़ रूप्या बिजली बोर्ड के खर्च कि लिये भी

`ना है। बिजली तो सारी स्टेट मे इस्तेमाल होती है। अगर यह सरा हिसाब लगाये तो 70 प्रति ात पैसा उन्ही प्रोजैक्टस पर खर्च किया जा रहा है जिन पर पहले खर्च होता था। यानी जो खर्च पहले होता था उनमे कोई तबदीली नही की गई है। इसके बाद, एम.आई.टी.सी. का खर्च है, सरकार ने खाल पक्के करने के लिये डेढ़ करोड़ रूप्ये के करीब दिया है, वह खर्च है, सरकार ने खाल पक्के करने के लिये डेढ़ करोड़ रूप्ये के करीब दिया है, वह खर्चा भी इसमे भाामिल है। इसके अलावा जो खाल पक्के करने के लिये खर्च आयेगा वह किसानो से वसूल किया जायेगा इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि खाल पक्के करने का खर्चा डिपार्टमैंट खुद बर्दा ात करें क्योंकि खाल पक्के करने से पानी की बचत होगी और पानी की बचत होने की वजह से सरकार को भी फायदा होगा। इसलिये यह खर्चा किसानो पर न डाला जाये। यह सारा खर्चा भी कृशि की मद मे दिखाया गया है जबकि यह पैसा किसानों से वसूल हो रहा है.....

श्री सभापतिः अब आप खत्म करे और सदस्यों ने भी बोलना है।

चौधरी रिजक रामः इस सिलसिले मे मैं एक बात कह कर खत्म कर दूंगा। चेयरमैन साहब, अबियाने का रेट दो तीन साल पहले हुआ था और अब अबियाने का रेट पहले से अढ़ाई तीन गुना हो गया है। हरियाणा मे अबियाने का कर बहुत ऊंचा कर है इसलिये इसे बढ़ाया नही जाना चाहिए। इसके अलावा

ताबान की भारह इस वक्त बीस गुना है। इस मामले मे महकमें का कोई अफसर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नही है। चाहे वैसे मवे ि ायों के गुजरने से खाल टूट जाये लेकिन किसान को पूरे रकगे का मैक्सीमम रेट पर तवान देना पड़ता है। फिर किसान मे अपनी करने की भाक्ति नही है तो इतनी भारी परे ाानियां लोगो को हो रही है। यह ताबान इन लोगो पर बहुत भारी है इसको 20 गुना से कम कर के दो या अढ़ाई परसैंट कर देना चाहिए। तावान पर और ज्यादा न कहते हुए मैं स्प्रिकलर्स के बारे मे अर्ज करना चाहता हूं.....

श्री सभापतिः आप वाइंड अप कीजिये।

चौधरी रिजक रामः चेयरमैन साहब, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं स्प्रिकंलर्स के लिये 12 लाख रूप्ये की सबसिडी रखी गई है, यह कुछ स्पैसिफाई एरियाज के लिये है। मैं इसमे कुछ ि ाकायत नही करता, कुछ एरियाज है जहां ज्यादा खर्च करना पड़ता है वह करना ही चाहिए लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार स्प्रिंकलर्स पर बड़ा दिल खोल कर खर्च कर रही है परन्तु कुछ ऐसे जरिये है, भाायद आपके नोटिस मे भी हो, वहां छोटी छोटी स्कीमें 3–3 लाख की 2–3 साल से पड़ी है। कभी उनकी फाईल भी खोल कर नही देखी गई है, इतना पक्षपात यह सरकार कर रही है। कुछ इलाकों मे तो सरकार सबसिड दे रही है। और कुछ को नही दे रही है। यह सबसिडी डिवैल्पमैंट के लिये है। मैं आखिरी बात कह कर

खत्म करता हूं, टाईम भी थोड़ा है, बस दो चार मिनट लूंगा। जैसा कि एलान किया गय है कि सरकार डिवैल्पमेंट पर खर्च करेगी परंतु यह बजट जो 227 करोड़ का इतना बड़ा बजट बना है, उसमे आप देखेंगे कि एक दो महकमों को छोड़ कर ऐजुके ान कोआप्रे ान, टूरिज्म आदि महकमे आप ले । कोआपे ान मे 3–4 ज्वायंट रजिस्ट्रार, असिसटेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार है जिन पर करोड़ों रूप्या खर्चे किया जाता है जो जाया जाता है। इस बजट से जो एक्सपैंडीचर इन पर हो रहा है वह बहुत है, करीब 50 करोड़ रूप्ये होगा। फिर भी इस बजट मे और खर्चा बढ़ाया गया है, और भी बहुत सी सहूलियतें दी गई है। इस बात का कल भी मैंबरों ने जिक्र किया था। इस बजट की कापी छपने से पहले मिनिस्टर साहब ने पढ़ी भी नही होगी।

श्री मूल चंद जैनः मैं तो स्वीकार करता हूं कि मैंने पढ़ी है।

चौधरी रिजक रामः लैंड टैक्स के बारे मे भी धोखे मे रखा गया है। चेयरमैन साहब, हलवाईयों पर जो सेल्ज टैक्स लगाया गया हे, उसको खत्म कर दिया जाये। जैसा कि सरकार का वायदा था, सरकार ने एलान भी किया था कि हमारा मैनीफैस्टो है कि सेल्ज टैक्स हम खत्म कर देंगे। चेयरमैन साहब, आपको याद होगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने 21–6–77 को एलान किया था कि सेल्ज टैक्स खत्म करेंगे लेकिन टैक्स बढ़ रहा है, बजाये घटाने के, इसको रिवाईज किया गया है। सेल्ज टैक्स आटे पर भी है, दूसरी चीजों पर भी है जिसका असर आम आदमी पर पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाबू मूल चंद जैन जी इन टैक्सों पर ध्यान देंगे। चेयरमैन साहब, आप देखिये ट्रैक्टर पर टैक्स है जो किसानों पर ही है, इम्पोर्टिड खाद पर 7 प्रति ात, सीड्स पर 4 प्रति ात, कैरोसीन आयल पर 7 प्रति ात। इसी तरह और भी टैक्स है। एक तरफ तो कहते है कि हम किसानों को फायदा देना चाहते है और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ा रहे है, यह दोनों बातें कैसे हो सकती है ? चेयरमैन साहब, बसों का किराया बढ़ा है।.....

श्री सभापतिः आपने कहा था कि अभी खत्म करूंगा, चार मिनट हो गये आप वाइंड अप कीजिये।

चौधरी रिजक रामः चेयरमैन साहब, बसों का किराया बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः चौधरी साहब आपने अभी खुद ही कहा था कि दो मिनट मे वाइंड अप कर रहा हूं.....

चौधरी रिजक रामः बस जी आधा मिनट बाकी रह गया है। अभी खत्म करता हूं। चेयरमैन साहब, जैसा कि चौधरी सुरेन्द्र सिंह ने फरमाया कि डीजल की कीमत बढ़ गई है, इसलिये किराया बढ़ाया है। लेकिन चेयरमैन साहब, आप देखते है कि यह पैंसेंजर टैक्स हम वसूल करते है, आप हैरान होंगे यह सुनकर कि इनको यहां से 60 परसैंट आमदन होती है। इस आमदनी को तो सरकार कहीं दिखाती नही और घाआ दिखाकर टैक्स लगाती है। जहां 1961–62 मे जो 1/6 टैक्स था वह बाद मे 1/5 हुआ और उसके बाद 1/4 हुआ और यह चीज मैमोरेंडम मे भी दी हुई है, वहां आज अगर 100 रूप्ये की आमदन है तो 60 रूप्ये सरकार टैक्स लेती है।

श्री सभापतिः चौधरी साहब आपने अभी खुद ही कहा था कि दो मिनट मे वाइंड अप कर रहा हूं.....

चौधरी रिजक रामः इन्ही भाब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान लेता हूं। (विघ्न)

श्री कंवल सिंह (घिराये): चेयरमैन साहब, काफी बातों पर चौधरी रिजक राम ने लाइट डाली है, मैं भी थोड़ा सा कहना

चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब नक इम्पोर्टिड कारों को मिनिस्टरों द्वारा न इस्तेमाल करने की घोशणा करवाई है, मैं इस बात पर उनको बधाई देता हूं। एक बात जरूर देखने मे आई है कि जिस दिन यह घोशणा हुई, उस दिन सारी कारे गायब हो गई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा फिर आती जा रही है। मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब से बतौर सलाह कह कहना चाहूंगा कि कई वजीरों ने कहा की हमारे पास गाड़ियां नही है, कहां से लाए। मेरी सलाह है। कि आपकी जो अटोनोमस कारपोरे ांज है उनके पास पांच पांच, छः छः, सात सात गाड़ियां, है, उन मे से वे गाड़ियां विदड्रा करके मंत्री साहेबान को दे दें दूसरी बात मैं कोठियों के बारे मे कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, हमारे मुख्य मंत्री साहब ने इस बारे मे बड़ी चुस्ती की है अपनी कोठी छोड़ने के लिये। हम लोगो ने कुछ सुझाव दिये थे, हमारी कहने की नीयत भी यह ीथी कि जो मंत्री अढाई तीन तीन रूप्ये मे प्राईवेट कोठियों किराये पर लेकर रह रहे है, उनको छोड़ दे और जो कोठियां किराये पर लेकर रह रहे है, उनको छोड़ दे और जो कोठियो सैक्टर 7 मे मिनिस्टरों के लिये बनी हुई है, जिन मे वेम लोग रह रहे है जो इन मे रहने के लिये इंटाइटल्ड भी नही है, उनको वहां से निकाल कर ये कोठयां मिनिस्टरों को दे दी जाये। यह बात बड़ी अनुसिचत है कि मिनिस्टर तो प्राईवेट कोठियों मे रहे और वे बंगले जो मिनिस्टरों के लिये बने हुए है, वे खाली पड़े रहे । हमारा सुझाव तो यही था कि जिन कोठियों मे मंत्री महोदय तीन तीन हजार रूप्या किराया देकर रह रहे हे, उनको छोड़ दे

और सैक्टर 7 वाली कोठियों मे आ जाये। चेयरमैन साहब, यह हमारी स्टेट के लिये भाोभा नही देता कि हमारे मुख्य मंत्री जी कोठी को छोड़ करके फलैटस मे आए। अगर चीफ मिनिस्टर साहब की कोठी के किराए का हिसाब लगाया जाये तो सरकारी रेट के हिसाब से दो फलनैटस का किराया ज्यादा हो जाता है और दूसरे चीफ मिनिस्टर सहाब की सिक्योंरिटी का सवाल भी होता है। इन्हे गवर्नमैंट के कइ कामो मे सिक्रेटी रखनी पड़ती हे, फलैटस मे वह नही रह पाती। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इस डिसिजन को कम से कम रिवाईज करे और हमारे जो पहले सुझाव थे उसके पीछे जो भावना थी उसकी वे कद्र करे। हम किसी मंत्री को उसके स्टेटस से नीचे नही गिराना चाहते । हम नही चाहते कि हमारे मुख्य मंत्री जी कोठी को छोड़ करके फलैट मे आये।। चेयरमैन साहब, बड़े दुख की बात हे कि एक सदस्य भापथ्हा लेने से पहले एक कोठी मे रहते थे और उस कोठी का किराया भी एक हजार रूप्या था लेकिन जिस दिन से उन्होने मंत्री पर की भापथ ली हे, उस कोठी का किराया दो हजारा रूप्ये कर दिया गया। क्या हमारी स्टेट के पास पैसा फालतु है कि नाजायज किराया बढ़ाया जाये ?

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य को यह पता नही कि उस कोठी का नीचे का पोर ान मेरे पास था लेकिन अब मैंने सारी कोठी ले ली है। इसलियें ली है जैस कि चेयरमैन साहब, आप जानते है कि

वजीर बनने केक बाद मेरे पास कितनी पब्लिक आती है। यदि उस कोठी को अब दोबारा नए सिरे से लिया जाये तो वह चार हजार रूप्ये मे भी मिलनी मुि कल है।

चौधरी लाल सिंहः चेयरमैन साहब, यह हाउस के टाईम को जाया करने वाली बात है और यह तो ईमानदार मिनिस्टर साहब को परे ाान करने वाली बात है। इन्होंने मुख्य मंत्री जी को एम.एल.एज. के साथ फलैटस मे बैठा दिया । इनको भी बैठा दो तो स्टेटा का क्या बनेगा ?

श्रीमी भाांति देवीः चेयरमैन साहब, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वह किसी व्यक्ति वि ोश पर किसी प्रकार का लांछन लगाने का प्रयास न करे और हाउस को सामूहिक रू से अपनी सलाह दें

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, इनको एप्रोप्रिए ान बिल पर ही बोलना चाहिए ताकि सब सदस्यों को टाईम मिल जाये।

श्री सभापतिः मैं मैंबर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे एप्रोप्रिए ान बिल पर ही बोले।

श्री कंवल सिंहः अगर गवर्नमैंट मंत्री को पैलेस देना चाहे तो इस पर एतराज करने की बात नही होगी। मेर मतलब किसी के ऊपर परसनल अटैक करने का नही। मैंने तो एक उदाहरण दिया है, अगर गवर्नमैंट कोई पैलेस मंत्री को देना चाहे

तो दे। इसमे एतराज करने की कोई बात नही होगी लेकिन जो गल्त बात है उनको हम हाउस के सामने रखेंगे। उसको हाउस के सामने रखने का हमारा फज्र बनता है। चेयरमैन साहब, इसके बाद एस.टी.डी. का जिक्र किया गया है। आज के ट्रिब्यून मे एस.टी.डी. फैसिलिटीज के फेवर मे एक आरगूमैंट आई थी और उसमे यह कहा गया ाि कि जो हमारे आफिसर्ज साहेबान है, उनके ऊपर तो लिमिट हे लेकिन मिनिस्टर्ज पर कोई लिमिट नही है, जो टैलीफोन का मिसयूज कर सकते है। चेयरमैन साहब, एस.टी.डी. फैसिलिटी बंद करने के लिये सुझाव तो इसलिये दिये थे कि इसका मिसयूज न हो। इसके मिसयूज बंद करने के लिये सुझाव तो इसलिये दिये थे कि इसका मिसयूज न हो। इसके मिसयुज के चांसिज ज्यादा है। एस.टी.डी. कहीं की जाये तो उसका कहीं रिकार्ड नही होता। वैसे जो टैलीफोन बिल आते है यह तकरीबन कए बुक ट्रांस्फर हैं अगर एस.टी.डी. फैसिलिटिज न हो और बुक करके काल की जाये तो उसका रिकार्ड होता है और उससे मालूम हो जायेगा कि कौन सी काल कौन सी जगह से की गई है। अगर कोई नाजायज काल करेगा तो रिकार्ड देख कर पकड़ा जायेगां पैसा बचाने की इसमे कोई खास बात नही है लेकिन अगर नाजायज काल कही होती है तो वह बंद हो जायेगी।

चेयरमैन साहब, अब मैं सेल टैक्स के बारे मे जिक्र करना चाहता हूं। हमने पहले भी सुझाव दिया था आयरन एण्ड स्टील पर पहले फस्ट स्टेज पर सेल्ज टैक्स होता था जोकि कांग्रेस गवर्नमैंट ने

जाते जाते उसको लास्ट स्टेज पर कर दिया था जिससे स्टेट को एक करोड़ रूपये का घाटा हुआ। मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस चीज पर गौर करके उस सेज्ल टैक्स को उसी स्टेज पर लाकर हाउस से पास करवाये जो टैक्स अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी पर है उसको रिवाईज किया जाएगा। हमारे फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने हमारे सुझावों के मुताबिक किसानों को राहत दी है लेकिन जो टैक्स लगाए हैं, मैं समझता हूं वह उनकी क्षमता से बाहर हैं। टैक्स उन पर लगाए जाएं जिनकी टैक्स देने की क्षमता है ताकि प्रदेश का रैवेन्यू बढ़े और हम अपने प्रदेश का डिवैल्पमैंट का कार्य कर सकें। चेयरमैन साहब, एक चीज मेरे सामने कल ही आई थी और मैंने उसको एक काल अटैन्शन मोशन के जरिए हाउस में रेज करना चाहात लेकिन किसी कारणवश वह एक्सैप्ट नहीं हो सकी। रोहतक मैडीकल कालेज में बहुत धांधलेबाजी हो रही है। कुछ लोग स्ट्राईक पर गए थे। हमारी सरकार ने उस मामले को ज्यादा देर उलझाया न रखने के लिए उस स्ट्राईक को बन्द करवाया और स्ट्राईक करने वालों को 92 दिन की पे दी जो 3 लाख रूपए के करीब बनती है। पेमेंट इसलिये की कि वह स्ट्राईक कर सकते थे, उनमें कफद युनिटी थी। उसके मुकाबले में जिन लोगों ने 3 महीने तक सेवा की, दफतर में काम किया उन लोगों को वी.सी. ने और जो हामरी गवर्निंग बाडी की एक सब कमेटी बनी थी, जिसमें मेजर जनरल दरियाव सिंह, श्री मुखत्यार सिंह एम.पी. और श्री मनोहर लाल सैनी, एम.पी. शामिल थे, उसने रिकमैन्ड किया था कि जो डाक्टर्ज

स्ट्राईक में शामिल नहीं हुए थे और जिन्होंने स्ट्राईक के दौरान काम किया था, जो गवर्नमैंट के लायल वर्कज रहे थे उनको दो एडवांस इन्क्रीमैंट दी जाएं। एक डा. हजारी लाल है जिसकी वी.सी. ने 1974 से परमोशन रिकमैन्ड कर रखी थी। उस सब–कमेटी ने रिकमन्डेशन की थी कि उस डाक्टर को परमोशन दी जाए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसी महीने को 12 तारीख को गवर्निंग बाडी की मीटिंग हुई और उसी कमेटी ने इस मामले को डैफर कर दिया। जो लोग गवर्नमैंट के इतने लायल रहे हैं, जिन्होंने इतना काम किया है उनको तो कोई ईनाम नहीं दिया जा रहा है ओर जिन्होंने स्ट्राईक की, उन लोगों को ईनाम दिए गए हैं। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि उस गवर्निंग बाडी पर अपना इन्फल्यूएंस डाल करके उन लोगों को भी राहत दें और उनके जो जायज हक हैं वे उनको दे। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

डा. बृज मोहन गुप्ता: आनरेबल मैम्बर यह जो स्ट्राईक की बात कर रहे हैं उस वक्त वह कालेज सरकार के अन्दर नहीं था और जो सरकार के लायल रहे हैं वे वी.सी. के अगेस्ट रहे हैं। सरकार कार इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री कंवल सिंह: डिप्टी स्पीकर सहाब, हमने जनता की सेवा की जबकि इन लोगों ने उन मरीजों को मारा। डिप्टी स्पीकर साहब, ड्रिप लगे हुए थे, उनको निकाला। डाक्टरों को मर्हम पट्टी करते हुए हटाया गया है और जानबूझ कर मरीजों की हत्या की गई है और ये कह रहे हैं कि वह सेवा करते हैं .....(शोर) तो

डिप्टी स्पीकर साहब, उसी कालेज के अन्दर पिछले दिनों एक रेड हुआ था जिस के अन्दर यह पा गया कि जो बलड सीरा था वह एक्सपायरड डेट का था। यह सारे सदन को अच्छी तरह से पता है कि एक्सपायर होने के बाद कोर्ठ भी ड्रग हो, एक तो उसकी पोटैन्सी कम हो जाती है ओर दूसरे वह रीएक्शन कर सकती है। इस बिना पर पुलिस के केस रजिस्टर्ड हुआ लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े दुख की बात है कि डी.पी. जोकि जिले का सबसे बड़ अधिकारी होता है, उसने होम मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया कि इस मामले को किस तरीके से दबा दिया जाए और वह इसलिए कि डी.सी. रेडक्रास का चेयरमैन होता है। इसके अलावा एक और रेड हुआ जिसमें 1000 रूपये की दवाईयां सैन्ट्रल कोआप्रेटिव स्टारे की उसी मैडोकल कालेज में मिसिंग मिली उसके ऊपर भी अभी कुछ नहीं हो रहा। तीसरी बात यह है कि एक बीएरर के घर में 30 बैड शीटस मिलीं। डिप्टी स्पीकर सहाब, मैं यह अपना फर्ज समझता हूं कि ये तीनों बातें हाउस के सामने लाऊ। इसके अलावा एग्रो–इंडस्ट्री के बारे में भी सीरीयस बात है जो कि अभी सरकर के जेरे–गौर है। मैं समझता हूं सरकार इन पर गौर करे। जहां पर इररैगूलैरिटी ओर करप्शन हुई हैं, वहां पर कोई जबरदस्त कदम उठा करके कोई न कोई उपाय निकालें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, अगर एप्रोप्रिएशन बिल पर पूरे तौर पर बोलू तो शायद एक महीने में भी डिस्कशन खत्म न हो, इसलिए मैं दो तीन सुजेशन आपके सामने रखना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, ला एंड आर्डर की हालत हरियाणा में बड़ी खराब है। जो अच्छा काम करने वाले पुलिस आफिसर हैं उनको प्रमोशन दी जानी चाहिए लेनिक जिनका रिकार्ड खराब है, जिन्होंने नाजायज तोर पर जायदादें बना रखी हैं, उनको सर्विस से रिटायर करके उनसे जूनियर आफिसर्ज को प्रमोट किया जाए ओर उनकी जगह छोटे मुलाजम सिपाही वगैरा भर्ती किए जाएं ताकि हरियाणा में ला एंड आर्डर की स्थिति सम्भल सके। डिप्टी स्पीकर साहब, पुलिस वालों को 6 परसैन्ट क्वार्टर दिए जाते है। मैं आपको सुजैशन देना चाहता हूं कि 6 परसैन्ट की बजाये 100 परसैन्ट फैमिली क्वाढ्र पुलिस वालों को दिए जाने चाहिएं ताकि वे अपने बचों के साथ आराम से रह सकें और पब्लिक की सेवा कर सके। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने आनरेबल दोसत सरदार लछमन सिंह, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ रहे हैं, इनसे कहूंगा कि अगर ठेकेदारी सिस्टम हो तोड़ कर, ज्यादा से ज्यादा काम डिपार्टमैंट के थ्रू करवाया जाए तो हरियाणा की डिवैल्पमैंट ज्यादा हो सकतमी हैं। ठेकेदारी सिस्टम बन्द होना चाहिए, इस सिस्टम के तहत हर काम के ज्यादा एस्टीमेटस बनते हैं ओर बहुत ज्यादा हेराफेरी होती है। मैं सरकार को अच्छी राय देना चाहता हूं कि सारे काम ज्यादातर डिपार्टमैंट अपने थ्रू करवाये, ठेके पर न दिए जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा इरीगेशन के बारे में कहना चाहूंगा। ब्यास–रावी का पानी जब मिलेगा तब देखा जाएगा, लेकिन जो मौजूदा पानी है उसका बटवारा सही ढंग से किया जाए। रोहतक और सिरसा जिलों को बहुत सी जमीन प्यासी पड़ी हुई है, 5 परसैन्ट पानी भी नहीं मिलता 95 परसैन्ट जमीन पानी के बिना प्यासी पड़ी हुई है। मेरी सरकार को नेक राय है कि खर्चा घटाकर बचत की जाये और उससे पानी पैदा करके किसानों को दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहूंगा। पिछले सैशन में एक गलत एक्ट पास हो गया था जिसके मुताबिक एक–एक लाख रूपयो बड़े–बड़े कारखानेदारों को, सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स दाखिल करने के लिए कर्जे के रूप में दिया गया। इस बिल को दोबारा हाउस में लाया जाए और इस गलत फैसिलिटी को खत्म किया जाए। इस प्रकार बड़े बड़े कारखानेदारों को पैसा न दिया जाए। जिस प्रकार सरकार ने जमीन पर सीलिंग लगाई हुई है उसी प्राकर इन कारखानेदारों पर भी सीलिंग लगाई जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप रैपीटीशन न करे।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। हरियाणा के किसी देहात में औरतों को लेटरीन का इन्तजाम नहीं है, इससे औरतों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मरेा सरकार को एक सुझाव है कि इस बजट में गांवों में औरतों के लिए लेटरीन बनाने के

लिए पैसे का प्रोवीजन रखा जाए। मुख्यमंत्री साहब, गांवों में जाते हैं, उन्हें पता है कि औरतों को लेटरीन की कितनी भारी दिक्कत है। इसके इलावा मैं सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि बूढ़ों को पैन्शन दी जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे सी.एम. साहब बड़ी हिम्मत करके मुख्यमंत्री बने हैं, हमें इनसे बड़ी उम्मीद थी कि इनके आने से जनता का भला होगा, लेकिन इस सरकार ने गरीब जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि इसके दूसरी तरफ सरमायेदारों के लिए काम कर रही है.....

चौ. लाल सिंह: आन ए प्वायंट आफर आर्डर। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पिछले आंकड़े निकलवा कर देख लें, पता लग जाएगा कि किस मुख्यमंत्री ने गरीबों की ज्यादा मदद की है। (व्यवधान)

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान और गरीब जनता की भलाई के लिए जो बजट बनना चाहिए वह नहीं बना। इस बजट में खुले दिल से खुंदक निकाली गई है और जान बूझकर किसान की चार कैटैगरीज बना दी गई हैं। एक क्लास सवा 6 एकड़ जमीन रखने वाली, दूसयरी 10 एकड़ वाली, तीसरी 12 एकड़ और चौथी 16 एकड़ वाली। इसके इलावा सरकार ने 18 एकड़ की सीलिंग भी लगा रखी है। जब लोगों के पास बहुत कम जमीन रह गई है तो बड़े जमीदारों का नाम कहां रहा? सब जमीदार बड़े किसान से छोटे किसान बन गये हैं, इसलिये लैड टैक्स किसान पर से खत्म किया जाए। मैं फाईनैन्स

मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इस टैक्स को खत्म किया जाए। लेकिनकल फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर देहातों पर पैसा खर्च होता तो उन पर टैक्स भी लगेगा, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी इन्टैन्शन है कि किसानों पर टैक्स लगाया जाए, हालांकि इस टैक्स का बोझ छोटे किसान बरदाश्त नहीं कर सकते। मैं इस बजट की मुखालफत करता हूं और किसानों पर जो टैक्स लगाया गया है, इस पर जैन साहब को रिजाईन करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः आपका टाईम हो गया है, आप बैठ जाईए।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: एक मिनट में खत्म करता हूं। इसके इलावा किसान को उसकी प्रोडयूस का पूरा भाव दिया जाए। किसानों की बहबूदी के लिए जमीन की डिवैल्पमेंट के लिए जो रूपया रखा गया है वह बहुत कम रखा है बजट में किसानों को उचित भाव देने के लिए कोई मद नहीं रखी गई। मै। सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर किसान को ठीक भाव नहीं मिलेगा तो किसानों का भला होने वाला नहीं। मैं आनरेबल मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि किसानों की जिन्स का भाव बढ़ाया जाए वरना किसान का भला होने वाला नहीं। हमें अफसोस है कि हरियाणा में किसान की भलाई का थोथा नारा लगाया जाता है, लेकिन सही मायनों में कुछ नहीं किया जाता।

श्री देवेन्द्र शर्मा (थानेसर): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो तीन बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन पोहलू साहब को आलोचना करने का मौका दे दिया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आलोचना का मौका इस वजह से मिला कि हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट को जो काम करने चाहिए थे, वे नहीं किए। रैवेन्यू डिपार्टमैंट ने फ्लड के दिनों में लोगों की बड़ी सहायता की, ओले पड़े, सरकार ने लोगों की भरपूर सहायता की, लेकिन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट में पब्लिक में इन अच्छे कामों का कोई जिक्र नहीं किया, सोया रहा। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट के काम को स्पीड–अप करने की कृपा करें। मैं दावे के साथ कह सकता कि सरकार ने जो जो काम किए हैं, उनका पता पब्लिक को तो क्या होना था 80 परसैन्ट एम.एल.एज. को भी नहीं है। बेशक आप पूछ सकते हैं और यह कारण है कि पोहलू साहब और दूसरे साहेबान आलोचना कर रहे हैं और यह मौका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट ने ही दिया है। मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट के बारे में छोटी सी बात कहना चाहता हूं। 'तामीरे हरियाणा' मैंगजीन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट से निकलता है, पहले पंजाब से भी निकलता था। इसमें जो कुछ छपता है, वह पजांब की तरक्की के बारे में छपता है, उसका कल्चर क्या है, उसकी डिवैल्पमैंट क्यसा है, वहां के गीत किस प्रकार के हैं, वहां की क्या क्या उपलब्धियां हैं सब कुछ पंजाब के बरे में छपता है लेकिन

'तामीरे हरियाणा' के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। इस पर हजारों रूपया खर्च होता है। क्यों न सरकार इसको बन्द कर देती और इस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाया जाये। इसी तरह से एक रिटायर्ड आफिसर को इसका एडीटर लगा दिया लबकि डिपार्टमेंट में आलरेडी कम्पीटैन्ट और इन्टैलीजैन्ट अफसर बैठे है, इन पर सरकारयकी नही नहीं करती और एक रिटायर्ड आफिसर को उढीटर बना दिया। भाुरू–2 में तो यकीन नहीं होता था लेकिन अब भी कुछ आफिसर ऐसे है जिन पर सरकार यकीन नहीं रिती। अगर सरकार उन पर यकीन करे तो काम बहुत बढ़िया चल सकता है। पुरानी सरकार के समय की गलतफहमियां पैदा हुई है, इसलिये इन पर कान्फिडैन्स नहीं होता और जब तक सरकार को कान्फिउैन्स नीं होगा तब तक काम चल ही नहीं सकता। कल्चरल अफेयर का ढोल पीटना, गीत गाना इससे काम नहीं चलता। मेरा सरकार से नेक राय है कि कल्चरल अफेयर प्रोग्राम को एजुके ान डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया जाये। जहां तक एजुके ान डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है, इसके बारे में मैं एक बात कहना चहता हूं। हमारे बहुत सारे साथी यू0पी0 पैटर्न को हरियाणा में लागू करने की बात करते है। यू0पी0 पैटर्न की कई चीजें बडी वेग और मिसलीडिंग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप यू0पी0 पैटर्न को पढे ंतो आपको मालूम होगा कि सिवायें तनवाह बढाने के और कोई चीज लाभदायक नहीं मिलेगी। आज यू0जी0सी0 के ग्रेड लागू होने से सारे प्रोफेसर काफी ज्यादा पैसा ले रहे है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः समय कम है, आप बैठ जाऐ।

श्री देवेन्द्र भार्माः जिस दिन से चौधरी भजन लाल जी मिनिस्टर बने है तब से मैने बोलना छोड़ दिया है। (व्यवधान) मैं किसी के खिलाफ कोई खास बात नहीं कहूंगा। एजुके ान डिपार्टमेंट में यू0पी0 पैटर्न लागू करने की बात चल रही थी। इसके तहत सिवाये प्रोफैसरों की तनखाह बढाने से और दूसरी बातें लागू नहीं की गई। कहा यह जाता है कि जब इतनी तनख्वाह दी जाएगी। तो प्रोफेसर लोग ट्यू ान नहीं पढायेगें बल्कि पूरा काम करेगें। परन्तु मैं कहता हूं कि प्रोफैसर लोग बडे आराम परस्त हो गये है। वैसे तो मैं प्रोफसर्ज की बडी इज्जत करता हूं। लेकिन यह सच है कि वे स्वयं तो मेहनत कराते नहीं और सारा इलजाम लडकों के उपर लगाते है। मैं कहता हूं कि पढाने वाला जब पढायेगा तभी तो लड़के पढेगें। तो डिप्टी स्पीकर साहब, यहां बडी वेग और मिसलींडिंग स्टेटमेंटस दी जाती है और जब मैं यह बात उन लोगों के मुंह से सुनता हूं जो पहले ऐजुके ान मिनिस्टर रह चुके हों, तो मुझे बडी हैरानी होती है। वे यह नहीं सोचते कि यहां सारे वे आदमी बैठे है जो बाहर लोगों को बडे आराम से बेवकुफ बना लेते है, ये कैसे बेवकूफ बन सकते है। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे बजट में रिफै ार कोर्स की बात की गई। रिफै ार कोर्स का मतलब है कि टीचर्ज को ट्रेनिंग दी जाए लेकिन इसके लिये सिर्फ आठ हजार रूपये रखे गये। आठ

हजार रूपये से क्या हो सकता है? यह पैसा ज्यादा होना चाहिये था।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं अडल्ट ऐजुके ान के बारे में कहना चाहूंगा। हालांकि इसके लिये सैन्टर से पैसा मिलता है लेकिन फिर भी इसके लिये केवल 1 करोड़ 21 लाख रूपया रखा गया है। इससे अडल्ट ऐजुके ान कैसी बढ़ेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, अपग्रेडे ान आफ स्कूल्ज के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हरियाणा में काफी मिडल स्कूल है लेकिन इनमें से सिर्फ 7 स्कूल अपग्रेड किये जायेगें। एक हिसार में है, एक भिवानी में है और एक रोहतक में हैं चार स्कूल पता नहीं कहां अपग्रेड करेगें? अगर केवल सात स्कूलों को हाई स्कूल बनाया जायेगा तो ऐजूके ान को कैसे बढावा मिलेगा हांलाकि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहाथा कि हम ऐजूके ान परइतनी तवज्जह नहीं दे पाये है। जितनी हमें देनी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्षः अब आप वाइंड अप कीजिये।

श्री देवेन्द्र भार्माः उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुरप ान की बात कह देता है। यहां कहा जाता है कि हमने कुरप ान सारी बन्द कर दी है। डिप्टी स्पीकर साहब, हममे से 90 परसैन्ट एम0एल0एज0 ऐसे है जो लड़ भिड़ कर यहां आये है। और मैं दावें से कह सकता हूं कि अगर पिछले एम0एल0एज0 से हमारा मुकाबला किया जाये तो कुरप ान में दो परसैन्ट भी मुकाबला नहीं

हो सकता। हम उनके मुकाबले में बडे ईमानदार है। (विघ्न) चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि आप सारी उम्र अन्याय के खिलाफ लडते रहे हे क्योंकि आप बेसिकली फाईटर है। आपसे लोग बडी तवक्को रखते है और मैं भी उनमें से एक हूं कि आप इस दि ाा में और भी बडे कदम लेगें क्योंकि जितनी कुरप ान हम रोकना चाहते थे उतनी रूक नहीं पाई है। मैं इसके इस्टांसिज भी दे सकता हूं। (विघन) मैं एक डिपार्टमेंट का ही उदाहरण आपको दे देता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी गवर्नमेंट एक लख ईटों के लिये 20 टन कोयला दिया करती थी। उस 20 टन में सवा लाख ईटें बनाई जा सकती हैं लेकन अब गवर्नमेंट ने यह कोटा 25 टन कर दिया है। 5 टन तो यहां बढा दिया। दूसरी तरफ सवा लाख ईटों की जगह अब पौने दो लाख ईटें बनेगी। इसके अलावा पहले उनसे जो ईटें ली जाती थी वह भी लेनी बन्द कर दी गई है। इसका कारण यह बताया जाता है कि 75–80 परसैन्ट ईटें सरकारी कामों में ही इस्तेमाल होती है। डिप्टी स्पीकर साहब, यही नहीं, रेट भी अब इन्होने बढा कर 100 रूपये हजार कर दिया है। (विधन) जैन साहब चूंकि समझ गये है , इसलिये मैं इस बारे में औरज्यादा नहीं कहता।

इसी तरह चावलों की बात है। 100 बोरियों में से 70 बोरियां निकलती हैं इसमें भी कुरप ान होती है। पिछले साल हमारी ऐसी बेइज्जती हुई जिसका कोई हिसाब नहीं है। रि ाया में हमारे चावल गये परन्तु वे खराब निकले। डिप्टी स्पीकर साहब,

वैसे तो होता यह है कि बासमती को जितना देर रखो उतनी बढ़िया वह होगी लेकिन आई0आर0 8 एक ऐसा चावल है जो ज्यादा देर रखने से टूट जाता है । इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन बातों की तरफ वह ध्यान दें इससे एक तो सरकार की बदनामी नहीं होगी और दूसरे पैसा जाया न होगा। (विघन)

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं और बता देता हूं। सोनीपत में किसी एक जगह पर रेड हुआ था। (विघन) फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट की ही बात मैं कर रहा हूं। लेकिन बाद में उसका कुछ नहीं हुआ। वह रेड एक बडें अफसर ने कियाथा। उस सज्जन ने यह कहा बताने हे कि भाई साहब, मैने अपने बाप की जमीन और मां के जेवर बेचकर नौकरी हासिल की थ। जब तक में वह पैसे वसूल नहीं कर लूंगा तब तक रि वत लेना बन्द नहीं करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, उस अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये चीफ मिनिस्टर साहब, मै आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आदमी तो आप दिल से बढ़िया है। लेकिन हमारी आप थोडी सी रिक्वैस्ट मान लें मेरे जैसे एम0एल0ए0 आपसे कुछ नहीं मांगते। हम तो सिर्फ यह चाहते है कि राज बढिया तरीके से चले और डिवैल्पमेंट का काम पूरा हो। (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने बढ़िया–2 आदमी अपने नजदीक लगाने भाुरू किये है। अहूजा साहब पुराने सो ालिस्ट है, फ्रीडम फाईटर हैं लेकिन मैं इनसे यह कहना

चाहता हूं कि आप ऐसे आदमियों से क्यों डरते हो जो न तो एम0एल0ए0 है और न एम0पी0 है। अगर आप ऐसा करना छोड दे तो मैं दावे से कहता हूं कि आप सारे हिन्दूस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब चीफ मिनिस्टर होगें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिये, आपका टाईम खत्म हो गया है। (विघ्न)

श्री देवेन्द्र भार्माः मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः अब आप एक मिनट में क्लोज–अप कर दिजियेगा।

श्री देवेन्द्र ार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, जब बजट बनता है तो उसे फाईनैंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और फाईनैंस सैकेटरी मिल कर बनाते है। इसे चाहे अकेला फाईनैंस सैकटरी बनाये, फाईनैंस मिनिस्टर बनाये या चीफ मिनिसटर बनाये परन्तु यह तीनों की सलाह से बना हुआ माना जाता हैं लेकिन बडे अफसोस की बात है औरहिनदुस्तान में मैने कभी ऐसा नहीं सुना जो बजट पे ा होने वाले दिन इस सै ान में हुआ। यही नहीं , डिप्टी स्पीकर साहब, उसके आगे भी बहुत कुछ हुआ। डैमोक्रेसी में हम कुलैक्टिव रिसपौसिबिलिटी की बात करते है लेकिन यहां कुलैक्टिव रिसपौंसिबिलिटी से भागना चाहते है। तीनों आदमियों की सलाह से बजट बना था लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि यह तो 'ऐन्टी किसान' बजट है।

मुख्यमंत्री (चौधरी देवी लाल): यह मैने कभी नहीं कहा कि 'ऐंटी किसान' है।

श्री देवेन्द्र ार्मा: कहा है ओर यह अखबारों मे आया है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय हो गया है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: केवल आधा मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप अब बैठिये। अब फाईनैंस मिनिस्टर साहब बोलेगें।

श्री देवेन्द्र भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, एम0एल0एज0 फलैट्स और कारों की बात मुझे कर लेने दो।

श्री उपाध्यक्ष्ज्ञ: मेहरबानी करके अब आप बैठ जाईये।

श्री देवेन्द्र भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, राव साहब ने कहा कि हमें स्टैन्डर्ड आफ जजमैंट तथा ने ानल मौरेलिटी की बात सोचनी चाहिये लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बात सिर्फ स्टूडैन्टस के उपर ही नहीं लादी जानी चाहिये। हम एल0एल0एज0 क्या करते हे यह भी देखना चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि आप एम0एल0एज0 का ट्रेंनिग कैम्प क्यों नहीं लगाते?

श्री उपाध्यक्ष: आपका सुझाव आ गया। अब आप बैठिये।

चौधरी लाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, एम0एल0एज0 यहां पढने नही बल्कि राज करने आये है।

चौधरी संत कवंरः आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। भाई देवेन्द्र जी ने यह कहा है कि एम0एल0एज0 को ट्रेंनिग देने के लिये कैम्प लगाये जाने चाहिये। मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब यहां पर कैम्प लगा हुआ था, उस समय पर ये सरकार को तोड़ने के लिये दिल्ली बैठे हुये थे। (विघ्न)

श्री देवेन्द्र भार्माः ऐसे हालात पैदा कर दिये थे कि मुकाबला करना पडा।(विघ्न)

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, जो एप्रोप्रिए ान बिल हाउस में अंडर कंसिड्रे ान है, इसमें 776 करोड यपये के खर्च का सवाल है। मेरा ख्याल था कि इतनी बडी रकम की हाउस में अनुमति ली जा रही है तो मैंबर साहेबान उसी हिसाब से रूल 203 में जो हवाल दिया है, उसको सामने रखते हुये एप्रोप्रिए ान पर कोई बुनियादी पालिसी की बात करेगें या एडमिनिस्ट्रे ान के बारे में जिनका बजट में हवाला नहीं दिया गया है, उस पर विचार रखेगें। लेकिन मुझे अफसोस है कि अकसर वही बातें दोहराई गई है जो जनरल बजट में आ चुकी है । यहां हाउस में डिमानडज पर तीन दिन तक बहस होती रही थी उनका भी मैने जवाब दिया था लेकिन अब जिन चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया है उनके बारे में जवाब देना चाहता हूं।

पहली बात भ्रश्टाचार के बारे में राव दलीप सिंह जी ने और मेरे नौजवान साथी देवेन्द्र भार्मा ने की। मैं यहां हाउस में बताना चाहता हूं कि भ्रश्टाचार क्यों पैदा होता है, क्यों बढ़ता है, यह समझना होगा। अगर हम समझ जाये ंतो उसको रोकने में आसानी हो जायेगी। लेकिन उस बुनियादी कारण का समण्ने के इलावा माननीय सदस्य चाहे वे अपोजी ान में है चाहे रूलिंग पार्टी में है, स्पैसिफिक एग्जाम्पल दे। यहां पर सब कह देते है कि इनसपैक्टर रि वत लेता है। लेकिन जनरल तरीके से कहने पर रि वत नहीं रूकती है। कौन सा इन्सपैक्टर ले रहा है उसका हवाला आना चाहिये। अगर इन्सपैक्टर ने किसी हलवाई का नमूना लियाहै तो इस बात का ब्योरा होना चाहिये कि फलां मौके पर, फलां इन्सपैक्टर ने नमुना भरते वक्त रि वत ली। जैसे चौधरी रिजक राम जी कह रहे थे, वे तो हर चीज का कैरीकेचर करते है। कैरीकेचर करने से हिन्दुस्तान की समस्या हल हो जाये तो मैं भी कैरीकेचर कर सकता हूं, लेकिन ऐसे समस्या का हल नहीं होगा। समसरूा का हल तो मेहनत करने से होगा। किसी भी कुरीति को समाज से हटाने के लिये कुर्बानी देनी पडती है, नुकसान उठाना पड़ता है। मैं सारे हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे दे ा में हमारे बुजुर्गो ने इस बात का तो यकीन दिलाया है कि सत्य की जीत होगी। परन्तु किसी ने नहीं कहा कि सत्य के लिये जो लडने वाले है उनको नुकसान नहीं होगा। रामायण और माहाभारत की आप मिसाल लेलें। राम सत्य के लिये लडे लेकिन रावण के खिलाफ लडने में उन्हे भी नुक्सान उठाना पडा और

आखिर में सत्य की जीत हुई। महाभारत में भी यही बात हुई। हमने आजादी की लडाई लड़ी कितने लोग भाहीद हुये, गोली का ि ाकार हुये। करप् ान जैसी भयानक चीज असैम्बली में भाशण देने से खत्म नही हो सकती। मैं इसके लिये अपने साथियों से कहूंगा (विघन) मै अपने साथियों से बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा। (विघन)

श्री मूल चन्द मंगलाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर , सर। हमारे फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि सत्य के लिये कुर्बानी देनी पड़ती है। इसमें कोई भाक नही है। करप् ान को रोकने के लिये हमारे सी0आई0डी0 के अुसरान इसी बात के लिये लगे हुये है और भी बहुत सी बातें है जिनके लिये हमें भी लड़ना है लेकिन उज्जीना डाइव ान ड्रेन बन रही है। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मूलचन्द जैनः मैने बहुत नम्रता से साथीयों के समने कहा है कि इस पर विचार करे। अगर आत स्पैसिफिक मिसाल देंगें तो उसकी पूरी तरह से इन्क्वायरी होगी। और जो भी कसूरवार होगा, उसको माफ नहीं किया जायेगा।

अब उस मौलिक बात की ओर हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भ्रश्टाचार क्यों होता है? मेरी यह धारणा है कि सरमायेदारी में समाज से भ्रश्टाचार बन्द नहीं हो सकता, असम्भव बात है। कमी तो हो सकमी है लेकिन उसको जड़मूल से

निकालना मुि कल है। सरमायेदारी निकलेगी तो भ्रश्टाचार बन्द होगां जहां तक जनता पार्टी का ताल्लुक है, उसने दे ा के सामने एक लक्ष्य रखा है कि इस दे ा में भाोशण रहित समाज कायम किया जाये। इस द ाा में सैन्टर ने भी बजट में संकेत किया है और वे धीरे–2 चल रहे है । मेरे लायक दोस्त चौधरी भाम ेर सिंह जी तो इस बात पर यकीन नहीं करेगें कि कोई भी लक्ष्य हो, अगर वह लक्ष्य दस कोस जाने का है तो एकदम कोई नहीं पंहुच सकता है, कदम–ब–कदम आगें बढना होता है। आज हम एक पड़ाव पर खडे है, उससे अगलजा कदम क्या हो, इसके बारे में सोचना है। आज क्या स्थिति है उसके बारे में सोचना है, क्या कदम उठाया जा सकता है। इस किसम का सुझाव कभी –2 आता है। मै आज हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस किस्म का सुझाव आयेगा तेा जरूर गौर करेगें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः आज आप जनसंघ को अपने में से निकाल दें, भाोशण रहित समाज आ जायेगा।

श्री मूलचनद जैनः बडे अफसोस से कहना पडता है कि जिस स्पिरिट से मैं बात कह रहा हूं उसकी तरफ कोइ विचार नहीं किया जा रहा। मैं यहां पर भ्रश्टाचार का जिक्र कर रहा हूं। हमारे नौजवान साथी श्री देवेन्द्र भार्मा चले गये है, उन्होने कुछ हाउस में कहा। बहुत दफा तो हमारी नुक्ताचीनी गलत इत्तलाह के आधार पर होती है। उनहोने यह सब कुछ गलत सूचना की बिना पर कहा। उन्होने यह भी कहा कि पहले तो 20 टन (12.00 बजे)

कोयला उनको दिया जाता था जिसे बढाकर अब 25 टन कर दिया गया है । मुझे अभी अभी पता लगा है कि पहले कोयला रानगंज से आता था जोकि सुपीरियर क्वालिटी का होता था औरउस 20 टन कोयले से जोकि रानीगंज से आता थ, एक लाख या डेढ़ लाख ईटें बन जाती थी लेकिन अब कोयला रानीगंज से नहीं आता। अब कोयला ध्नबाद माईन्ज से आ रहा है। वह कोयला थोडा इन्फीरियर क्वालिटी का हैं इस 25 टन कोयले से भी उतनी ईटें नहीं बनती जितनी उस 20 टन कोयले से बनती हैं (व्यवधान) जहां तक मुझे पता है, दो किस्म का कोयला होता है, एक स्पौन्सर्ड और दूसरा अन–स्पौन्सर्ड कोयला। अन–स्पौन्सर्ड कोयला जो होता है, इसका मतलब यह होता है कि इसे भट्टे का मालिक अपनी कोि ा ाों से लेता है, उससे बनी ईन्टों पर सरकार को कोई कन्ट्रोल नहीं है लेकिन जो स्पौन्सर्ड कोयला होता है, उस पर है.....

श्री देवेन्द्र भार्माः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, जैन साहब ने अभी यहां पर यह कहा है कि अन–स्पौन्सर्ड कोयला स्पौन्सर्ड दो किस्म का कोयला होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार ने यह फेसला कियाथा कि न तो हम उन्हे कोयला देगें और न ही हम उनसे ईन्टें लेगें तो यह पालिसी लागू क्यों नहीं की जा रही है? आज पोजी ान यह है कि भट्टा मालिक 70–80 प्रति ात कोयला सरकार द्वारा दिया हुआ इस्तेमाल कर रहे है।

श्री मूलचनद जैनः उपाध्यक्ष महोदय, 1–2 महीने से ही स्पौन्सर्ड कोयला हम उन्हे दे रहे है। जो अन–स्पौन्सर्ड कोयले की बनाई हुई ईंटे है, उनको हमने डी–कन्ट्रोल कर दिया है लेकिन जितनी ईन्टें स्पौन्सर्ड कोयला से बनायेगें, उनके लिये हम परमिट इ ू करेगें। तभी वह बिक सकेगी।एक बात चौधरी रिजक राम जी ने और कही। उन्होने यह कहा कि जीरी पर तो 7 परसैंट परचेज टैक्स है। पता नहीं उन्होने कंहा से पढ लिया । जो किताब मेरे पास है, इसमें तो 4 प्रति ात परचेज टैक्स पैडी पर लिखा हुआ है। सेल्ज अैकस के बारे में जहां तक ताललुक है, एग्रीकल्यरल एम्पलीमैंटस पर, खेती के काम आने वाले औजारों ओर म ीनों पर बिल्कुल नहीं है। एक बात चौधरी कंवल सिंह जी ने यह कही कि आयरन एंड स्टील पर पहले जो सैल्ज टैकस लगता था , वह प्रथम स्टेज पर लगता थ, लेकिन अब फाईनल स्टेज पर कर दिया गया है। मैने इस बात का जवाब जब जनरल डिस्क ान का जवाब दिया था, उस वक्त भी दिया था। मैने उस वक्त भी यह बताया था कि न सिफ आयरन एंड स्टील आइटम्ज बल्कि और 5–7 आईटम्ज ऐसी है, जिनको हमने विचार करने के लिये एक्साईज एंड टैक्से ान कमि ानर के पास दिया हुआ है ताकि वे इस बात पर गहराई से विचार करें और जिस तरीके से हमारी आमदनी बढ सकती है, वह तरीका हमें बतायें ताकि हम उसी तरह से उन पर सेल्ज टैक्स लगाकर प्रदे ा की आमदनी बढायें। सेल्ज टैक्स के बारे में यहा पर यह भी कहा गया कि हलवाइयों पर भी इसें क्यों लागू कर दिया गया है जबकि सेल्ज टैक्स को खत्म करने की

घोशणा की गई थी। मैने तो इस बारे में पब्लिक में भी कहाथा। मैं कई बार यह बात पहले भी दोहरा चुका हूं। आन्ध्र प्रदे ा, मद्रास है, वैस्ट बंगाल हैख् ये सब प्रदेश यह आवाज उठा रहे है कि स्टेटस को और ज्यादा फाईनैनि ायल पावर्ज दी जाये। मगर यहां पर यह कहा गया है कि सेल्ज टैकस को बिल्कुल ही खत्म किया जाये। मगर यहां पर यह कहा गया है कि सेल्ज टैक्स को बिल्कुल ही खत्म किया जाये। स्टेटस को जितनी फाईनैन्ि ायल पावर्ज कांस्टीचयू ान में दी गयी है, अगर सेल्ज टैक्स को खत्म कर दिया जाता है तो उससे स्टेटस के रिसोर्सिज और कम हो जायेगें। इसलिये सेल्ज टैकस के बिल्कल हटाये जाने का तो प्र न ही पैदा नहीं होता है।

चौधरी रिजक रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। सेल्ज टैकस अबौलि ा हो या न हो, इसके बारे में पहले जब चर्चा चला करती थी तो उस समय तो हमारे माननीय मंत्री जी यही कहा करते थे कि इसे खत्म किया जाये। अब यह कहते है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब सरचार्ज 2 प्रति ात से बढाकर सरकार ने 15 प्रति ात कर दिया था तो उस समय उन्होने इसी हाउस में तकरीर की थी। उस समय उन्होने यह कहा था कि जनता पार्टी के घोशणा पत्र में यह बात थी कि हम सेल्ज टैक्स को समाप्त करेगें। इन्होने उस समय बड़े जोर का प्रोटैस्ट किया था और अब ये सारी बातों को भूल गये है। (व्यवधान व भाोर)

श्री मूलचन्द जैनः मैने जो कुछ कहा था, वह मुझे अब भी याद है। आप मेरी स्पीच निकलवाकर देख लें आपको पता लग जायेगा। स्पीच बाकायदा रिकार्ड होती है। आप उसे निकलवा कर देख सकते है, ऐसी कोइ बात नहीं है जो मैने गलत कही हो। मैने यही कहा था कि जो आप मार्किट फीस बढा रहे हो, जो सरचार्ज 2 से बढाकर 15 प्रति ात कर रहे हो इससे जेा बोर्डर की मंडियां है, जैसे सांपला है, कालका है, अम्बाला है, इनमें ट्रेड पर असर पडेगा औरयहां पर ट्रेड कम हो जायेगा। यही मैने प्वांयट उस वक्त उठाया था फिर उनको रिलीफ यह दिया गया था कि सरचार्ज तो 15 प्रति ात से घटाकर दोबारा 2 प्रति ात कर दिया गया था और मार्किट फीस का जो असर है, उसके लिये जो नया सुझाव आ रहा है, उसके मुताबिक करने से यह कुदरती तौर पर होगा कि जो लोग छुपकर या कानून से बचकर अपना माल बाहर ले जाना चाहते है, ने नहीं ले जा सकेंगे इससे मंडियों को बडा फायदा होगा।

मास्टर ि ाव प्र ाादः आन ए प्वायंट आफ, आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर वे सेल्ज टैक्स घटा नहीं सकते तो बढा क्यो रहे है और फिर इसमें हलवाईयों को क्यों भाामिल कर रहे है?

श्री रघुनाथ गोयलः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। क्या वित्त मंत्री जी यह बतायेगें कि वे हलवाईयों को क्यों इसमें

भाामिल कर रहे है जबकि वे सेल्ज टैक्स को खत्म कर नहीं सकते?

श्री मूलचन्द जैनः मेरे साथी जो अभी बोल रहे थे चोधरी ि ाव प्रसाद और श्री रघुनाथ गोयल दोनों ने लिखकर दिया हुआ है.....

मास्टर ि ाव प्रसादः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चैलेन्ज करता हूं अगर मैने यह लिखकर दिया हो कि हलवाईयों के उपर टैक्स लगया दिया जाये। मैने यह कतई नहीं लिखकर दिया है।

श्री मूलचनद जैनः मैने अभी तो कुछ कहा भी नहीं इनहोने वैसे ही चैलेन्ज करना भाुरू कर दिया। मैने यही कहना है कि इन्होने मुझे यही लिखकर दिया है कि हलवाइयों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। अगर टैक्स लगाना ही है तो इनके तीन ग्रेड बना दिये जाये।

मास्टर ि ाव प्रसादः तीन ग्रेड वाली बात मैने नहीं लिखी है।.....(व्यवधान एवं भाोर)

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब,जैन साहब ने मार्किट फीस के बारे में जिक्र किया है। मार्किट फीस जब 2 से 3 प्रति ात बढाई गयी थी, उस वक्त एक कमेटी बनाई गयी थी ताकि 3 से दोबारा 2 प्रति ात करने में जो सरकार को घाटा होता है, उको पूरा करने के लिये सरकार को कुछ सुझाव दिये जायें ताकि यह पता लग सके कि हम इस तरह से इसको खत्म

कर सकते है। उस वक्त व्यापारियों ने सुझाव दिया था जो बार्डर पर इंडस्ट्रीज लगी हुई है उनमें सी0एस0टी0 बे ाक 1 प्रति ात ओर बढा दिया जाये। वह तो सरकार ने बढा दिया और उससे सरकार को काफी फायदा भी हो गया लेकिन अभी तक वह मार्किट फीस जो बढाई गयी थी, घटाई नहीं गयी है। वह वैसे की वैसे चल रही है।

श्रीमती भाांति देवीः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री जी की अजीब सी स्थिति देखी । कभी तो वे इधरदेखते है कभी उधर इ ाारा करते है। कम से कम इनको इस बात की तो पूरी जानकारी होनी चाहिये कि किस विधायक ने क्या लिख कर दिया है?

श्री मूल चन्द जैनः एक बात चौधरी रिजक राम जी ने और कही। वह यह कि सरकार का यह दाव कि 85 प्रति ात जो बजट है, वह खेाती पर खर्च कर रही है, यह बिल्कुल गलत है। सरकार ने यह कहीं नहीं कहा है कि वह बजट का 85 प्रति ात हिस्सा खेाती पर खर्च कर रही है। हमने यह कहा है कि 85 प्रति ात बजट का हिस्सा देहातों के विकास के कामों पर खर्च हो रहा है इस बात के लिये मैने आकंडे भी उस वक्त दिये थे। एक बात उन्होने यह भी उठायी कि बिजली का खर्च भी इसमें भाामिल कर लिया गयाहैं तो इस बारे में मैने उस वक्त भी जवाब दिया था कि जो भाहरों में बिजली खर्च होती है, उसी प्रकार भाहरों में बने स्कूल, काजिल, हस्पताल का लाभ देहाती भी उठाते है तो कितनी

भाहरों को सहूलियत होती है ओर गांवों को कितनी सहूलियत होती है, अगर इन दोनो चीजों को बराबर समझ लिया जाये तो बजट का 85 प्रति ात हिस्सा हमारें देहातों के विकास पर खर्च हम कर रहे हैं इसमें कोई भाक की बात नहीं हैं (व्यवधान)। देहात के भाई भाहर में खरीदो–फरोख्त करने के लिये आते है। गांवों में हस्पताल खुल रहे है, स्कूल खुल रहे हैं भाहर के लोग वहां पर नहीं जाएंगे। यह जितना भी रूपया खर्च कर रहे है यह देहात की सहूलियत के लिये, खेती में तरक्की के कामों के लिये खर्च कर रहे है। यह नहीं है कि खेती के लिये ही खर्च किया जायेगा। बलिक देहात की डिवैलपमैंट के लिये खर्च किया जायेगा। अगर हम यह पैसा वहां खर्च कर रहे है तो हम कोइ अहसान नहीं कर रहे है। यह हमारा फर्ज है। उपाध्यक्ष महोदय, इम्पोरटिड कार और माकानों के बारे में कहना बाकी रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम किफायत करने के बारे मे कोई कदम उठाते है तो भी नुक्ताचीनी होती है। इम्पोरटिड कार हमने हटा दी है तो भी लोगों ने नुक्ताचीनी करना आरम्भ कर दिया। (व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। जैन साहब के बारे मे ही अखबारों मे आया था कि वे कहते है कि मैं इम्पोरटिड कार लूंगा

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, पता नहीं श्री संत कंवर को क्या हो जाता है कि इनको समझा भी देते है तब भी इनकी समझ मे ंनही ंआता। मैने इनको अपने पास बिठाकर

समझाया था कि न मैने चीफ मिनिसअर को कहा ओर न ही चीफ सैक्रेटरी को कहा कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिये। बल्कि जब मुझे कहा गया कि कैबिनेट में तुम्हारा नम्बर चार है और बडी आसानी से बड़ी कार ले सकते हो तो मैने कहा कि मै बड़ी कार नहीं लूंगा। मै तो इसी कार में गुजारा कर लूगां। यह बात मैने कई दफा समझा दी है और मैने यह भी कहा कि अखबारों में कई बातें निकल जाती है अगर वे ठीक न हो तो हमारी क्या जिम्मेदारी है।

श्रीमती भाांति देवीः सारी बात पेपर में आई है हमें तो पता नहीं कि वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री मूलचन्द जैनः अब तो क्लियर हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, देवेन्द्र भार्मा ने पब्लिक रिले ांज डिपार्टमेंट को स्ट्रैग्थन करने की बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसलिये इस डिपार्टमेंट को ज्यादा रूपया दिया है ताकि सारी जानकारी जनता तक पहूंच सके। हमने कोई जनता पार्टी के गीत तो उससे गवाने नहीं है बल्कि जो सहूलियतें हम पब्लिक को दे रहे है। उसकी जानकारी यह डिपार्टमैंट पब्लिक को दे।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक रिले ान्ज डिपार्टमेंट में दो–तीन पोस्टें ऐसी है जिन पर लोग पन्द्रह–2 साल से बैठे हुये है आज भी उनको डार हे कि कहीं नौकरी से न निकाल दिये जाये।

श्री मूलचन्द जैनः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस मो ान को पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि –

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं02) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज–2

श्री उपाध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज–3

श्री उपाध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाड्यूल्ड

श्री उपाध्यक्षः प्र ान है–

कि ि ाडयूल बिल का ि ाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज–1

श्री उपाध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र ान है–

कि अनेक्टिंग फार्मूला बिल का अनेक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र ान है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (श्री मूलचन्द जैन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1979

वित्त मंत्री (श्री मूलचन्द जैन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryuana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, कुछसमय पहले जब आप पहले बिल की क्लाज पास करवा रहे थे तो मैं खड़ा हुआ था .....
.....

Mr. Deputy Speaker: It is a reflection on the Chair. It should be expunged.

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदस्यों के लिये बसों की सुविधायें बढानें के बारे में आया है इसका मैं विरोध करता हूं। इससे पहले हरियाणा की बसों में सिर्फ एम0एल0ए0 ही सफर कर सकता था लेकिन अब जो सं ाोधन पे ा किया है उसके अनुसार.....

श्री हरफूल सिंह: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में हर सदस्य के लिय कानून बने है लेकिन ऐसा लगता है कि स्वामी जी के लिये कोई कानून नही है। (व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

चौधरी हुक्म सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वांयट आफ आर्डर, आप हमें तो बोलने का टाईम ही नहीं देते। आप बार बार स्वामी जी का नाम लिये जा रहे है। (व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे I: नियम तो सब के लिये एक जैसे है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने विधायकों के लिये जो कुछ सुविधायें दी है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी बोल रहे हैं। कृपया आप उन्हें बोलने दें।

स्वामी आदित्यवे I: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जब पहले ही विधायको को कई प्रकार की सुविधायें दे रखी है तो इसके अलावा और जयादा सुविधाएं क्यो दी जा रही है? जैसे सरकार ने विधायकों को बस में पहले ही बिना टिकट के चलने की सुविधा दे रखी है, अपनी स्टेट में विधायक फ्री सफर कर सकते है और अपने राज्य से बाहर भी बिना टिकट के जा आ सकते है। इसके बावजूद भी उपाध्यक्ष महोदय मेरी समझ में नही आता कि सरकार.....(ाोर)

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैं स्वामी जी जिस बात पर बोल रहे है, उस पर डिसक ान हो ही नहीं रही है। क्ला 2 पर जब सरकार की तरफ से कोई अमैंडमेंट पे ा की जाएगी त बवह बोल सकते है अभी तो ओरिजीनल बिल ही पे ा हुआ है।

स्वामी आदित्यवे I: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा थ कि विधायकों को तो पहले ही बहुत सारी सुविधाएं सरकार की

तरफ से दी जा चुकी है ओर अब और देने की सरकार की परपोजल हैं (ाोर)

आवाजें: डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी जी, किस क्लाज पर बोल रहे है।? .....(ाोर)

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को किसान ओर गरीब मजदूरों की ओर भी ध्यान देना चाहिये जो कि बहुत मेहनत करते है, परिश्रम करते है, लेकिन सरकार ने उन गरीब मजदूरों ओर किसानों के लिये कुछ नहीं किया हैं जो स्वयं परिश्रम करते है, मेहनत करते है ओर अपने खून पसीने की कमाई हरियाणा सरकार को देते है। उनकी तरफ सरकार ध्यान नही दे रही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमें अपनी सहूलियतों की तरफ कम ध्यान देना चाहिये और जो गरीब मजदूर और किसान है, उनकी तरक्की की तरफ, उनके उत्थान की तरफ जयादा ध्यान देना चाहिये जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर हमारे दे ा का किसान प्रफुल्लित होगा तो दे ा भी उन्नत होगा। गरीब किसान जो हमारे प्रान्त को अन्न पैदा करके देता है उसकी समृद्धि के लिये सरकार को हर सम्भव प्रयत्न करने चाहिये। किसान और मजदूरों के बच्चों के उत्थान के लिये भी सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिये न कि हर समय अपने ही हितों को ध्यान में रखना चाहिये (ाोर)

आवाजें: उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी किस पर बोल रहे है, इनको बैठाया जाये। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी, अब आप बैठिये (ाोर)।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये जिससे दूसरे सदस्यों को बोलने में बाधा पडे।(ोार) उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल तो पास हो ही जाएगा लेकिन हमें यहां पर बोलने भी नहीं दिया जाता.....बार बार कहा जाता है कि स्वामी जी को बैठाऔ ओर आप ने भी कह दिया कि स्वामी जी आप बैठ जाईये (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी, कई तरफ से प्वांयट आफ आर्डर रेज हुये थे इसलिये मैने कहा था कि आप बैठ जाइये , मैने बोलने से नहीं रोका।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, सदन के कानून और अनु ाासन तो सब के लिये है, मेरे अकेले के लिये नहीं है। मैं बोल रहा हूं और सभी मैंबर साहेबन भाोर मचा रहे है।

चौधरी संत कवंरः डिप्टी स्पीकर साहब, जब किसानों पर टैक्स लगाया जाता है तब तो स्वामी जी इस बात का समर्थन करते है लेकिन अब चीप पापुलैरिटी हासिल करने के लिये इस बिल का विरोध कर रहे है। (ाोर)

डा0 बृज मोहन गुप्ता (जगाधरी): उपाध्यक्ष महोदय, मै तो इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हू। यह जो बिल है, इसमें जो सुविधायें अब दी जा रही है वे सभी के लिये है यह बडी अच्छी बात हैं रेलवे के अन्दर जब हम सफर करते है तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जा सकते है, अब मु कल यह है कि जिन लोगों के पत्नियां नही है वे इस बिल का विरोध कर रहे है। (ाोर)

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): जायज और नाजायज पत्नियां.....(ाोर)

कंवर राम पाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि अभी जब मेरे लाईक साथी बोल रहे थे तो हमारे एक मंत्री महोदय ने बैठे बैठे ''जायज और नाजायज'' पत्नियों की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने ऐसा किस लिहाज से कहा है? क्या मजाक किया गया है या ठीक कहा गया है? (ाोर)

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न हैं जब कोई माननीय सदस्य किसी एक विशय के सम्बन्ध में बोल रहा हो तो उसी के सम्बन्ध में पवांयट आफ आर्डर उठाया जाना चाहिये न कि किसी दूसरे प्वायंट पर किसी तरह का आक्षेप होना चाहिये। (ाोर)

डा0 बृज मोहन गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह व्यवस्था थी कि रेलवे के अन्दर हम अपनी पत्नी बच्चों को ले जा सकते थे और बस में नहीं और जब हम बस मं जाते थे तो हम तो बिना टिकट के जाते थे औरअगर हमारे साथ हमारी पत्नी वगैरह हो तो उसकी टिकट मांगी जाती थी यह एक तरह का मखौल था जिसका कि इस सरकार ने अब हल ढूंढ लिया है और अब यह कर दिया है कि अब हम बसों में अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा सकते है यह बहुंत अच्छी बात है। मेरे विचार से तो काफी समय पहले ही यह बिल पास हो जाना चाहिये था। देरी हो गई है फिर भी मैं इसके लिये अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि उसने बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया है। और मैं इसके साथ ही इस बिल का पूरी ताकत से समर्थन करता हूं इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी रामलाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाास्त्रों में पत्नी को अर्द्धांगिनी कहा गयाहै, इसलिये वह भी साथ ही जायेगी।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी बडी मेहरबानी जो आपने मूझे बोलने का समय दिया। मैं दो तीन मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विधायको को जो और सुविधायें दी जा रही है, वह गलत काम किया जा रहा है। (ाोर)

श्री भागी रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है, मेरी परसों ही कामरेड भांकर लाल जी से बात हूई थी। मैने उन से यह पूछा था कि आप इस तरह सरकार की हर पालिसी के खिलाफ क्यों बोलते हो तो उन्होने मुझे कहा था कि जो कुछ इन्होने पास करवाना है, वह तो हो ही जाना है पर मै तो इसलिये बोलता हूं ताकि मेरा नाम अखबारों मे आये और लेाग पढ़े (हंसी)

श्री जगननाथः डिप्टी स्पीकर साहब, कामरेड भांकर लाल जी भी स्वामी जी की कैटेगरी में आते है। (हंसी)

कामरेड भांकर लालः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था ओर जो सहूलियतें विधायको को दी जा रही है, वह बहुत ज्यादा है। मेरा तो अपनी सरकार को कहना है कि इन बातों केा छोड़कर गांवो के लोगो, कर्मचारियों और दूसरे लोगों जिनके पास खाने, पीने और रहने के साधन बहुत कम है, उन लोगों को सहूलियतें ज्यादा दी जाये। मैं ज्यादा न कहता हुआ यह कहूंगा कि सरकार जो कुछ कर रही है यह उचित नहीं हैं जो कुछ चाहिये उसे खुद ही अपने लिये जुटा लेते है। अगर इस टैडेसी को रोका गया तो लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेाग अपने दिल में यह सोचेंगे कि विधायक और मिनिस्टर लोग अपने वास्ते तो सब प्रकार से सोचते है कि उनको यह मिलना चाहिये, यह सहूलियतें मिलनी चाहियें लेकिन जो रेड़ी, खौंचा चलाने वाले

गरीब लोग, किसान मजदूर और छोटे कर्मचारियों की भलाई के लिये विधानसभा में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। (ाोर)

चौधरी हरस्वरूप बूराः अभी चहां पर गरीब बच्चों और गरीब किसानों का जिक करके यह कहा है कि इन लोगों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। बल्कि विधायक अपने लिये ही सोच रहे है, यह गलत है। सरकार की तरफ से बसों मे जो अपनी पत्नियों और बच्चों को ले जाने का प्रावधान किया गया है, इस बारे मे मैं अपने आनरेबल मैंबर को यह बता देना चाहता हूं कि जिन गरीबों का ये यहां पर जिक कर रहे है, हम उन को भी अपने साथ ले जा सकते है। (तालियां)

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, इस इ ा पर जो बोला जा रहा है, इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि ओरिजिनल बिल की जो क्लास 2 है, उस पर अमैंडमेंट पहले मूव होनी चाहिये। एक बार हम बोलेगें और दूसरी बार वे बोलेगें। अगर वह अमेंडमेंट भी साथ ही इक्टठी मूव हो जाए तो इकटठी डिसक ान हो सकती है। इस प्रकार टाईम की सेविंग भी हो जायेगी।

कामरेड भांकर लालः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दोबातें कहकर अपना स्थान लेता हूं। यह जो चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टरों ने कोठियां और कारों को छोडने का फैसला किया है, यह अच्छी बात है। लोगों के सामने यह एक आद र्

पे ा हुआ है लेकिन इस बारे में एक बात और है कि कोठियों को छोडने के बाद फलैटस में आने पर जो बाहर तम्बू लगायें गये है, उन पर 100, 200 रूपये का खर्चा रोज का और बढ़ गया हैं क्या ऐसा करने से ये मंत्री लोग इकनोमी कर पायेंगें? कभी नहीं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः भाकंर लाल जी, आप बैठिये। आपका टाईम खत्म हो चुका है। (ाोर)

श्री सुरेन्द्र सिंह (तो ाम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खडा हुआ हूं। आज हरियाणा प्रान्त में बेराजगारी दिन प्रति दिन बढती जा रही है। गरीब लोग एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते और जिनके बच्चे स्कूलों में पढते है। वे अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे सकते। एक तरफ तो बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हो ओर दूसरी तरफ आप पैसेंजर टैक्स बढा रहे हो.....

श्री जय नारायणः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी पिछले दो सालों से ही बढी है या इनके टाइम में भी थी?

श्री सुरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आज गरीब आदमियों को एक टाइम का खाना भी मु कल से मिलता है, फिर भी बसों के किराये बढाये जा रहे है । गरीब

आदमी को भी तारीख के लिये या किसी बीमारी के इलाज के लिये भाहर में जाने के लिये बसों में सफर करना पडता है। अगर कोई बीमारी के इलाज के लिये बाहर जाता है तो सरकार उनसे भी किराया लेती है और उस किराये को हर साल बढाती रहती हैं किराये बढाने के बावजूद भी आज बसों की बहुत दुर्द ाा है। अगर आप गर्मी के मौसम में, लम्बें सफर मेंयहां से लोहारू जाएं तो रास्ते में बस खडी हो जायेगी जहां पीने के लिये पानी भी नहीं मिलता (ाोर) मेरे कहने का मतलब यह है कि गरीबों पर टैक्स भी लगायें जा रहे है लेकिन उनको सहूलियत कोई नहीं दी जा रही है। इसके अलावा यह जो एम0एल0ए0 के साथ दूसरे आदमी को मुफत सफर करने की सुविधा दी जा रही है, मैं इसका विरोध करता हूं। छूट तो एम0एल0ए0 को मिली है उसकी पत्नी को नहीं मिली है। इसलिये सहूलियत केवल विधायक को होनी चाहिये न कि उसके सारे परिवार को .....

श्री जगननाथः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि ये कहते है कि बसें खराब हैं इनकी हकूमत ने एक एक साल में संजय के थ्रू 7–8 सौ गाड़ियों की बाडी मारूति के नाम से कहीं से बनवाई? वे सब बाडियां एक साल के बाद टूट गई। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि उस समय जो इन्होने गलत बाडियां बनवाई जो 8 साल की बजाये केवल एक साल चली इनके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या यह पिदली सरकार का कसूर है या इस सरकार का?

श्री सुरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना विरोध करता हूं कि यह जो विधायक के साथ उसकी पत्नी को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है, यह बिलकूल गलत है। इससे सरकार पर बहुत बोझा पडेगा। केवल इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

सरदार सुखदेव सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैं मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होने कभी बस में सफर भी किया है? ये दूसरे विधायकों के बारे में क्यों कह रहे है?

चौधरी हुक्म सिंह (दादरी): डिप्टी स्पीकर साहब, मे इस बिल के हक में बोलने के लिये खडा हुआ हूं। अभी कामरेड भांकर लाल जी और स्वामी जी इसकी मुखालफित कर रहे थे। इन बेचारों के पास अपने साथ ले जाने के लिये कुछ है नहीं इसलिये इन्होने तो विरोध करना ही था। भाई सुरेन्द्र जी ने इसलिये विरोध किया कि वे अपोजी ान में है। इन्होनें इसका विरोध इसलिये किया ताकि कल को अखबारों मे नाम आये। भाई पोहलू जी चुप बैठे है वे इस बिल के हक में है।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि कोई सदस्य बोलते वक्त दूसरे सदस्य पर किसी किस्म का आक्षेप न करे।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन ान आफ मैंबर्ज) अमेंडमेंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज –2

Mr. Deputy Speaker: Notice of an amendment to this clause has been received from the Hon. Chief Minister which may please be moved.

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज दो पर अमैंडमेंट मूव कर रहा हूं जो यह है कि –

For the proposed clause (b) of sub-section (1) of section 7 fo the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members)Act, 1975, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b)(i) two free non-transferable passes which shall entitle him and his wife or any other person accompanying him to travel at any time by any public service vehicle of Haryana State Transport Undertaking, including deluxe coach, and

(ii) one free non-transferable pass which shall entitile him to travel at any time within the State of Haryana or the Union Territory of Dehi or the Union Territory of

Chandigarh by any public service vehicle of the pepsu Road Transport Corporation;

Provided that if the journey is performed by him by an air-conditioned vehicle, he shall pay the difference between the fare of such vehicle and that of a deluxe vehicle."

मैं निवेदन करता हूं कि इस अमैंडमेंट को स्वीकार किया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

For the proposed clause (b) of sub-section (1) of section 7 fo the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members)Act, 1975, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b)(i) two free non-transferable passes which shall entitle him and his wife or any other person accompanying him to travel at any time by any public service vehicle of Haryana State Transport Undertaking, including deluxe coach, and

(ii) one free non-transferable pass which shall entitile him to travel at any time within the State of Haryana or the Union Territory of Dehi or the Union Territory of Chandigarh by any public service vehicle of the pepsu Road Transport Corporation;

Provided that if the journey is performed by him by an air-conditioned vehicle, he shall pay the difference between the fare of such vehicle and that of a deluxe vehicle."

Mr. Deputy Speaker: Question is-

For the proposed clause (b) of sub-section (1) of section 7 fo the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members)Act, 1975, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b)(i) two free non-transferable passes which shall entitle him and his wife or any other person accompanying him to travel at any time by any public service vehicle of Haryana State Transport Undertaking, including deluxe coach, and

(ii) one free non-transferable pass which shall entitile him to travel at any time within the State of Haryana or the Union Territory of Dehi or the Union Territory of Chandigarh by any public service vehicle of the pepsu Road Transport Corporation;

Provided that if the journey is performed by him by an air-conditioned vehicle, he shall pay the difference between the fare of such vehicle and that of a deluxe vehicle."

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

क्लाज –1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनेक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर सहाब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। अभी यहां पर एप्रोप्रिए ान बिल आया उस परभी सदस्य बोलना चाहते थे और इस बिल पर भी सदस्य बोलना चाहते है, अब इस बिल की थर्ड रीडिग की स्टेज आ रही है इसलिये कायदे के अनुसार आपको जो मैंबर बोलनाचाहें, उनको बोलने के लिये टाइम देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्षः अगर सदस्य सही टाईम पर बोलने के लिये खडे हे तो उनको पूरा मौका दिया जाता है।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंम्बली (अलाउंसिंज एंड पैन ान आफ मैंबर्ज) बिल, यथा सं ाोधित पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंम्बली (अलाउंसिंज एंड पैन ान आफ मैंबर्ज) बिल, यथा सं ाोधित पास किया जाये।

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह बिल पास न किया जाये।

चौधरी रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज 2 की अमेंडमेंट के साथ यह बिल सदन में रखा गया है। इसके बारे में दो भाब्द कहना चाहता हूं । यह जो अमेंडमैंट रखी गई है इसमें लिखा है–

"two free non-treansferable passes which shal entitile him and his wife or any other person accompanying him....."

इसमें ''ऐनी परसन'' जो लिखा है इस बात से यह पता लगता है कि असैम्बली के जो मेंबर्ज है उनको दो पास दिये जाते है। ''ऐनी परसन'' के अनुसार अगर वह मेल मैंबर है तो अपने साथ अपनी बीती को ले जा सकता है। मेल मैंबर को तो यह

अधिकार दिया है परन्तु जो फीमेल मैंबर है, अगर उसके साथ उसका पति जाना चाहे तो यह अधिकार उसको नहीं दिया गया। यह डिस्क्रिमीने ान इसमें नहीं होनी चाहिये थी। मैंबर के साथ हिज/हर लगाया है तो उसमें हसबैंड/वाईफ भी होना चाहिये था।

Shri Surrender Singh: It is not 'husband', but any other person.

चौधरी रिजक रामः दूसरी बात मैं डिप्टी स्पीकर यह अर्ज करन चाहता हूं कि जो मैंबर पत्नी है तो उसके साथ उसका पति होगा ओर जब पति पत्नी दोनो ंजायेगें तो उनका बच्चा भी साथ होगा। फिर बच्चे का टिकट लेना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके बारे में जो ''ऐनी परसन'' की अमैंडमेंट करने जा रहे है, इस पर वित्त मंत्री जी ध्यान दे।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो चौधरी रिजक राम जी और अपोजी ान के मैंबर इस अमैंडमेंट को अपोज कर रहे है, मैं अपने लायक दोस्तों से कहना चाहूंगा कि यह बिल सदन में दोबारा लाया गया है । कुछ दिन पहले जब इंट्रोडयूस करने के लिये लाया गया था उस वक्त इनको इसमें अमैंडमेंट देनी चाहिये थी। इनको जो ''एनटाईटल हिम'' पर एतराज है, वह ला की इंटरप्रटे ान के मुताबिक ''हिम इन्कलूडज हर'' समझा जाता है। फिर इसमें लेडी मैंबर भी आ

जायेगी। ''ऐनी अदर परसन'' के लिये यह बिल रोका नहीं जा सकतां ''ऐनी अदर परसन'' में सब कुछ आ जाता है।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंम्बली (अलाउंसिंज एंड पैन ान आफ मैंबर्ज) बिल, यथा सं ाोधित पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः अगर हाउस की सैंस हो तो सदन का समय एक घंटा बढा दिया जाये।

आवाजें: नहीं जी,एक घंटा बहुत ज्यादा है।

चौधरी भजन लालः आधा घंटा बढा दिया जाये।

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टभ स्पीकर साहब, आधे घंटे में बात नहीं बनती, यह परसों टेक अप कर लेना।

श्री उपाध्यक्षः क्या हाउस की सैंस है कि समय आधे घंआ बढा दिया जाये?

आवाजें: हां।

श्री उपाध्यक्षः हाउस का समय आध घंटे के लिये बढाया जाता है।

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैंम्बर्ज)

बिल, 1979

वित्त मंत्री(श्री मूल चन्द जैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलीटीज टू मैंबर्ज) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलीटीज टू मैंबर्ज) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। मैं इसके लिये दो सुझाव जैन साहब कौ देना चाहता हूं कि यह जो 45 हजार रूपये का प्रोवीजन मकान बनाने के लिये रखा गया है, इसमें प्लाट ओर सारा हाउस बनना है जो कि आज के जमाने में बहूत मु कल है।आज के हालात को देखते हुये इसको बढायाजाये। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी मेरी गुजारि ा मंत्री महोदय से यह कि यह तो बहुत ठीक है कि हमारे लिये इस प्रकार का प्रोवीजन कियागया है परन्तु इसके साथ दूसरे लो इन्कम ग्रुप और मिडिल इन्कम ग्रुप के लोगों की हजरों अर्जियां मकानें के लिये डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर पड़ी है, उनका प्रबन्ध किया जाये।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): आप उनके बारे में बताइये , उनका भी प्रबन्ध किया जायेगा।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): डिप्टी स्पीकर साहब, मैने इस बिल के बारे में आज सुबह अमैंडमेंट दी थी, पता नहीं किस वजह से मिस–अलाउड हो गई। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि क्लाज 5 में यह प्रोविजन दिया हुआ है:–

'Provided that no advance for building the house shall be sanctioned unless the plost or land on which the house is to be built, is exclusively owned and possessed by the member applying therefore, and is free from all encumbrances."

इसका मतलब यह हुआ कि जिस जमीन पर हमारा कोई आनरेबल मैंबर आना घर बनाना चाहेगा, वह हर बात से फ्री होना चाहिये। अगर इस पर आनरेबल मैंबर का पोजै ान नहीं होगा तो वह मकान नहीं बना सकेगा। मैं मंत्री महादेय के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा कि हरियाणा में बहुत–सी संस्थायें है, जैसे हुड्डा एजेंसी है या अरबन इस्टेट एजेंसी है, जिनसे 25 प्रति ात डिपाजिट करने के बाद प्लाट लिया जा सकता है और बाकी आसान कि तों में दिया जाता है। इस हालत में जिन आनरेबल सदस्येां के अपने प्लाट है, वे जब तक उन पर पोजै ान नहीं कर लेगें लोन नहीं ले सकते क्योकि वह प्लाट फ्री फ्राम आल इनक्मबरेंसिज नहीं होगा, इसलिये उसको लेान भी नहीं मिलेगा।

जब तक वह प्लाट उसके नाम ट्रांस्फर नहीं हो जाता उसको इसका फायदा नहीं होगा। ज्यादा अच्छा हेाता यदि इसमें यह किया जाताः—

'After the words "free from all encumbrances', the words ' except in cases where the plot is taken from the Government or any of its agencies' be added.'

अगर किसी आनरेबल मैंबर ने गवर्नमेट की एजेंसी से प्लाट लिया है और वह रैगूलर कि त अदा करता है तो इसकी कोई वजह नहीं है कि उसमें उसकी आनरि ाप न हो। अगर वह रैगुलर कि तें देता है तो इसका मतलब है कि वह मकान बनाने के लिये ही अप्लाई करेगा इससे जाहिर होता हे कि वह मकान बनायेगा। इसलिये मेरी अर्ज है कि जिनके पास ऐसे प्लाट है, कहीं वेइस सुविधा से वंचित न रह जाये। मेरी वित्त मंत्री जी से दरखास्त है कि इस पर विचार करे। इस अमैंडमेंट को जो मैंने बताई है लगायें । आप अ योंरैस दे ताकि इससे मैंबर लाभ उठा सकें और इस सुविधा को उपलब्ध कर सकें।

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): यह जो हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है, इसमें सरकार ने विधायकों को एक तो मकान बनाने के लिये कर्ज देने की व्यवस्था की है, दूसरी कार खरीदने के लिये सुविधा दी है। मकान बनाने के लिये 45 हजार रूपये और कार खरीदने के लिये

30 हजार रूपये देने की व्यवस्था की गई है। मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों में से एक ही सूविधा दी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्षः एक ही मिलेगी।

स्वामी आदित्यवे ाः जब सरकार ने एक चीज खरीदने का अधिकार दिया हे तो उपाध्यक्ष महोदय, धीरे–2 जब उनको अगुंली पकड़ने की जगह मिलेगी तो वे पहुंचा भी पकड लेगें। इस तरह से यह तो काम बढ जायेगा। मेरे विचार से यह सं ाोधन न किया जाये। हरियाणा में जिन लोगों के पास मकान नहीं है, पहले उनका यह सुविधा प्रदान की जाए, बाद में उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को यह सुविधा दी जाये।

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वांयट आफ आर्डर। स्वामी जी आप डिपार्टमेंट से अगर घर के लिये कर्जा नहीं लेना चाहते तो जितनी दुकानें चाहे, बना सकते है, आप को कर्जा देगें।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी बहूत है जिनके पास मकान नहीं है और 10–10 साल से आज तक उन्हें मकान बनाने के लिये कर्जा नहीं मिल रहा है। दूसरी बेइन्साफी यह है कि एम0एल0एज0 को तो यह कर्जा 7 परसैंट ब्याज पर दिया जायेगा और किसानों को 11 परसैंट पर दिया जाएगा।

श्रीमती भांति देवीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वामी जी का ध्यान इस तरफ दिला दूं कि दोनो सुविधायें विधायको को नही दी जा रही है, एक ही दी जायेगी, चाहे तो मकान की ले ले चाहे

कार की ले लें । इनको गलतफहमी हो गई है। दोनों सुविधायें कर्जे के रूप में है और दोनों पर ब्याज देना पडेगा।

स्वामी आदित्यवे ा: पटौदी और मेवात के एरिया में लोग दर–दर की ठोकरें खा रहे है, उनको मकानों के लिये कर्जा नहीं दिया जा रहा है। केवल विधायकों को 7 परसैंट पर दिया जा रहा है। एक आदमी विधायक बनने के बाद कोइ परमात्मा नहीं बन जाता है, वह भी जनता का ही सेवक है, उनको जनता की सेवा करनी चाहिये। जिस तरह से हमने जनता से वायदे किये थे हम उन वायदों के खिलाफ चल रहे है, इसलिये मैं चाहता हूं कि यह बिल सदन के सामने पे ा न किया जाये।

चौधरी लाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, एम0एल0एज0 ऐसे पत्थर तो है नहीं कि कोई चीज खा नहीं सकते। जब हम कुछ चीज खाते है तभी तो हमारा सांस चलता हूं। कर्जा तो कोई भी ले सकता है, कर्जा लेना कोई पाप नहीं है। (व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें सदस्यों को पूरी फैसेलिटीज दी जाये। इसमें तो सिर्फ 45 हजार रूपये मकानों के लिये दे रखे है जोकि आज की मंहगाई को देखते हुये बहुत कम है क्योंकि ईंटें भी बहुत मंहगी है। सीमेंट, लोहा, तथा लकड़ी भी बहुत मंहगी मिलती है। इसलिये मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब से गुजारि ा करूंगा कि कम से कम सुविधा एक लाख रूपये की दी

जाये क्योंकि यह तो एक कर्जा ही है। इसमें कोई एहसान की बात तो है नहीं, कर्जा तो कोइ भी लें सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि आम आदमी की तरह एम0एल0एज0 को भी सिक्योरिटी देनी पडेगी। यह तो एम0एल0एज0 की बेइज्जती है। जो पैसा देना हैै वह इस तरह से दिया जाये जिस तरह से एम0एल0एज0 को टी0ए0, डी0ए0 देते है। एम0एल0ए0 की परसनल सिक्योरिटी होने पर पैसा एंडवास दिया जाये। इसके बाद कार का पैसा है। आजकल एक एम्बैसडर कार 40 हजार रूपये से भी जयादा की आती है। मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कारें सरकारी कोटे से आती है, उनही में से अगर कोई एम0एल0ए0 लेना चाहे तो उसको दे दे। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर एम0एल0एज0 को कर्जा देना है तो खु करके दें, इसमें एम0एल0एज0 को ब्याज भी देना पडेगा। इन चीजों की बिना फैमिली के आदमियों को जरूरत नहीं है। यह भी जनता पार्टी ने गलती की कि इनको टिकट दे दी, इनको तो टिकट भी नहीं देनी चाहिये थी। कोई आन्ध्रा प्रदे ा से आ गया और कोई कहीं से आ गया। खैर, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में कहता हूं कि यह एम0एल0एज0 से सिक्योरिटी न ली जाये।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत ही छोटा सा बिल है और श्रीमती भार्ति देवी ने कहा कि विधायको को दोनों सहूलियतें नहीं मिलेगी, इनमें से कोई एक ले

सकते है। सहूलियतें भी क्या है, हम न तो कोई विधायकों के लिये कोई मकान बनवा रहे है ओर न ही उनको कार मुफ्त में दे रहे है। यह तो कर्ज की सहूलियत है। कर्जे की सहुलियत तो सरकारी कर्मचारियों को भी मिली हुई है। जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिली हुई है उसी तरह से एम0एल0एज0 को मिल रही है और यह इनका भी ब्याज देगें दूसरी बात मैं स्वामी जी को यह कहना चाहता हूं , लगता है उनको एक बहम सा हो गया हे जो सहूलियतें पार्लियामेंटरी मैंबर और विधान सभा के विधायकों को दूसरे दे ाों में मिलती है। उनके मुकाबले में हिन्दुस्तान में कम है। अमरीका में क्या सहूलियतें है , इग्लैंड में क्या सहूलियते है, यदि उन सहूलियतों का मुकाबला हम भारत के पार्लियामैंटरी मैंबर और विधान सभा के विधायकों की सहूलियतों से करें तो भारत में उनके मुकाबले में बहुत कम सहूलियतें उपलब्ध है। अगर विधायकों को ज्यादा सुविधायें मिलेगी तो वे जनता का ज्यादा काम कर सकेगें। इसीलिये यह बिल पे ा किया गया है। मैं समझता हूं कि इस पर कोइ खास नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिये। इसके बाद एक बात चौधरी बीरेन्द्र सिंह जल ने यह कही कि सब क्लाज 5 में कोई कसर हैं वह मैंने देखी है। जिस तरह से सरकारी कर्मचारी पलाट के लिये कर्जा ले सकता है वही बात यहां पर लगती हैं। जहां तक इस लोन को वापिस करने का सम्बन्ध है, अगर कोई आदमी पहली कि त देने के बाद आगे किस्त देना बंद कर देता है तो उससे यह पैसा बतौर मालगुजारी वसूल किया जा सकता हैं इसके अलावा इस अमैंडिग बिल में यह भी प्रोवीजन

रखी गई है कि अगर किसी ने कर्ज़ पहले ले रखा है तो उसको दोबारा नहीं दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलीटीज टू मैंबर्ज) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई कलाज विचार करेगा।

क्लाज –2

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज –3

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज –4

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज –5

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज –6

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज –7

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज –1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैंक्टिग फार्मूला बिल का अनैंक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री(श्री मूल चन्द जैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलीटीज टू मैंबर्ज) बिल पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलीटीज टू मैंबर्ज) बिल पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलीटीज टू मैंबर्ज) बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(13.00 बजे) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सेलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमेंट) बिल, 1979

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सेलरीज एंड अलाउंसिंज (अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सेलरीज एंड अलाउंसिंज (अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, इनको पहले ही सरकारी गाड़ी मिली हुई है, इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिये, इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री मूलचन्द जैनः मुझे अफसोस है , मेरे आनरेबल मैंबर एम0ए0 पास है, कम से कम इसको पढ तो लेते। हम इस बिल के द्वारा स्पीकर ओर डिप्टी स्पीकर से सुविधा वापिस ले रहे है। (व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रस्ताव है। मैं पढ कर ही कह रहा हूं, यह कहना कि मैने बिल पढा नही है, इस प्रकार का गलत आरोप नहीं लगाना चाहिये । (वयवधान)

श्री उपाध्यक्षः आपके उपर कोई आरोप नहीं है। (व्यवधान)

श्री मूलचन्द जैनः हम सुविधा देने नहीं जा रहे , बल्कि सुविधा वापिस ले रहे है इसमें लिखा है–

"Provided that the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, who has obtained an advance under the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979, for building a house shall not be entitiled to obtain an advance under this Act."

जो बिल अभी पास किया है इसके तहत स्पीकर ओर डिप्टी स्पीकर ने मकान बनाने के लिये या कार खरीदने, बतौर एम0एल0ए0 बतौर डिप्टी स्पीकर या बतौर स्पीकर कर्जा लिया हो तो उनको इस कानून के तहत यह सहूलियत नहीं मिलेगी। इस चीज को ठीक करने के लिये ही यह बिल लाये है।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सेलरीज एंड अलाउंसिंज (अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज –2

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज –1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैंक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (श्री मूलचन्द जैन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सेलरीज एंड अलाउंसिंज (अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सेलरीज एंड अलाउंसिंज (अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सेलरीज एंड अलाउंसिंज (अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्किटस (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1979

कृशि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब एग्रीकल्यरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब एग्रीकल्यरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): स्पीकर साहब, इस बिल में दो बातें रखी गई है। जनता पार्टी के भाासन को बने हुये तकरीबन दो साल हो गये है। जनता पार्टी के नेताओं ने जनता से वायदा किया था कि नीचे के स्तर पर जितने भी डैमोक्रेटिक इन्सटीच्यु ान है, उन में चुनाव का सिस्टम बहाल करेंगें और किसी भी इन्सटीच्यु ान की म्याद नहीं बढाई जायेगी, लेकिन इन दो सालों में दूसरी या तीसरी बार, डैमोक्रेटिक इन्सटीच्यु ान की म्याद बढ़ाने के लिये यह बिल आया है। इस में 6 महीने की म्याद बढाई जा रही है ओर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मेरे साथी जल्दी से इसके इलैक ान करवाने वाले नहीं है ओर यही सोचते होगें कि म्यादा बढाने वाले इस अमैंडिग बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाया जाये। अगर सरकार की नीयत में फर्क ही है तो क्यों नहीं इसकी म्यादा 1982 तक बढा दी जाये, बार–2 अमैंडमैंट लाने की क्या आव यकता है?

दूसरी बात मै यह कहना चाहूंगा, जैसा कि कल कृशि मंत्री ने सदन में एलान किया था कि सरकार ने कृशकों की फसल का बीमा करने का प्रोग्राम बनाया है.....

श्री अध्यक्ष: इसका बिल से क्या सम्बन्ध है?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः बहुत सम्बन्ध है। स्पीकर साहब, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड किसानों से फीस के तौर पर तकरीबन 15 करोड रूपया सालाना इक्टठा करता है और यह सारे का सारा रूपया दो मदों पर खर्च किया जाता है – एक सडकें बनाने पर और दूसरी मार्केट कमेटियां बनाने पर। अध्यक्ष महोदय, मार्केट कमेटियों की जिन्दगी तब तक रहेगी, तब खु ाहाल नजर आ सकती है जब किसान के खेत की फसल अच्छी हो और अगर वह फसल बरबाद हो जाती है तो मार्किट कमेटियों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। न कोई बेचने वाला आयेगा, न कोई खरीदने वाला आयेगा और न ही मार्केट कमेटियों को कोई आमदनी होगी। अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी संस्था, जिसको वर्ल्ड बैंक से 200 करोड रूपये का लोन मिला हो, किसान की भलाई के लिये वर्ल्ड बैंक की सुविधा उपलब्ध हो और इसके साथ ही 15 करोड रूपयेकी इसकी अपनी आमदनी हो, उसका केवल यही कार्य नहीं होनाचाहिये कि मार्केट कमेटी का अच्छे से अच्छा दफतर बना दिया या पक्की सडकें बना दी, बल्कि उनका फर्ज बन जाता है कि जिस किसान से वे पैसा कमाती है, उसकी बहबूदी के लिये कुछ काम करें। कृशि मंत्री महोदय ने जो बीमा की बात कही, इस पर मैं एक सुझाव दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इसपर विचार करेगें। फसल बीमा की स्कीम की जिम्मेवारी मार्केट बोर्ड पर डाली जाये और बीमें की वसूली मार्केट कमेटियां किया करें.....

.....

Mr. Speaker: I would request th hon. Member to restrict himself to the provisions of the Bill. बिल के उपर बात होनी चाहिये। मार्किट कमेटियों पर जनरल डिसक ान करना ठीक नहीं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अच्छा जी,। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कह रहा था कि इस बिल में यह प्रोवीजन किया गया है कि मार्किट कमेटी के मैंबरों में प्रोडयूसर्ज की संख्या बढाई जायेगी। ये मेंबर किसानों के हित के लिये, किसानों की रक्षा के लिये बढाये जाते है लेकिन असल में ये किसान के हितों की रक्षा नहीं कमर पाते। ये माकेट कमेटियों की फीस बढाकर किसानों के पैसे को गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे है, सिवाये अच्छे अच्छे दफतर बनने के, स्टाफ को तनखाह देने के और कुछ नहीं करते। 200 करोड रूपया जो वर्ल्ड बैंक से मिला हे, एक बहुत बड़ी रकम होती है। यह रकम हरियाणा के टोटल बजट का 1/3 हिस्से के बराबर है। इस रूपये से वे स्कीमें बनाई जा रही है जो बडी ट्रेडी ानल और स्टिरिओटाइप्ड है। इस पैसे को इस्तेमाल छोटे–2 किसानों की भलाई के लिये , मजदूरों की भलाई के लिये किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि प्रोडयूसर्ज ग्रुप में से, जो लाइसैंसी है, उस ग्रुप में से वाईस चेयरमैन बनाया जाएगा। यह बात दुरूस्त है, हर जगह ऐसा होता आयाहै कि वाईस चेयरमेन उसी मार्केट कमेटी से सम्बन्धित

होना चाहिये ताकि उसकी भलाई कर सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय, देखने वाली बात यह है कि प्रोडयूसर्ज की लिस्ट में एक ऐसी डिवेल्पिंग क्लास है जिसे ि ाडयूल्ड कास्ट, भाडयूल्ड ट्राइबज ओर बैकवर्ड क्कलास कहते है और ये मार्केटिग प्रौसैसिंग सोसायटीज से आते है। क्या इन में से भी वाईस चेयरमैन बनेगा, क्या इस लिस्ट में इनके नाम है? मैं समझता हूं कि इन्ही लोगों में से वाईस चेयरमैन चुनना चाहिये। क्या इन तीनों क्लासिज के आदमी इस लिस्ट में भाामिल है, इसके बारे में मंत्री महोदय से क्लैरिफिके ान लेना चाहूंगा।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान(गुड़गांव): अध्यक्ष महोदय, मैं बिल के समर्थन में खडा हूआ हूं। मेरे माननयी सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कुछ बातें कहीं जो बिल्कुल गलत और निराधार हैं वर्ल्ड बैंक से 200 करोड रूपये की रकम मार्केट बोर्ड को नहीं मिली है। (व्यवधान) केवल साढे 23 करोड रूपया मन्जूर हुआ है 200 करोड वाली बात बिल्कुल गलत है।

Chaudhri Birender Singh: I want to clarify. I have never said that they have got a loan of Rs. 200 crores. What I had said was that there are schemes for which they are trying to get loan upto the maximum limit of Rs. 200 crores.

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान: स्पीकर साहब, यह अमैंडिग बिल है। इसमें हम कुछेक अच्छी बातें करने जा रहे है। चुनाव के बारे में जो कहा गया, उसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं

कि अभी अभी पंचायत के इलैक ान हुये है। उसके बाद हमने एक एक्ट एंड रूल्ज रिव्यू कमेटी मुकर्रर की थी और उसकी मीटिंग्ज हुई। उसकी रिकमैन्डे ान्ज गवर्नमेंट के पास आई हैं अब चूंकि इसकी नोटिफिके ान करने के लिये समय की जरूरत होती है इसलिये यह समय मांगा गया है। गवर्नमेंट की अपनी तरफ से डिले करने की कोई नीयत नहीं थी ओर न है। इसके अलावा, स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि पहले जो चुनाव होता था उसको खत्म करके कांग्रेस सरकार ने नोकिने ान का सिलसिला भुरू कर दिया था। दुबारा गाड़ी को लाईन पर लाने के लिये समय लगता हैं फिर स्पीकर साहब, हमने इस अमैंडिग बिल में यह प्रोविजन भी किया है कि बैकवर्ड क्लास और भाडयूल्ड कास्टस के लोग यदि इलैक्ट होकर न आ सकें तो उनको कोआप्ट किया जाये। पहले यह प्रोविजन बिलकुल नहीं था।

स्पीकर साहब, जहां तक फडंज की बात है, इसके बारे में मै हाउस को बताना चाहता हूं कि इससे काफी डिवैल्पमेंट के काम होने जा रहे है। मैं माननयी सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति यह थी कि पहले मार्किट कमेटीज का 55 परसैंट रूपया सरकार के पास चला जाता है लेकिन अब उससे ज्यादा अमांउट नि चत किया जाएगा मार्किट कमेटीज के लिये और जो इलैक्टिड बौडी होगी वही इस पैसे को खर्च किया करेगी। मैं इन भाब्दों के साथ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने समय दिया। मैं इस बिल के समर्थन में खडा हुआ हूं। इसमें कोई भाक नहीं कि सरकार मिनिस्टर साहब और चेयरमैन साहब लोगों की बहुत सेवा करने मे लगे हुये है लेकिन इस बिल में थोडा सा सुधार करने की जरूरत है। मंडियों में लोग अपने बैंलों को जोड कर अनाज लेकर आते हैं लेकिन उन बैलों के लिये पानी पीने की मंडियों मे कोई व्यवस्था नहीं हैं एक तो यह होनी चाहिये। इसके अलावा, मंडियों मे जो पल्लेदार होते है , जो बोरियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते है, वे बहुत गरीब आदमी हैं उनको बारि । और गर्मी आदि में बडी तकलीफ उठानी पडती हैं दुकानदार आदि उनको अपनी दुकानों में घुसने नही देते। उनके लिये भी मंडियों में कोई व्यवसथा होनी चाहिये। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय एकअर्ज मेरी और है। कुछ इलाके हमारे ऐसे है जहां पी0डब्ल्यू0डी0 वाले सडक नही ंबना सकते। वे इलाके फिरनी के अन्दर पडते है। अगर उन्होने स्कूल या हस्पताल आदि तक जाना हो तो उनहे बडी दिक्कत होती है। इसलिये यह मंडियों का पैसा ऐसी सडको ंपर लगना चाहिये।

लाला बलवन्त राय तायल (हिसार): स्पीकर साहब, मुझे इस बिल की क्लाज 3 की सब क्लाज 1 पर एतराज हैं इसमें प्राविजन किया गयाहै कि कमेटी का चेयरमैन प्रोडयूसर और वाइस चेयरमेन बिजनैसमैन होगा। स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने इस

एक्ट में तरमीम करके जो इस बौडी को एक नौमीनेटिड बौडी बना दिया था, उस चीज को दूर करने के लिये जो कदम उठाये गये है वे तो ठीक है लेकिन यह जो नई बात ला रहे है कि प्रोडयूसर चेयरमैन होगा और व्यापारी वाईस चेयरमैन होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इसमें 19 मैंबर होगें। किसी भी मैंबर को अध्यक्ष बनने का राईट है और किसी भी मैंबर को वाइस चेयरमैन बनने का राईट हैं मंत्री महोदय पता नहीं इस बात को कहां स`ले आए है। डैमोक्रेसी में तो एक वोटर को यह अधिकार है कि वह कहीं से भी खडा होकर किसी पोस्ट के लिये इलैक ान लड सकता हैं। इसलिये मैं इस क्लाज को डैमोक्रेटिक क्लाज नहीं समझता। (विघन) भाायद हाईकोट्र मे भी यह क्लाज ठहर न सके। इसलिये मैं कहूंगा कि इस बात को हटाया जाए, बाकी मुझे इस बिल के बारे में कोई ऐतराज नहीं है।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर महोदय, यह जो तरमीमी बिल हाउस के सामने मंत्री महोदय ने पे ा किया है इसमें कुछ अच्छी क्लाजिज है जैसे औफि ियल्ज के बारे मे ंपाबन्दी लगी है कि पब्लिक के जो नुमांयदे हो वे चेयरमेन हो। तादाद भी कुछ बढाई गई हैं तादाद थोडी हो या ज्यादा हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहतालेकिन एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूं। आज देहात में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में इतनी पार्टीबाजी पैदा हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसका मुंख्य कारण रोज के चुनाव हैं। कभी कोआप्रेटिव सोसाइटीज के,

कभी मार्किटिंग कमेटी के, कभी जिला परिशद के और कभी ब्लौक समिति के चुनाव होते रहते है। वैसे यह प्रजातंत्र के सिद्धांत के मुताबिक तो ठीक है लेकिन प्रजातंत्र का सिद्धांत उस हद तक ठीक है जिस हद तक यह देहात की प्रजा को दुख न पहुंचाये। मेरी एक प्रार्थना है कि ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे सभी चुनाव एक साथ हो सकें।

दूसरी बात स्पीकर साहब यह है कि जहां मैंबर्ज की स्ट्रैंग्थ बढ रही है वहां इस कमेटी की पावर्ज भी बढ़नी चाहिये। ठाकरान साहब ने बोलते हुये फरमाया कि 55 परसैंट रूपया जो बोर्ड को मिलता है, उसमें से कुछ रूपया मार्किटिंग कमेटीज को दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, पहले मार्किटिंग कमेटीज का कुछ प्रति ात रूपया मार्किटिंग बोर्ड को आता था। उसमें से कंसौलिडेटिड फंड में नहीं जाता था। पिछली सरकार ने अपना पूरा कंट्रोल करने के लिये मार्किटिंग बोर्ड में और फिर कंसौलिडेटिड फंड में पैसा लेकर अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करना भुरू किया। इस बजट में भी 9 करोड़ रा ि ा ऐसी है जो मार्किटिंग कमेटीज से वसूल होगी ओर कसौंलिडेटिड फंड में जायेगी। इस तरह के काम करने का सरकार को हक नहीं है। (विधन) एक तरफ तो मार्किटिंग कमेटीज के मैंबर्ज की स्ट्रैंग्थ बढा रहे है लेकिन ूदसरी तरफ उनको यह अधिकार नहीं होगा कि जो रूपया उनके एरिया में वसूल होता है उसे वे खर्च कर सकें। (विधन) मेरा सुझाव यह है कि जो रूपया जिस एरिया में वसूल

होता है, उसे उस एरिया की मार्किटिंग कमेटी को खर्च करने का अधिकार होनाचाहिये। पहले मार्किटिंग कमेटी अपने हल्के में कही सडकें बनाती थी, कहीं पुलियां बनाती थी, कहीं रास्ते ठीक करने का काम करती थी लेकिन अब वे सब काम होने बंद हो गये है।

स्पीकर साहब, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। चुनाव का जहां तक सम्बन्ध है, इसकी ओर मंत्री महोदय वि ोश ध्यान दें। चुनाव में कई बार गरीब आदमी भी खडे होते है लेकिन उनका क्या हाल होता है, उसका एक उदाहरण मैं हाउस के सामने रख देता हूं पंचायत के एक इलैक ान में पंच के लिये एक उम्मीदवार थे। उनकी अपनी राय भी थी मगर जिस वक्त राय की गणना हुई तो उसमें एक भी राय उसके हम में नही पाई गई उसके यार दोस्तों ने जब उससे पूछाकि आपकी अपनी राय भी कहां गई., तो उसने कहा कि वह तो मैंने पहले ही बेच दी थी ओर प्राप्त हुआ पैसा चुनाव में लगाया है। इस तरह की माल प्रैक्टिसिज पंचायत के इलैक ान में होती है और पार्टीबाजी भी इन चुनावों की वजह से फैलती जा रही हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देकर एक ऐसी प्रणाली प्रस्तावित करे जिससे पार्टीबाजी भी कम हो और चुनाव भी ठीक ढंग से हो।

श्री अध्यक्षः टाईम बहुत कम है। मंत्री जी ने भी जवाब देना है । अगर हाउस एक्सटेन्ड करना चाहते है तो मुझे कोई आपति नहीं ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): स्पीकर साहब मैं इस बिल की पुरजोर ताइद करता हूं लेकिन जो आपने इलैक ान की अवधि बढाई है यह ज्यादा है यह तीन महीने होनी चाहिये थी। मैंबर्ज की जो तादाद बढाई है यह भी थोडी है, ज्यादा होनी चाहिये थी। देहात के लोगों की भर्ती कम हैं मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि मंडियों में लूट हो रही हैं मार्किट कमेटियां सर छोटूराम जी ने बनाई थी ताकि किसानों के साथ लूट न हो।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): स्पीकर साहब जो अमैंडमेंट बिल हाउस के सामने आया है मैं इसके बारे में अर्ज करूंगा कि यह कांस्टिच्यू ानीली बिल्कुल गलत है। अगर सरकार इसको पास करनो की कोि ा ा करेगी तो यह कोर्ट में चैंलेजं हो जायेगा। 90 एम0एल0ए0 हरियाणा विधान सभा के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकते है, कोई रूकावट नहीं है। जहां रिजर्वे ान है वहां तो नहीं लड सकते लेकिन दूसरी जगह से लड सकते हैं। इसलिये मैं लीडर आफ दी हाउस से निवेदन करूंगा कि हर आदमी को इलैक ान लडने का अधिकार है। यह बिल्कुल गलत है कि चेयरमैन प्रोडयूसर ही बन सकता है। इलैक ानमें कोई भी खडा हो सकता है, जिसको वोट ज्यादा मिले वही चेयरमैन बन सकता है। इसलिये मेरी मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि इस अमैंडमेंट को वापिस लिया जाये और पास न किया जाये। (विघन)

श्री अध्यक्षः अगर आप हाउस का टाईम एक्सटेंड करना चाहते है तो मुझे कोई आपति नहीं है चाहे आप एक घंटा करें या दो घंटा करें।

आवाजें: कोई जरूरत नहीं है।

Mr. Speaker: Now I will request the Hon. Minister to give a reply.

कृशि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह): स्पीकर साहब मेरे साथियों ने एक दो प्वांयट उठाये है। वैसे तो मेरे भाई श्री प्रताप सिंह ठाकरान ने जवाब दे दिया है। कई प्वांयटस का जवाब उनकी तरफ से आ गया है। एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, जैसा कि चौधरी लाल सिंह ने कहा है कि मंडियों में पानी का प्रबन्ध नहीं है। उनका अच्छा सुझाव है, प ुओं के लिये पानी का प्रबन्ध होना जरूरी है। दूसरा सुझाव चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने दिया है, वह भी बहुत अच्छा है। उनहोने कहा कि ये मार्किट कमेटियां खास काम के लिये है, किसानों के , प्रोडयूसर्ज की भलाई के लिये अच्छे कदम उठाने हेतू बनाई गई है लेकिन वह हो नहीं रहा है। इनका ज्यादा रूपया सड़कों पर खर्च हुआ है जबकि ज्यादा रूपया मंडियों परखर्च होना चाहिये। और चीजें जो मेरे अपने दिमाग में भी है उनके बारे में कदम उठायें जायेगें। अगर कोई किसान माडल फार्म बनायेगा तो उसको भी मार्किट कमेटी से जो कुछ जानकारी दी जा सकेगी, दी जायेगी। इन बातों पर हम गौर कर रहे है।

चौधरी रिजक राम जी ने जो बताया है, उनकी बात से भी मैं सहमत हूं पिछले सालों में वहां गडबड थी। मैं उनसे इस बात के बारे में अलग से डिस्क ान पर लूंगा। हम कोि ा ा करेगें कि जो इलैक ान हो वे भी साथ ही हो ताकि बोझा कम हो। जो हमने छः महीने का टाईम मांगा है, इसमें कई चीजें करनी पडेगी लेकिन मैं आपको वि वास दिलाता हूं कि तीन महीने में हम इस काम को कर देगें।

आखिरी चीज हमारे तायल साहब ने और श्री मांगे राम गुप्ता ने फरमायी थी। यह फैसला सैंन्टर की बडी हाई पावर्ड कमेटी ने किया था जिसमें बहुत सारी स्टेटस के रिप्रेजन्टेटिवज आये थे। उनहोने तो फैसला यहां तक किया था कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन प्रोडयूसर्ज के होने चाहिये। बहुत सारी स्टेटस ने ते चेयरमैन और वाइस चैयरमैन प्रोडयूसर्ज के लगाये हैं। हमने तो जान–बूझ कर यह प्रोविजन किया है कि लाइसेंसी भी होने चाहिये। सारी चीजें बडी फायदे की है। इससे जो चोरी और गबन होता था, वह भी रूकेगा। हरिजनों की रिजर्वे न के बारे में चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान ने बता दिया है। यह बहुत अच्छी अमैंडमेंट आई है। इससे बडा फायदा होगा। इसलिये इस अमैंडमेंट को पास कर दिया जावे।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि –

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज–2

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

चौधरी रिजक रामः स्पीकर सहब बाकी सारी क्लाजों को इकट्ठा पुट कर दें।

श्री अध्यक्षः यदि हाउस सहमत हो तो ऐसा हो सकता है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब सभी क्लाजों को अलग अलग पुट करें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्षः अगर एक मैंबर भी यह कहता है कि अलग–2 पुट की जाये ंतो अलग अलग की प ुट होगी।

क्लाज–3

श्री अध्यक्षः प्र ान है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज–4

श्री मांगें राम गुप्ताः स्पीकर साहब मै इस क्लाज पर बोलना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Before you speak, do I have the sense of the House to extend the sitting?

(**Voices:** No,no.)

Mr. Speaker: In that case, I would request the hon. Member to by very brief.

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): स्पीकर साहब जो अमैंडमेंट प्रोसैसिंग के बारे में गवर्नमैंट की तरफ से आई है, यह गलत है। गवर्नमैंट अगर यह समझती है कि फैक्टरी वालों पर एग्रीकल्चर गुडस पर मार्किट फीस नहीं होती है, ऐसी बात नहीं हैं उन पर मार्किट फीस है अब तोजिस माल को प्रौसैस कर दिया जायेगा उस पर भी मार्किट फीस लगा दी गई है। इस अमैंडमेंट के करने से मंहगाई भी बढेगी ओर चोरी भी बढेगी।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज–5

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज–1

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैंक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

स्वामी आदित्यवे ाः स्पीकर साहब मै ंटाइटल पर बोलना चाहता हूं।

Mr. Speaker: The I would request the House to agree to extend the time of the sitting by 15 minutes.

Cooperation and Dairy Development Minister (Chaudhri Bhajan Lal): It may be extended by five minutes.

Mr. Speaker: Five minutes will not do. क्योंकि जो भी सदस्य बोलना चाहता है मुझे उसको बोलने के लिये पूरा टाईम देना हैं इसलिये हाउस 10 मिनट के लिये एक्सटैंड किया जाता है।

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 1979 (पुनरारम्भ)

टाइटल

स्वामी आदित्यवे I: मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, वैसे तो अब बोलने का कोई मौका नहीं है। अगर आप बोलना चाहते है तो थर्ड रीडिंग के वक्त बोल लें।

प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृशि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह): प्रस्ताव पे ा करने से पहले मैने हाउस को जो यह बताया है कि एक हाई पावर्ड कमेटी थी, उसके बारे में मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि वह हाई पावर्ड कमेटी नहीं था बल्कि वह नै ानल कमी ान आन एग्रीकल्चर था। इस कमी ान ने यह रिकमेडे न की थी कि प्रोडयूसर ही चेयरमेन और वाइस चेयरमैन होनाचाहिये। हमने तो आउट आफ दी वे जाकर यह कोि ा ा की है ताकि हम दूसरे भाइयों को भी साथ रख सकें। अब मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जायें।

मै ंप्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव हुआ कि–

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाये।

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, इसमें नाम पंजाब का लिखा हुआ है। हरियाणा को बने हुये आज 13 साल के लगभग अर्सा हो गयाहै लेकिन हम रोज देखते है, इसी तरह के बिल आते रहते है जिनमें पंजाब लिखा रहता हैं। इनमें पंजाब की जगह हरियाणा होना चाहिये।

श्री अध्यक्षः यह जो बिल पे ा हुआ है यह हरियाणा अमैंडमैंट बिल है, इसका जो पेरैन्ट एक्ट है, वह पंजाब से लिया गयाहै। जिस वक्त यह कम्पलीट बिल लायेगें उस वक्त ओरीजनल एक्ट को चेंज करने के बाद जो कानून बनेगा उसका नाम हरियाणा से हो सकता है।

प्र न है कि –

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन कल दिनांक 29–3–79 सुबह 9. 30 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(13.33 बजे)

The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 29th March, 1979.)

ANNEXURE (A)

Surplus Land

***1204. Master Jogi Ram:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the area of surplus land secured during the period from 4th July, 1977 to 4th July, 1978 and from 5th July, 1978 to date separately;

(b) the area of the said land as referred to in para (a) above which has been distributed and amongst whom;

(c) whether the persons to whom the said land has been distributed have taken possession thereof; and

(d) the area of land which still remains to be districbuted and amongst whom it is proposed to be distributed?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह)

(क) 4—7—77 से 4—7—78 तक 9069.5 एकड़

5—7—78 से 28—2—79 तक 7197 एकड़

(ख)

अनुसूचित जाति		पिछड़े वर्ग		अन्य	
संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र

776	2842. 5एकड़	307	957 एकड़	874	2539एकड़

(ग) हां। 4276 एकड़ भूमि का 1881 ऐलीजीबल व्यक्तियों द्वारा कब्जा लिया जा चुका है।

(घ) 11268 एकड़।